

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 मार्च, 1985

खण्ड 1, अंक 11

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भाक्रवार, 22 मार्च, 1985

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(11)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(11)50
विभिन्न विशयों का उठाया जाना	(11)52
नेमिंग आफ मैम्बर	(11)57
वाक आउट	(11)58
वक्तव्य— सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा कैनाल वाटर की न्यू रोटे अन पालिसी संबंधी	(11)59
विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)	(11)61
नेम किये गये मैम्बर को सदन से बाहर भेजने की घटना का प्र अन उठाना	(11)62
बिल्ज (इन्ट्रोड्यूस्ट सदन की अनुमति से)	(11)

1. दि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(11)64
2. दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(11)65
3 दि हरियाणा म्यूनिसिपल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(11)66
4 दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1985	(11)67
5 दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985	(11)67
वर्ष 1985–86 के बजट पर सामान्य चर्चा	(11)72
बैठक का समय बढ़ाना	(11)108
वर्ष 1985–86 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(11)109

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 22 मार्च, 1985

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर 1 चण्डीगढ़ मे 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज अब सवाल होंगे।

Uniforms for Constables

***817. Prof. Sampat Singh:** Will the Minister of State for Revenue and Home be pleased to state-

(a) the yearwise total expenditure incurred on the supply of uniforms to the Constables Head Constable, ASIs and SIs of Haryana Police during the period from 1st January, 1982 to-date; and

(b) the rate per meter of the cloth purchased for the winter and summer uniforms, referred to in part (a) above, together with the names and addresses of the firms/agencies from which the said cloth was purchased ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) व (ख): विवरणीय सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) 1982 (जनवरी से दिसम्बर) — 11657750/- रुपये

1983 (जनवरी से दिसम्बर) — 6360313/- रुपये

1984 (जनवरी से दिसम्बर) — 6793845/- रुपये

1985 (जनवरी से दिसम्बर) — 603614/- रुपये

(ख) सर्दी की वर्दी: वांछित सूचना निम्नलिखित है :-

वस्तु का नाम	1982 (जन० से दिस०)		1983 (जन० से दिस०)		1984 (जन० से दिस०)		1985 (जन० से दिस०)	
	दर प्रति मीटर	फर्म का नाम व पता	दर प्रति मीटर	फर्म का नाम व पता	दर प्रति मीटर	फर्म का नाम व पता	दर प्रति मीटर	फर्म का नाम व पता
1 सर्ज वूलन (नीला) (ट्रैफिक पुलिस	79/-रु0	मै० नै अनल वूलन मिलज,						

	हेतु)		चण्डीगढ़					
2	ग्रेट कोट कलाथ (नीला) (द्रैफिक पुलिस हेतु)	64 /-₹0	मै0 नै अनल वूलन मिलज, चण्डीगढ़					
3	ग्रेट कोट कलाथ (खाकी) (आदे अ दिनांक 27-4-82 द्वारा)	64 /-₹0	उक्त प्रति अत कटौती व 15 प्रति अत छूट भात प्रति अत अदायगी पर।	99.85 ₹0 प्रति अत कटौती व 15 प्रति अत छूट भात प्रति अत अदायगी पर।	ए0के0 टैक्सटाईलज कारपोरे अन लुधियाना (ओसीएम मिलज)	94 /- ₹पये		ए0के0 टैक्सटाईलज कारपोरे अन लुधियाना (ओसीएम मिलज)

4	सर्ज गर्म (खाकी)	79 / -₹0	उक्त	88 / - रुप0 7.5 प्रति ात कटौती हाई पावरड कमेटी द्वारा	मै0 पानीपत वूलन मिलज खरड (एनटीसी)				
5	ग्रेट कोट क्लाथ (खाकी) (आदे ा दिनांक 19-7-82 द्वारा)	66 / -₹0	मै0 नै ानल वूलन मिलज, चण्डीगढ						
6	अंगोला क्लाथ	55 / -₹0 (पूरी चौ0)	उक्त	25..50 रु0 (1प्रति ात	मै0 रामा टैक्सटाईल दिल्ली	55 / - रु0 1 प्रति ात	मै0 ओसवाल वूलन मिल		

(खाकी)			छूट व 2.5 प्रति आत एक्साइड डयूटी बढ़ी) (आधी चौ0)	(बिन्नी)	छूट (पूरी चौ0)	लुधियाना		
(ग) गर्मी की वर्दी								
1	झील कोटन (नीला) (ट्रैफिक पुलिस हेतु)	8.88 रु0	मै0 गोयल एण्ड कं0 चण्डीगढ़ (एलगिन मिल)					
2	झील कोटन (सफेद)	8.44 रु0	मै0 गोयल एण्ड कं0 चण्डीगढ़					

	(द्रैफिक पुलिस हेतु)		(एलगिन मिल)					
3	कोटन ड्रील (खाकी)	8.68 रु0	मै0 गोयल एण्ड कं0 चण्डीगढ़ (एलगिन मिल)				11.40	मै0 गोयल कारपोरे अन चण्डीगढ़ (एलगिन मिल)
4	सैलुलर कोटन (खाकी)	6.62 रु0	मै0 एलगिन मिल्ज कानपुर		6.90 रु0	मै0 गोयल कारपोरे अन चण्डीगढ़ (एलगिन मिल)		
5	टेरीकोट क्लाथ (खाकी)	45.00 रु0	मदुरा कोटस नई दिल्ली	47.14 रु0	मै0 रतन क्लाथ हाउस, लुधियाना,	43.90 रु0	मै0 बेनी प्रसाद एण्ड कं0 अमृतसर (जगजीत	

				(मदुरा कोटस)		कोटन टैक्सटाइलज)		
6	टेरीकोट व्लाथ (सफेद) (ट्रैफिक पुलिस हेतु)	44.25 रु0	मै0 बेनी प्रसाद एण्ड कं0 अमृतसर (जगजीत कोटन टैक्सटाइल)					
7	टेरीकोट व्लाथ (नीला) (ट्रैफिक पुलिस हेतु)	44.25रु0	उक्त					

प्रो० सम्पत् सिंहः र्स्पीकर साहब, जब मैंने यह उत्तर पढ़ा तो मैं समझता था कि स्टेट होम मिनिस्टर साहब ही जवाब पढ़ेंगे लेकिन इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं क्योंकि इनका बड़ा अच्छा तजुर्बा है। र्स्पीकर साहब, पुलिस के कांस्टेबलज, हैड कांस्टेबलज, ए०ए०आई०ज० और सब इनस्पैक्टर्ज की वर्दी के लिए कपड़ा खरीदा है और उसके रेट्स दिये हैं सन 1982 में ग्रेट कोट क्लाथ (खाकी) 64 रुपये मीटर के हिसाब से मै० नै अल वूलन मिलज, चण्डीगढ़ से खरीदा है और यही कपड़ा सन 1983 में ए०के० टैक्सटाईलज कार्पॉरे अन लुधियाना (ओ०सी०ए० मिलज) से 99.85 रुपये मीटर के हिसाब से पांच परसैंट कटौती लेकर खरीदा है। इसी तरह से सन 1985 में फिर 94 रुपये मीटर के हिसाब से मै० ए०के० टैक्सटाईलज कार्पॉरे अन, लुधियाना (ओ०सी०ए० मिलज) से खरीदा है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सन 1982 में 64 रुपये के हिसाब से खरीदा और सन 1983 में छूट लेकर 94 रुपये के हिसाब से वही कपड़ा खरीदा यह एक दम से तीस रुपये का रेट पर मीटर के हिसाब से कैसे बढ़ गया ? सन 1984 में कपड़ा खरीदा नहीं फिर सन 1985 में भी उसी कम्पनी से 94 रुपये मीटर के हिसाब से खरीदा। इसी तरह से सन 1982 में सर्ज गर्म खाकी 79 रुपये पर मीटर के हिसाब से खरीदी, 1983 में 88 रुपये मीटर के हिसाब से खरीदी लेकिन उस पर साढ़े सात परसैंट कटौती हाई पावर्ड कमेटी द्वारा करवा ली गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले किसने खरीदा था ?

(विधन) साढे सात परसेंट की कटौती तो हाई पावर्ड कमेटी ने करवा ली क्योंकि उसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं। (विधन)

श्री अध्यक्ष: आपकी सप्लीमेंटरी पूछते हुए तीन मिनट हो गये हैं, आप इसे भार्ट करके पूछिए।

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि जो रेट पहले फिक्स किये थे, उनको फिक्स करने वाले कौन लोग थे। पहले इन्होंने ज्यादा रेट्स क्यों रखे और बाद में कम कैसे करवा लिए ? (विधन)

श्री अध्यक्ष: इसमें लिखा है कि सन 1983 में यह रेट था और बाद में यह रेट था।

प्रो० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, एक ही कपड़े के अलग अलग रेट्स हैं। अंगोला खाकी सन 1982 में 55 रुपये मीटर के हिसार से लिया और सन 1983 में साढे पच्चीस रुपये के हिसाब से खरीदा गया। पहले दुगने रेट से कैसे लिया गया ?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार जो भी परचेज करती है उसके बाकायदा टैंडर इन्वाइट करती है। जिसका टैंडर लोएस्ट होता है उसे आर्डर दिया जाता है। एक तरफ कहते हैं कि 55 रुपये क्यों लिया और बाद में 25.50 रुपये के हिसाब से ले लिया तो कहते हैं कि यह सस्ता कैसे ले लिया। इनको तो खु नी होनी चाहिए कि सस्ते भाव से लिया है। सन 1982 में हाई पावर्ड कमेटी नहीं थी। मई 1983 में हाई पावर्ड कमेटी बनी, उसने

यह कपड़ा खरीदा है। अध्यक्ष महोदय, चित भी इनकी पट भी इनकी। एक तरफ कहते हैं कि ज्यादा से कम भाव पर क्यों खरीदा, दूसरी तरफ कहते हैं कि कम से ज्यादा भाव पर क्यों खरीदा। एक जबान में दो बातें करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मई 1983 से इसकी परचेज के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनी, उसमें फाईनैस सैक्रेटरी, महकमे के मंत्री, डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी, हैड आफ दी डिपार्टमेंट और मैं हूं। ये सारे बैठ कर और बात की तह में जाकर आर्डर प्लेस करते हैं। जिसका आर्डर लोएस्ट होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है। बेसलैस बात कहने से कोई बात नहीं बनती। हाई पावर्ड कमेटी के बनने के बाद करोड़ों रुपये का फायदा हुआ है।

प्रौ० सम्पत्ति सिंह: स्पीकर साहब, ये कह रहे हैं कि 55 रुपये मीटर से 25.50 रुपये मीटर के हिसाब से ले लिया लेकिन 1984 में फिर 25.50 रुपये फिर से 55 रुपये के हिसाब से क्यों लिया ?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, कपड़ा एक तरह का नहीं होता। यह लम्बे अर्ज का हो सकता है। यह देखना होता है कि कपड़ा कितना चौड़ा है। पहले वाले का एक गज अर्ज होगा तो दूसरे का ज्यादा होगा। पहले की चौड़ाई आधी होगी, बाद वाले की चौड़ाई ज्यादा होगी। सन 1982 वाले कपडे की चौड़ाई पूरी है और सन 1983 वाले की आधी है। यह जवाब में दिया हुआ है। इसलिये सन 1982 में 55 रुपये मीटर के हिसाब से लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह कपड़ा हाई पार्टर कमेटी के फैसले के बाद खरीदा गया। उससे पहले जिसने भी खरीदा, उसके लिए टैन्डर या कोटे तन मांगी गई होंगी। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहता हूं कि किस रेट के हिसाब से टैन्डर या कोटे तन किस किस फ्रम से आये हैं ?

चौधरी भजन लाल: जितनी भी परचेज हुई है, सबके टैन्डर मंगाये हैं। एक परचेज में दस से ऊपर टैन्डर आए हैं जो अलग अलग जगहों से हैं।

श्री मंगल सैन: क्या इसमें आदमपुर के लोग भी हैं ?

चौधरी भजन लाल: आदमपुर के किसी भी आदमी ने टैन्डर नहीं दिया और न हिसार के ने दिया है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि टैन्डर देने वाले कहीं के भी हो सकते हैं। आदमपुर के भी हो सकते हैं। जिनके टैन्डर आये हैं मेरे पास इस समय उनके पूरे नाम नहीं हैं। बाद में माननीय सदस्य को पूरी तफसील में जवाब भेज देंगे और उनके नाम भी दे देंगे। (विधन)

Mr. Speaker: He is assuring you that he will send the details.

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, जहां सवाल में रेटस पूछे गये हों वहां ये कोटे तन लेकर न आयें, यह कैसे हो सकता है ? How can we ask supplementaries ? यह हमारा राईट है, अगर हमें पूरी सूचना मिल जाती तो भायद हम गवर्नर्मेंट को

एक्सपोज कर पाते। इसलिए हमारा वह राईट तो खत्म हो गया।

Sir, the question can be deferred till tomorrow.

Sh. Mangal Sein: This question may be deferred till tomorrow, Sir.

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि बाकायदा टैंडर लिये जाते हैं। जिसका लोएस्ट होता है, उसे आर्डर प्लेस करते हैं। (गोर व व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरी रिक्वैस्ट यह है कि चूंकि मुख्य मंत्री महोदय के पास पूरा जवाब नहीं है, इसलिये इस सवाल को मंडे को फिर ले लें। (व्यवधान व भाओर)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। बे तक आप इसे मंडे तक पोस्टपोन कर लीजिये। मैं इनको पूरा जवाब दूँगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक हैं अगला सवाल।

Haryana State Industrial Development Corporation

***824. Smt. Chandravati:** Will the Minister of State for Industries be pleased to state-

(a) the date on which Haryana State Industrial Development Corporation was set up;

(b) the names of the persons who have remained as Chairmen and Managing Directors of the said Corporation since its inception;

(c) the present strength of staff employed togetherwith the method of recruitment thereof and the designation wise names and address of the persons recruited in the said Corporation during the period from 1979-80 to date; and

(d) whether any steps have been taken by the said Corporation for the development of industries in the State; if so, the details thereof ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया):

(क) : 8 मार्च 1967।

(ख) तथा (ग): वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है। (अनुबन्ध 1 तथा 2 पर)

(घ): हाँ। वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है। (अनुबन्ध 3 पर)

अनुबन्ध—1

अध्यक्ष	
श्री	
1	आर०एन० चोपडा, आई०ए०एस०
2	एच०के० सांघी
3	आर०एन० चोपडा, आई०ए०एस०
4	आर०एन० अहुजा, आई०ए०एस०
5	ई वर चन्द्र, आई०ए०एस०
6	एम०एल० बतरा, आई०ए०एस०
7	एस०के० मिश्री, आई०ए०एस०
8	एम०सी० गुप्ता, आई०ए०एस०
9	वी०के० सिबल, आई०ए०एस०
10	एच०वी० गोस्वामी, आई०ए०एस०
11	वी०के०बिसल, आई०ए०एस०
12	फतेह चन्द विज, एम०एल०ए०

13	वी०के० सिबल, आई०ए०ए०स०
14	वी०ए०स० ओङ्गा, आई०ए०ए०स०
प्रबन्धक निदे तक	
1	पी०ए०न० साहनी, आई०ए०ए०स०
2	जे०डी० भार्मा, आई०ए०ए०स०
3	एल०सी० गुप्ता, आई०ए०ए०स०
4	जे०डी० भार्मा, आई०ए०ए०स०
5	त्रिलोचन सिंह, आई०ए०ए०स०
6	एस०जी० सुन्दरम, आई०ए०ए०स०
7	एल०ए०म० जैन, आई०ए०ए०स०
8	जे०डी० गुप्ता, आई०ए०ए०स०
9	एल०ए०म० जैन, आई०ए०ए०स०
10	जे०डी० गुप्ता, आई०ए०ए०स०
11	आर०ए०ल० सुधीर, आई०ए०ए०स०
12	के०के० भार्मा, आई०ए०ए०स०

13	एम०जी० आई०ए०एस०	दे वासहायम्,
14	ए०एन० माथुर, आई०ए०एस०	
15	धनेन्द्र कुमार, आई०ए०एस०	
16	जे०के० दुगल, आई०ए०एस०	
17	पी०आर० कौ० तक, आई०ए०एस०	

अनुबन्ध-2

वर्ष 1979-80 से फरवरी, 1985 के दौरान भती किये गये अमले के पदक्रम, नाम और पत्ते तथा उनके भर्ती के तरीकों के विवरण की सूची।

वर्तमान संख्या 250			भर्ती के तरीके			
क्र0	नाम व पते	नियुक्ति की तिथि	रोजगार कार्यालय के माध्यम से	विज्ञापन द्वारा अनोपलिधि प्रमाण पत्र के विरुद्ध	अन्य स्रोत	टिप्पणी
पद का नाम: वरिश्ठ प्रबन्धक तकनीकी						
1	श्री आर0 के0 गुप्ता, म0 नं0 163, सैक्टर 16ए, चण्डीगढ़	1-2-1982		हाँ		
2	श्री एन0के0 जैन गांव व पी0ओ0 सिधालुपूर जिला	14-5-1984		हाँ		

	चुरू, राजस्थान					
पद का नाम: प्रबन्ध तकनीकी						
1	श्री डी०के० अग्रवाल, 1117 / 36-सी, चण्डीगढ़	12-12-1979		हाँ	31-8-1982 को सेवा से त्याग	31-8-1982 को सेवा से त्याग
2	श्री आर०पी० जैन, मैसर्ज ज्ञान चन्द, संतोष कुमार, कलाथ मरचैट, राईकोट लुधियाना	12-3-1981		हाँ		
3	श्री ए०पी० चमोली, म० न० 597, सैकटर 8बी चण्डीगढ़	16-11-1981		हाँ		
4	श्री सुनील कुमार गुप्ता, म०न० 3144, सैकटर 37-डी, चण्डीगढ़	1-10-1984		हाँ		

1	श्री सती ठाकुमार, गांव बान्दुपुर, पी0ओ0 एवं डिस्ट्रिक्ट सोनीपत	27-9-1983		हाँ		
2	श्री एम0के0 गुप्ता, ई / 1021, नारायणा विहार, नई दिल्ली।	7-10-1983		हाँ		

पद का नामः सहायक वित्त प्रबन्धक (वित्त)

1	श्री विनोद सेठी	18-1-1980		हाँ	11-2-1980 को सेवा से त्याग
2	श्री नन्द लाल महता, म0नं0 32, ब्लाक नं0-1, गोहाना, सोनीपत	11-2-1983		हाँ	30-4-1980 को सेवा से त्याग
3	श्री मनोहर लाल, गांव व डाकखाना ककरू, जिला अम्बाला	2-12-1981		हाँ	9-9-1983 को सेवा से त्याग

पद का नामः प्र० तक्षण प्रबन्धक

पद का नामः प्रौद्योगिकी विभाग					
संख्या	नाम	जन्म तिथि	उमेर	लिंग	सेवा से त्याग की तिथि
1	मिस रेणु मिनोचा, 251 / एच, माडल टाउन, करनाल	25-5-1982	41	हाँ	9-9-1983 को सेवा से त्याग
2	श्री मनोज सैक्सना, एच०एस० / 20, कैला T नगर, अम्बाला कैन्ट	7-9-1982	41	हाँ	9-9-1983 को सेवा से त्याग
3	श्री आर०एन० खान, अबदुल रहमान, बिल्डिंग धोवीयां गली, अलीगढ (यू०पी०)	29-9-1983	41	हाँ	
4	श्री वी०के० कौर्मि, टैमपल कोठी, नजदीक के०एल० जलान हस्पताल, भिवानी	31-10-1983	41	हाँ	
5	श्री पी०के० गोयल,	7-11-1983	41	हाँ	

	डाकखाना गुरया, जिला मिर्जापुर (यू०पी०)					
--	---	--	--	--	--	--

पद का नाम: लेखा कार्यकारी

1	श्री लाजपत राय गुप्ता	31-7-1981		हाँ		1-1-1983 को हरटोन को स्थानान्तरण
2	श्री के०एस० मलहोत्रा, 69 टाईप-4, थरमल कालोनी, पानीपत	17-12-1982		हाँ		30-6-84 को सेवा से त्याग

पद का नाम: वरि ठ प्रबन्ध (सिविल

	श्री					
1	ओ०पी० गिरोतरा, 3 / 700, महम, रोहतक	25-10-1982		हाँ		

पद का नाम: सहायक महा प्रबन्धक

1	एन०एस० बरार, 7, बैक कालोनी, पटियाला	31-12-1981		हां		
2	मन्जूल सागर, 216, वैस्ट मारदपाली, सिकन्दराबाद (ए०पी०)	8-1-1982		हां		

पद का नाम: उप महा प्रबन्धक

1	वीनू नालर, नं० 14, ज्वायस कम्पाउंड सारलाधोत, पोस्ट मनीपाल, करनाटका	19-2-1981		हां		
---	---	-----------	--	-----	--	--

पद का नाम: महा प्रबन्धक

1	के०के० कथूरिया, नं० 114, गरेटर कैला T-1, न्यू देहली-48	12-1-1984		हां		
---	--	-----------	--	-----	--	--

पद का नाम: वरिश्ठ प्रबन्धक वित्त

1	पी०के० सिंधल, 4197, हिल रोड, अम्बाला कैन्ट	31-8-1982		हाँ		
---	---	-----------	--	-----	--	--

पद का नाम: प्रबन्धक (सिविल)

1	जरनैल सिंह, क्वार्टर नं० 66बी, रेलवे कालोनी, नजदीक लोको स्टेंड, जालंधर सिटी	4-12-1981		हाँ		
2	परमजीत सिंह, गांव एंवं डा० बादलों गांवा अजनुहा, होरी आयरपुर	4-1-1982		हाँ		16-12-1982 को सेवा से त्याग
3	भगमल, गांव व डा० फुल, तहसील फतेहाबाद, हिसार	24-6-1982		हाँ		

पद का नाम: डिजाइन अभियन्ता

1	प्रदीप कुमार	10-1-1980		हाँ		1-1-1983 को हरद्रोन को
---	--------------	-----------	--	-----	--	---------------------------

						स्थानान्नातरित
पद का नामः सहायक अभियन्ता						
1	सत्य नारायण गुप्ता	11-8-1980			बतौर प्र० आक्षणार्थी	
पद का नामः उप अभियन्ता						
1	एस०के० कौ० आक	18-9-1981		हां	"	
2	डी०के० बतरा	22-9-1981		हां	"	
3	जगपाल सिंह	14-10-1981		हां	"	
पद का नामः सहायक प्रबन्धक (सिविल)						
1	ई वर सिंह, गांव व डा० नारा, जिला करनाल	6-9-1979		हां		5-5-80 को सेवा से त्याग
2	धर्मवीर राघव, म०नं० 119, मौहल्ला 8, बीसवां, जिला	9-10-1979		हां		

	गुड़गांव					
3	बी०वी० सूद, ब्लाक नं० 5, त्र क्वा० नं० 78, सेंट्रल गवर्नर्मेंट क्वार्टर, कलकत्ता	9-10-1979		हाँ		3-3-80 को सेवा से त्याग
4	दविन्द वर्मा, 510 / 3, साखापुर बारा, चैनगंग, लखनऊ	9-2-1982		हाँ		
5	अजेय पाठक, म०न० 959, सैक्टर 10, पंचकूला	9-2-1982		हाँ		
6	भवान सिंह राणा, गांव दिआन, डा० मण्डली, जिला पूणा	2-3-1982		हाँ		
7	ओम प्रकाश गोयल, गांव व डा० कलायत, जिला जीन्द	15-10-1982		हाँ		

8	पी०के० गर्ग, छछरोली, जिला अम्बाला	8-10-1982		हां		
9	सतपाल महता, गांव व डा० रानिया, जिला सिरसा	27-7-1983		हां		
10	क रमीर सिंह, गांव साफरा पो० पलखेरी जिला अम्बाला	18-8-1983	हां			19-10-83 को सेवा से त्याग
11	मोहिन्द्र सिंह, गांव व डा० सुलखा, जिला मोहिन्द्रगढ	29-5-1984	हां			
12	रो ठन लाल, गावं व डा० मनोहरपुर, जिला जीन्द	15-1-1985	हां			
13	अ ठोक कुमार, अ ठोक नगर, गन्नौर, जिला सोनीपत	16-2-1981	हां			जून 1982 को स्वर्गवास
14	बृज बिहारी मित्तल, मं०नं० टी / 66 / यू०एम०ई०एस०,	13-2-1981	हां			

	सिरसा					
15	विनोद कुमार अहुजा, मोन्ह ० बी-११-१४, पारा, मुहल्ला जिला रोहतक	३-३-१९८१	हां			६-३-८१ को सेवा से त्याग
16	अ पोक कुमार, म०न्ह ० ४०९, वाड न० ७, पानीपत जिला करनाल	२१-१-१९८५	हां			
पद का नाम: आ युलिपिक						
1	सुद नि कुमार, गानूल मण्डल, सोनीपत	९-९-१९७९	हां			१६-७-८० को सेवा से त्याग
2	आनन्द कुमार खातरी, देहली	२८-९-१९७९			हां	हां, हरद्रोन को स्थानान्तरित
3	आद बावेजा, म०न्ह ० ९६५ / ३, पानीपत जिला करनाल	१५-२-१९८०		हां		१८-१२-१९८० को सेवा से त्याग

4	बचना राम सारोहिया, कोठी नं० 1552, सैकटर 18, चण्डीगढ़	15-2-1980		हाँ		22-5-80 को सेवा से त्याग
5	अनिल मंगला, म०नं० 3369, सैकटर 23बी, चण्डीगढ़	19-2-1980		हाँ		16-6-82 को सेवा से त्याग
6	कृश्ण लाल, म०नं० 1526 / 7, सैकटर 30, चण्डीगढ़	12-3-1980		हाँ		12-6-81 को सेवा से त्याग
7	मिस रेनुका, 113 / आर माडल टाउन, सोनीपत	10-6-1980	हाँ			20-1-1982 को सेवा से त्याग
8	मिस रेणु, म०नं० 3117, सैकटर 23डी, चण्डीगढ़	2-3-1981			हाँ	7-9-83 को सेवा से त्याग
9	असलीधारण के० काउंगल, पो० थीचल, जिला त्रिचुर (केरला)	9-3-1981			हाँ	19-2-1982 को सेवा से त्याग

10	सुमेर सिंह, गांव जोगली, डॉ नारा, जिला करनाल	11-3-1981		हाँ		हरद्रोन को स्थानान्तरण
11	मिस नीरु बाला	15-5-1981		हाँ		5-11-1981 को सेवा से त्याग
12	मिस सुनीता रानी, टी० 74सी, रेलवे कालोनी, पानीपत जिला करनाल	6-4-1981	हाँ			
13	बलबीर सिंह, जनता स्ट्रीट सुभाश रोड, रेलवे स्टेन के सामने, जिला अमृतसर	30-7-1981		हाँ		
14	मिस निर्मल अरोडा, प्लाट नं० 71, नजदीक आर्य स्कूल, हिसार	10-8-1981		हाँ		4-9-81 को सेवा से त्याग
15	मिस प्रवीन लता, गांव व डॉ ललहेड़ी, जिला ऊना	7-10-1981		हाँ		

	(हिमाचल प्रदे ट)					
16	सुन्दर लाल बजाज, म0नं0 34 / 2, तारा नगर, सोनीपत	15-10-1981		हाँ		28-9-1982 को सेवा से त्याग
17	मिस सुमन भार्मा, म0नं0 103, सैकटर 8ए, चण्डीगढ़	16-10-1981		हाँ		11-5-1982 को सेवा से त्याग
18	श्रीमती फिल शे विक्रम, म0नं0 1228, सैकटर 19बी, चण्डीगढ़	16-10-1981		हाँ		
19	जोगिन्द्र पाल अरोड़ा, म0नं0 144 / 5, मौहल्ला रंगरान, जिला जीन्द	20-8-1982		हाँ		2-5-83 को सेवा से त्याग
20	योग राज भार्मा, गांव व डा० तिलपट, जिला फरीदाबाद	19-8-1982		हाँ		18-1-83 को सेवा से त्याग

21	महावीर प्रसाद, गांव वडा० चिकनवास, जिला हिसार	23-8-1982		हाँ		
22	अनिल सचदेवा	24-8-1982		हाँ		हरद्रोन को स्थानान्तरित
23	जोगिन्द्र पाल परुथी, मोहल्ला रंगरान सफीदों, जिला जीन्द	24-8-1982		हाँ		
24	ओम प्रकाश, यमुनानगर, अम्बाला	14-9-1982		हाँ		24-1-84 को सेवा से त्याग
25	प्रेम प्रकाश, गांव वडा० पिल्लूखोड़ा मण्डी, जिला जीन्द	14-5-1982	हाँ			
26	चमन लाल, गांव करकड़ माजरा, जिला अम्बाला	2-12-1982	हाँ			

27	निर्भय कुमार, म0नं0 324, 4 मरला माडल टाउन, गुडगांवा	24-2-1983		हाँ		16-6-83 को सेवा से त्याग
28	आर0एस0 विरदी, राजौरी गार्डन के पास, जनता कालोनी, नई दिल्ली	24-2-1983		हाँ		
29	मिस द नि भार्मा, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़	24-2-1983		हाँ		
30	सत्यपाल, गांव व डाकघर पलथा, जिला करनाल	5-8-1983	हाँ			
31	सतपाल, गावं व डा० फरल, जिला कुरुक्षेत्र	10-8-1983	हाँ			12-9-84 को सेवा से त्याग
32	कुलदीप सिंह, म0नं0 5 / एस0डब्ल्यू, ओलन्ड कालोनी, पी०ओ० भाखडा डैम, जिला बिलासपुर	6-84	हाँ			

33	मिस जनक दुलारी, म०नं० 547 / 6, रूपाली बाजार पानीपत, जिला करनाल	10-2-84		हाँ		
34	किरत सिंह, गांव मुतकण्डा, जिला पौढी गढवाल	15-2-1984		हाँ		
35	मिस कमला देवी, गांव व डा० थाना कलां, जिला सोनीपत	7-3-1984	हाँ			
36	मिस सुदे । देवी, गां० व डा० सोहरमालपुर जिला करनाल	12-3-1984	हाँ			
37	आर०एन० रोहिला, गांव हसनपुर, जिला जीन्द	1-6-84	हाँ			12-11-84 को सेवा से त्याग
38	मिस नीलम सचदेवा, 949, प्रेम नगर, अम्बाला	1-8-1984	हाँ			

39	नन्हा राम भार्मा, गांव डांरा राजपुर, जिला सोनीपत	3-8-1984	हाँ			
40	मांगे राम, गांव व डांरा अरेनपुरा, जिला करनाल	9-8-1984	हाँ			
41	वेद प्रकाश, गांव धानपुर, पी०ओ० दौलताबाद, जिला गुड़गांव	6-8-1984	हाँ			
42	नरेन्द्रा कुमार सरीन, म०नं० 2270/ए, न्यू आबादी, सुभाश नगर, अम्बाला सिटी	8-8-1984	हाँ			
43	मिस आरा, म०न० 9200/6, नया बास, अम्बाला सिटी, जिला अम्बाला	7-8-1984	हाँ			

44	कुलजिन्दर कौर, गांव लालपुर, पी0ओ0 नारायणगढ, जिला अम्बाला	8-8-1984	हाँ			
45	परवीन कुर, 85 / 2, आहता नई रेलवे रोड, गुड़गांव	10-10-1984	हाँ			
46	कन्हैया लाल, गांव साहपुरा पी0ओ0 बल्लभगढ, जिला फरीदाबाद	15-10-1984		हाँ		
47	ओम प्रकाश भार्मा, गांव वाला फतेह, जिला बिलासपुर (एच0पी0)	7-2-1985		हाँ		
48	राजेन्द्र सिंह वी0पी0ओ0 तीरा, जिला रोपड़ (पंजाब)	12-2-1985		हाँ		
49	परवीन कुमार, म0न्ड0 731,	4-2-1985	हाँ			

	प्रेम नगर, करनाल					
50	गुरदयाल सिंह, रामपुरा, पी०आ० धाना कलां, जिला हिसार	13-2-1985		हाँ		
51	मिस बसन्ती देवी, म०नं० 719, सैकटर 2, पंचकूला	13-2-1985	हाँ			
52	नीरज कुमार कौर टाका, भवन धानंद रोड, कुरुक्षेत्र	19-2-1985		हाँ		
53	रणवीर सिंह, वी०पी०आ० अरावरा, जिला सोनीपत	8-2-1984	हाँ			
54	मन बहादर, गांव रमजा, पी०आ० गुजयां, जिला पर्वत नेपाल	10-2-1984			हाँ	
लेखा-लिपिक						
1	मोहन लाल, कुएं वाला	30-11-1979	हाँ			

	मौहल्ला, गांधी चौक, हिसार					
2	राजिन्द्र प्रसाद रोहिला, डंगा रोड, पठानकोट	5-12-1979	हाँ			
3	राधाकृष्ण गुप्ता, गांव गोवली, पोस्ट भाहजादपुर, जिला अम्बाला	13-7-1981	हाँ			
4	भरपूर सिंह, गांव व डा० कनीना, जिला महेन्द्रगढ़	10-7-1981	हाँ			
5	अ०क कुमार मेहता, 222/9, भास्त्री गेट, टोहाना, हिसार	19-8-1981	हाँ			
6	ध्यान चन्द, गांव व डा० राजसन, जिला करनाल	24-3-1982	हाँ			20-2-84 के सेवा से त्याग
7	साहिब खान, गांव व डा०	28-4-1983	हाँ			

	सिकरवा, जिला गुड़गांव					
8	सुनील कुमार, 9, फ्रैंड्स कालोनी, टाउन हाल रोड, अम्बाला सिटी	3-5-1983	हाँ			
9	देवेन्द्र सिंह, गांव कनबरी, पी0ओ0 विनदरोली, जिला सोनीपत	3-5-1983	हाँ			
10	प्रदीप कुमार, मोहल्ला दुर्गावाला, झज्जर	4-5-1983	हाँ			
11	राजेन्द्र सिंह, वी0पी0ओ0 खण्डे वाली, जिला रोहतक	5-5-1983	हाँ			
12	धर्मवीर सिंह, गांव पहारपुर, जिला रोहतक	1-6-1983	हाँ			12-8-1983 को सेवा से त्याग
13	चमन लाल, म0नं0 37 / 16, गुरु नानकपुरा,	23-1-1984	हाँ			

	पानीपत, करनाल					
14	पवन कुमार, म०नं० 2448 / 2, जगाधरी गेट, अम्बाला सिटी	27-1-1984	हां			19-2-84 को सेवा से त्याग
15	देस राज, गांव बरोली माजरा, पी०ओ० लोड़ी, जिला अम्बाला	27-1-1984				1-10-1984 को सेवा से त्याग
16	कृष्ण लाल, गांव मीरपुर, पी०ओ० नारायणगढ़, जिला अम्बाला	28-3-1984			हां	एच०एल०आर०डी०सी० के सरपलस पूल से
17	लक्ष्मण राम, गांव अवली, पी०ओ० अवला, जिला करनाल	29-3-1984			हां	यथा
18	नरेन्द्र कुमार, कोठी नं० २, गली नं० २, जिला भिवानी	2-4-1984	हां		हां	एच०एल०आर०डी०डी० सी० से

19	परमल सिंह, गांव मनगोली, पोस्ट आफिस, सनगीर, जिला कुरुक्षेत्र	9-1-1985	हाँ			
----	---	----------	-----	--	--	--

कैफीतायर

1	रमेश कुमार, म0नं0 12 / 118, महाबीर पार्क, बहादुरगढ़ (रोहतक)	9-7-1981	हाँ			
---	---	----------	-----	--	--	--

सीनियर आडिटर / एस0ओ0

1	आत्मा राम	27-2-1981			प्रतिनियुक्ति पर	
2	ओ0पी0 मुंजाल	30-12-1983			यथा	
3	सुरेश कुमार	4-1-1983			यथा	

सीनियर लेखा लिपिक

1	राम चन्द, गांव जर्थरी, पी0ओ0 राई, जिला	7-1-1985	हाँ			
---	---	----------	-----	--	--	--

	सोनीपत					
2	हरजीत सिंह, टयुमवैल फारम, नजदीक गीता भावन, गुड़गांव	31-1-1985	हाँ			

सीनियर अकाउटेंट

1	राके । कुमार, म0नं0 1174, सैकटर 23बी, चण्डीगढ	2-4-1979	हाँ			
---	---	----------	-----	--	--	--

असिस्टेंट अकाउटेंट

1	उमे । चड्ढा, कोठी नं0 84, सैकटर 27ए, चण्डीगढ	20-971979		हाँ		8-10-1980 को सेवा से त्याग
2	ए0के0 श्री वास्तव, म0नं0 सी / 2 / 12 औरंगाबाद, वाराणसी	9-2-1982		हाँ		8-10-1982 को सेवा से त्याग

जूनियर अकाउटेंट

1	राके ठ ग्रोवर, म0नं0 1546, सैकटर 23, चण्डीगढ	24-9-1979		हां		3-11-1981 को सेवा से त्याग
2	अमूल्य कुमार, टैम्परेरी कालोनी, पो0ओ0 रसाजन, जिला रायगढ	15-3-1982		हां		

सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर

1	वेद वतरा, म0नं0 225, 8वां मरला, सोनीपत	15-2-1980		हां		9-5-1980 को सेवा से त्याग
---	---	-----------	--	-----	--	------------------------------

जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर

1	रमेठ कुमार, सूरजपुर, वी0सी0 डब्ल्यू0 अम्बाला	7-8-1980	हां			2-1-1984 को सेवा से त्याग
2	मिसेज राज कुमारी, म0नं0 209 / 210, अर्जुन नगर, गुडगांव	21-8-1981	हां			

झाईवरज

1	गरीब राम, गांव गणे पुर, पी०ओ० कटमोली, जिला अम्बाला	27-11-1981	हाँ			
2	अमरीक सिंह, म०नं० 2127 / 37, चण्डीगढ़	10-10-1983	हाँ			

रिसेप अनिस्ट

1	मिस पूनम क यम, म०नं० 1530, सैकटर 11सी, चण्डीगढ़	3-4-1981	हाँ			
---	---	----------	-----	--	--	--

कलर्क कम टाईपिस्ट

1	रो न लाल, अम्बाला	14-8-1981	हाँ			हरद्रोन को स्थानान्तरित
2	भोरसिंह गांव खेरा खालीलपुर, पी०ओ० नूंह, गुड़गांव	5-2-1982	हाँ			14-2-1983 को सेवा से त्याग

3	अनील कुमार, म0नं0 3474 / 37सी, चण्डीगढ़	1-3-1982	हाँ			13-10-1982 को सेवा से त्याग
4	भूभ दयाल, म0नं0 4797, डॉ अम्बेदकर नगर, गली नं0 1, अम्बाला कैट	3-2-1982		हाँ		1-3-1983 को सेवा से त्याग
5	प्रेम कुमार वर्मा, म0नं0 1267, मोहल्ला बनस, जिला महिन्द्रगढ़	2-1-1984	हाँ			
6	भीष्म चन्द, गली मलयन, नजदीक गीता भवन, भिवानी	3-1-1984	हाँ			
7	दिने । कुमार, गांव तसरोली, पीओ धनोरा, जिला अम्बाला	24-1-1984	हाँ			
8	एस0के0 गौतम, न्यू हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,	2772-1984				एच0एल0आर0 डी0सी0 के सरपलस

	करनाल					पूल से
9	मिसेज विजय कुमारी, 9993 / ए / सराय रोहिला, रोहतक रोड, न्यू दिल्ली	12-12-1984	हाँ			

टयूबवैल ओपरेटर

1	रमेता कुमार, वी0एड पी0ओ0 बुरवाल, जिला सोनीपत	8-8-1984	हाँ			
2	पुरुशोतक दास, गांव सिंहा, तहसील रिवाड़ी, जिला मोहिन्द्रगढ	14-8-1984	हाँ			
3	कृष्ण चन्द, गांव पिंगली, पी0ओ0 चरो, जिला करनाल	14-8-1984	हाँ			
4	जोग ध्यान, म0नं0 68, वार्ड नं0 9, पेहवा, जिला	17-8-1984	हाँ			

	कुरुक्षेत्र					
5	सुमेर चन्द, गांव धनोरा, जिला अम्बाला	14-8-1984	हाँ			
6	राम भगत, गांव रामगढ जिला मोहिन्दगढ	21-8-1984	हाँ			
7	बाबू राम, गांव गुडडा, पी0ओ0 अमुपुर, जिला करनाल	28-8-1984	हाँ			
8	प्रेम चन्द, म0नं0 140, मुगलन मुहल्ला, जिला करनाल	14-9-1984	हाँ			
टैक्नीकल असिस्टैंट						
1	गुल अन कुमार, म0नं0 वी-11-1693, मुहल्ला प्रधान, जिला रोहतक	19-2-1981		हाँ		

2	मदन लाल यादव, रोहतक	25-3-1981		हां		हरद्रोन को स्थानान्तरित
3	के०के० वर्मा, राजस्थान	26-3-1981		हां		यथा
4	रमेत चन्द, म०नं० 7434 / 4, नदी मुहल्ला, अम्बाला सिंटी	1476-1982	हां			18-4-1984 को सेवा से त्याग
5	रघुवीर चन्द, वी०पी०ओ० करुर, तहसील नरवाना, जिला जीन्द	6-12-1984	हां			

सहायक

1	आर०एस० चावला, अम्बाला	26-11-1981		हां		हरद्रोन को स्थानान्तरित
2	निरंजन राम, म०नं० 2388 / 1, मरीवाला टाउन, मनीमाजरा	26-3-1982	हां			

3	एस०पी० गुप्ता	15—1—1984			हां (हरियाणा सिविल सचिवालय से प्रति नियुक्ति पर)	
4	राम सरन	12—3—1984			यथा	
5	एस०एस० डागर	6—2—1984			यथा	
6	डी०आर० लामा	6—2—1984			यथा	
7	आर०एन० यादव	6—2—1984			हां (हरियाणा सिविल सचिवालय से प्रति नियुक्ति पर)	
8	एस० के० मित्तल	6—2—1984			यथा	
9	सती । कुमार	18—6—1984			समाज कल्याण विभाग से प्रति	

					नियुक्ति पर	
10	कै०एल० भार्मा	11-7-1984				
सेवादार						
1	मांगे राम, रोहतक	16-11-1979	हाँ			
2	मोहिन्द्र सिंह, गांव सकरीन, जिला मण्डी	22-2-1980	हाँ			
3	सुखविन्दर सिंह, सरनदी गेट, पटियाला	5-2-1981	हाँ			
4	रामफल, जीन्द, हरियाणा	19-8-1981	हाँ			हरद्रोन का स्थानान्तरित
5	अनन्त राम, अम्बाला, हरियाणा	24-8-1981	हाँ			यथा
6	बलवन्त सिंह, अम्बाला, हरियाणा	27-8-1981	हाँ			यथा

7	मेहर सिंह, वी०पी०ओ० सनकरी, जिला सोनीपत	28-9-1981	हाँ			
8	ठाकुर प्रसाद पांडे, राम कि न कलोनी, अम्बाला कैट	30-9-1981	हाँ			
9	भोर सिंह, गांव थनावडी, तहसील तो नाम, जिला भिवानी	10-12-1981	हाँ			
10	जय भगवान, गांव खालिरा, जिला करनाल	19-1-1982	हाँ			
11	केहर सिंह, वी०पी०ओ० भाहजादपुर, जिला अम्बाला	3-2-1982	हाँ			
12	टीकम सिंह, गांव खेरा खलीलपुर, जिला गुडगांव	9-2-1982	हाँ			
13	राम सिंह, वी०पी०ओ०	9-2-1982	हाँ			

	बस्ती, जिला करनाल					
14	हवा सिंह, वी०पी०ओ० कलीओमा, जिला सोनीपत	9-8-1982	हाँ			
15	मातु राम, गांव खांगारा, जिला अम्बाला	25-6-1982	हाँ			
16	जयपाल सिंह, गांव दमदमा, जिला गुड़गांव	31-3-1983	हाँ			
17	लछमण सिंह, गांव व पी०ओ० पनगली, जिला मण्डी	18-12-1984	हाँ			जनगणना विभाग
18	राम चन्द, मण्डी	20-6-1983				डाकतार विभाग से प्रति नियुक्ति पर
19	अर्जुन राम, गांव बरेली, पी०ओ० जुलाहा, जिला पिथौरागढ़	7-11-1984				डी०आर०डी० रोहतक से स्थानान्तरण

इलैक्ट्रोनी तायन

1	जसवन्त सिंह मलिक, म0नं0 2, बतरा कलोनी, नजदीक सुजान सिंह पार्क, जिला सोनीपत	27-1-1984		हाँ		
---	---	-----------	--	-----	--	--

रिकार्ड कीपर

1	रविन्द्र कुमार, म0नं0 1801, मुहल्ला रामपुरा, जिला हिसार	18-2-1984	हाँ			
2	महावीर प्रसाद, वी0पी0ओ0 खरखोदा, जिला सोनीपत	22-10-1984	हाँ			
3	मिस प्रभा रानी, वी0पी0ओ0 नारायणगढ़, जिला अम्बाला	18-10-1984	हाँ			
4	अनील कुमार, वी0 न ठहरा, पी0ओ0 सिढौरा,	30-11-1984	हाँ			

	जिला अम्बाला					
5	रणवीर सिंह, कोठी नं० 3181, सैक्टर 28-बी, चण्डीगढ़	8-2-1985	हाँ			
6	अनील कुमार, नजदीक गवर्नर्मेंट हाई स्कूल कलानौर, जिला रोहतक	11-2-1985	हाँ			
7	सुरे । कुमार, म०नं० 34 / 8, मुहल्ला पनसारीन, जिला कुरुक्षेत्र	18-2-1981	हाँ			

अनुबन्ध—३

निगम हरियाणा राज्य में उद्योग के विकास में जुटी हुई है। राज्य में बड़े एवं मध्यम स्तर में लगी लगभग 325 वर्तमान इकाईयों का तीसरा भाग निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता में लगा है। निगम की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता से राज्य में औद्योगिक क्षेत्र में प्रचूर धन राहिा का संचय हुआ है। जिससे बहुत संख्या में रोजगार सुविधायें उत्पन्न हुई हैं राज्य में औद्योगिक विकास को बहुत बढ़ावा मिलता है। जिससे बहुत संख्या में रोजगार सुविधायें उत्पन्न हुई हैं एवं राज्य को नाना प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ हुए हैं। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कम्पनियों की संख्या जिन को निगम ने सहायता प्रदान की है निम्न है :—

1. सावधि ऋण योजना के अन्तर्गत कम्पनियों की संख्या— 67 ईकाईयां
2. साम्य सांझेदारी तथा हिस्सों के निम्नांकन की योजना— 31 ईकाईयां
3. सार्वजनिक / संयुक्त / सहायक क्षेत्र में औद्योगिक ईकाईयां—20 ईकाईया
4. उद्यमियों की संख्या जिनको विकसित प्लाट निर्मित भोड़ नाना सुविधाओं सहित आबंटन किए गए— 1635

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, इन एम्पलाईज में कम से कम 40 की तो मैंने गिनती की है, वे ऐसे हैं जो दूसरे प्रान्तों के हैं। इनमें कुछ असिस्टेंट्स तक भी हैं। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे बतायेंगी कि लोग इन पोस्टों के लिये हरियाणा में नहीं मिलते थे ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर सर, इस निगम में 253 कर्मचारी हैं। अगर इनमें से केवल 40 कर्मचारी दूसरे प्रान्तों के भी हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इनमें कुछ टैक्नीकल तथा दूसरे कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो यहां पर नहीं मिलते थे।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, टैक्नीकल कर्मचारी नहीं हैं। वाराणसी, राजगढ़, राययगढ़ (मध्य प्रदे ।) तथा पूना तक से आदमी लिये गये हैं। मैंने इस लिस्ट में देखा है कि कलर्क, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सिविल जिसके लिये कोई क्वालीफिकेशन आपने नहीं दी हैं, इन पोस्टों के ऊपर भी बाहर के लोग लगे हुए हैं जबकि हरियाणा में पहले ही बहुत ज्यादा अनेम्पलायमेंट हैं। बिना किसी एडवरटाइजमेंट के मनमाने तरीके से लोग लगाये जाते हैं। मैं इस सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि क्या इन पोस्टों को भरने के लिये कोई एडवरटाइजमेंट की गयी थी या यों ही मनमाने तरीके से भर्ती कर लिये गये हैं।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर सर, जो बात माननीय सदस्य ने कही है, यह ठीक नहीं है। बिना किसी एडवरटाईजमेंट के हमने कभी लोग नहीं भरे हैं। यह बतायें कि वह कौन सी पोस्ट के बारे में कह रही हैं कि हमने लोग बिना एडवरटाईजमेंट के लिये हैं ? (व्यवधान व भाओर)

श्रीमती चन्द्रावती: यह बता दो कि कौन कौन से अखबार में और किस दिन एडवरटाईज की गई ? (व्यवधान व भाओर)

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: सर, हम एक तो रोजगार विभाग के माध्यम से लेते हैं, दूसरे विज्ञापन के माध्यम से लेते हैं और इसके अलावा अन्य स्त्रोतों से लेते हैं।

एक आवाज़: वे अन्य स्त्रोत क्या हैं ?

मुख्यमंत्री (चौधरी भजन लाल): अन्य स्त्रोत हैं डैपुटे अन आदि।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: अन्य स्त्रोतों से अभिप्रायः के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भी निगम में प्रति नियुक्ति होती है। निगम में कुछ कर्मचारी दूसरी निगमों से स्थानांतरित होकर भी आते हैं। इन सारे तरीकों से ही कर्मचारी निगम में लिये जाते हैं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अकसर ऐसा देखने में आया है कि कई कारपोरे अन्ज में औवर स्टाफिंग है। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि इस कारपोरे अन में गवर्नर्मैंट ने आफिसर्ज की और कलैरीकल स्टाफ की कितनी पोस्टें सैंक अन या एपूव कर रखी हैं और उनमें से कितनी पोस्टों के खिलाफ भर्ती कर रखी हैं?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: जो सैंक अन्ड पोस्टें हैं, उनमें से 182 सामान्य, 32 भूतपूर्व सैनिक, 23 अनुसूचित जाति, 14 पिछडे वर्ग और 2 विकलांग। अगर माननीय सदस्य कहें तो मैं सब के नाम भी बता सकती हूं।

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने मेरी बात को समझा नहीं है। उन्होंने कहा कि इतनी पोस्टें सैंक अंड हैं। मैंने यह भी पूछा है कि इनमें से कितनी पोस्टों पर आदमी भर्ती किए हुए हैं। मैं एक बार फिर कलैरीफाई कर दूं कि मैं उनसे यह जानना चाहता दूं कि किस सर्विस में कितनी पोस्टें सैंक अन्ड हैं, और उनमें से कितनी पोस्टें भरी हुई हैं? (व्यवधान व भाओर)

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: पोस्टें तो आव यकता अनुसार होती हैं। (व्यवधान व भाओर)

चौधरी सुरेन्द्र सिंह: आप किसी भी दफतर में देख लें, सैंक अन्ड पोस्टें जरूर होती हैं। चाहे वह आव यकता अनुसार ही क्यों न हों, लेकिन गवर्नर्मैंट उनकी सैंक अन जरूर देती है।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, बाकायदा जितनी पोस्टें सैंक अंड थीं, हमने उतनी पर ही आदमी लगाये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने बताया 253 टोटल पोस्टें हैं। इनमें से 188 जनरल की चाहिये। 188 के मुकाबले जनरल साईड पर 182 लगे हुए हैं। इनमें 6 कम हैं। भूतपूर्व सैनिक 25 चाहिये थे लेकिन 32 लगे हुए हैं अनुसूचित जाति के चाहिये 27 थे लेकिन लगे 23 हुए हैं, इसमें 4 कम हैं। पिछड़ी जातियों के 11 चाहिये थे, 14 लगे हुए हैं। इसमें 3 फालतू लगे हुए हैं। दो विकलांग हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: जनाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं यह पूछना चाहती थी कि इन पोस्टों को कब एडवरटाईज किया गया और कौन से अखबार में किया गया था ?
(व्यवधान व भाओर)

श्री अध्यक्ष: इस सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह बहुत पुरानी भर्ती है।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, स्टेट में लोगों को जोब्ज नहीं मिलतीं और ये दूसरी स्टेट्स के लोगों को भर्ती किए जा रहे हैं। ये बाहर के लोगों को एम्प्लायमैंट दे रहे हैं।

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, बहिन जी बहुत पुरानी मैम्बर हैं, वकील भी हैं। प्रजातन्त्र में जहां तक सर्विस का सवाल है, बाकायदा भारत सरकार का कानून बना हुआ है कि दे वासी यानि हिन्दुस्तान का वासी कहीं भी नौकरी निकले तो वहां पर एप्लाई कर सकता है, इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। जहां तक उनको सर्विस देने का ताल्लुक है, जिस व्यक्ति ने सिलैक अन करनी है, वह देखता है कि कौन सा व्यक्ति उस काम के लिए काबिल है या योग्य है, वह उसको सिलैकट करता है। पहल हमें आ उनको दी जाती है जो स्टेट के लोग होते हैं, लेकिन अगर किसी पोस्ट के लिये कोई काबिल व्यक्ति ने मिले तो दूसरों को स्थान देना पड़ता है। काम चलाना होता है, इसलिये उनको नौकरी देनी पड़ती है। काम बन्द तो नहीं किया जा सकता।

श्रीमती चन्द्रावतीः क्या आपको टाईपिस्ट भी हरियाणा के नहीं मिले।

चौधरी भजन लालः इसमें स्पीड की बात होती है। कई बार स्पीड वाले आदमी कम मिलते हैं। आपने नर्सिज के बारे में देखा होगा कि 90 परसैंट नर्सिज केरला साईड की लगी हुई हैं। मुझे कल से 10 परसैंट नर्सिज ही हरियाणा प्रदेश की होंगी। जब हमें एम्प्लायमैंट एक्सचेंज से आदमी न मिलें तो हम बाकायदा उनसे एन०ए०सी० लेकर उसके बाद एडवरटाइजमैंट करते हैं। एम्प्लायमैंट एक्सचेंज में अगर किसी कैटेगरी के लिये नाम दर्ज न हो या कोई सूटेबल आदमी न मिले तो वह लिख देते हैं कि इस

पोस्ट के लिये हमारे पास कोई नाम दर्ज नहीं है और एनोएओसी० दे देते हैं। फिर दूसरे तरीके से सिलैक अन कर लेते हैं।

श्रीमती चन्द्रावतीः कौन से अखबार में एडवरटाइजमैंट दिया है ?

चौधरी भजन लालः आपने एक साल की इन्फर्मेंट अन नहीं पूछी है। आपने तो 5 साल की पूछी है। जब भी कोई इन्टरव्यू ली गई है। बाकायदा एम्पलायमैंट एक्सचेंज के थ्रू आदमी लिये गये हैं या बाकायदा प्रैस में एडवरटाइजमैंट करके, इन्टरव्यू करके सिलैक अन की गयी है।

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो भर्ती की गयी है, यह आर्बिट्री तरीके से की गयी है और केवल अपने चहेतों को लिया गया है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, आप ही देखिये, एक तरफ ये कहती हैं कि अपने चहेतों को भर्ती कर लिया दूसरी तरफ कहती हैं कि बिहार से ले लिये और मध्य प्रदेश से ले लिये।

चौधरी हुकम सिंह फोगटः स्पीकर साहब, बहिन जी जवाब देते हुए यह कहा है कि कुल 253 कर्मचारी हैं। क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि इनमें से कितने एम्पलायमैंट एक्सचेंजिज के थ्रू लिये गये कितने विज्ञापन के थ्रू लिये गये और कितने औन डैपुटे अन लिये गये हैं ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, जो भी कर्मचारी इस निगम में लिये गये हैं वे नियमानुसार लिये गये हैं।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, इस सवाल के बारे में काफी कुछ कहा गया है और लिस्ट भी दी गई है। चालीस आदमी हरियाणा के बाहर के हैं। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि किसी दूसरे प्रदे 1 का कोई आदमी किसी पोस्ट के लिए न रखा जाए। स्पीकर साहब, जहां तक हरियाणा प्रदे 1 का ताल्लुक है हमारे यहां अनएम्प्लायमैट की बड़ी भारी प्रोबलम है। क्या मंत्री महोदया हाउय में यह आ वासन देंगी कि आइंदा जो भी रिकूटमैट होगी उसमें हरियाणा के लडकों को प्राथमिकता दी जाएगी ? स्पीकर साहब, इन चालीस के अलावा अनैक चर 2 के पेज तीन पर कुछ पोस्टस हैं जिनके अगेस्ट भर्ती किए गए लोगों के नाम तो दे दिए हैं लेकिन ऐड्रेस नहीं दिये हैं। इससे ऐसा जाहिर होता है कि वे भी दूसरे प्रान्तों के रहने वाले हैं। इनमें डिप्टी इंजीनियर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं। इनके नाम हैं लेकिन ऐड्रेस नहीं दिये हैं। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगी कि इंडस्ट्रियल डिवैलपमैट कार्पोरे अन का चेयरमैन किसी आई0ए0एस0 अफसर को लगाने की बजाए कोई टैक्नीकल आदमी लगाने का सरकार का विचार है जिससे कि कार्पोरे अन का काम ठीक ढंग से चल सके ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, हरियाणा प्रान्त छोटा सा प्रान्त है। कितने हर वर्ष यहां से पढ़कर निकलते

हैं, यह सबको पता है। अगर हम इस किस्म का बैन लगा दें कि केवल अपने प्रदेश के बच्चों को ही नौकरी में लिया जाएगा, किसी दूसरे प्रान्त के बच्चे नहीं लिये जाएंगे तो फिर दूसरे प्रान्त भी हमारे बच्चों के लिए बैन लगा देंगे। फिर भी हम यह ध्यान रखते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे अपने प्रान्त के लिये जाएं। यह निगम भी इसीलिए बनाई गई है कि यहां के लोगों को अधिक से अधिक भला हो सके और यहां के लड़कों को नौकरी मिल सके। स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत सदन को वि वास दिलाती हूं कि आइंदा जब कभी कर्मचारियों की भर्ती होगी तो हरियाणा के बच्चों का ध्यान रखा जाएगा और अब भी रखा जाता है। जहां तक आई0ए0एस0 अफसर की बजाये कोई टैक्नीकल आदमी चेयरमैन बनाने की बात है, स्पीकर साहब, आई0ए0एस0 चेयरमैन बनाने के बाद इस निगम की उन्नति हुई है और इस निगम में 88 परसैंट रिकवरी हुई है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यहां पर बार बार यह बताया जा रहा है कि निगम की पोस्ट्स के लिए एडवरटाइजमैंट की जाती है और हम अगर दूसरे प्रान्तों के बच्चों पर पाबन्दी लगा देंगे तो वे हमारे बच्चों पर पाबन्दी लगा देंगे और सारा हिन्दुस्ताचन एक है। स्पीकर साहब, ऐसे समझाया जा रहा है जैसे कि यह क्लास रुम हो।

क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि यह एडवरटाइजमैंट किस किस अखबार में और कब कब की गई ?

स्पीकर साहब, अनैक चर में श्री डी०के० अग्रवाल, टैकनीकल मैनेजर का नाम आया है। वे चण्डीगढ़ के रहने वाले हैं। 12-12-1979 को वे अप्वायंट किए गये और 31-8-1982 को रिजाइन कर दिया। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने त्याग पत्र क्यों दिया ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे आपके रवैये से तंग हों और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हो ? कहीं यह गलत अप्वायंटमैंट तो नहीं हो गया था ? स्पीकर साहब, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उसके जवाब से सप्लीमैंटरीज अराइज होती हैं और इनको सभी सप्लीमैंटरीज का जवाब देना चाहिए।

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, बारह व्यक्ति छोड़ कर चले गए। अध्यक्ष महोदय, हम किसी पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं कि वह छोड़ कर न जाए। हो सकता है कि उन्होंने कोई बिजनैस भुरू कर लिया हो या कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई हो। इस समय मेरे पास उनके इस्तीफे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: इनकी यह बात ठीक है। किसी आदमी को कहीं अच्छी जगह बैटर पोस्ट मिल जाती है या वह अपना कोई धन्धा भुरू कर लेता है तो वह छोड़ कर जा सकता है।

Sh. Mangal Sein: Half an hour discussion may be allowed on this queation, Sir. They are not fully prepared. काफी लोग छोड़ कर चले गए। मि० अग्रवाल छोड़ कर चल गया। क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगे कि उसके त्यागपत्र में क्या लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्षः किसी के मन में क्या है कोई आदमी यह कैसे जान सकता है ?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस्तीफे में क्या लिखा है, मैं तो यह जानना चाहता हूं ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, इस्तीफा तो मेरे पास नहीं है। डा० साहब अगर व्यक्तिगत रूप से इस बारे में जानना चाहेंगे तो मैं इनको लिखकर भिजवा सकती हूं या ये मेरे कार्यालय में आकर देखा सकते हैं।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, सवाल के पार्ट बी का जवाब अनेक चर 3 पर दिया हुआ है। इसमें लिखा है:-

“Number of companies promoted for setting up projects in public/joint/assisted sector is 20”

क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इन बीस कम्पनीज में ज्वायंट सैक्टर में कितनी कम्पनीज हैं और उनमें कौन सी प्राईवेट कम्पनीज का सांझा है उनके नाम बताये जायें। इसके अलावा उन 31 कम्पनीज का नाम भी बताएं जिनको अंडर राइटिंग/इक्विटी पार्टिपिपे अन स्कीम के थू असिस्ट किया गया है ?

श्रीमती भाकुन्तला भगवाड़िया: स्पीकर साहब, मैं उन 31 के नाम बता देती हूं।

1	न्यूकम प्लास्टिक लि0, फरीदाबाद
2	परस्टोईद आफ इंडिया लि0, फरीदाबाद
3	भारत कारपैट्स लि0 फरीदाबाद
4	पानीपत फूडज लि, पानीपत
5	कर्सॉवैल इंडिया लि0, फरीदाबाद
6	प्रोमेन लि0 फरीदाबाद
7	केवल वर्क्स (आई) लिमिटेड, फरीदाबाद
8	हरियाणा स्टील एंड अलायज, मुरथल
9	हरियाणा स्टील एंड अलायज, मुरथल
10	हांडा स्टील्स प्रा0 लि0 फरीदाबाद
11	जोतिन्द्रा स्टील एंड टयूब्स, फरीदाबाद
12	हरियाणा ब्रेवरीज लि0 मुरथल
13	टाईगर लाक्स लि0 गुड़गांव
14	डेल्टन केबल्ज लि0 फरीदाबाद
15	डाबरीवाला स्टील एंड इंजीनियरिंग फरीदाबाद

16	मोहता इलैक्ट्रो स्टील लिंग भिवानी
17	हरियाणा कनकास्ट लिंग हिसार
18	हरियाणा आक्सीजन लिंग हिसार
19	सहगल पेपर्ज लिंग धारुहेड़ा
20	सैनचूरा टयूब्स लिंग भिवानी
21	हरियाणा टेनरीज लिंग भिवानी
22	इंडो स्विस टाईम लिंग गुडगांव
23	तिरुपति वूलन मिल्ज, नथूपुर
24	वरेजा निपिंग फैस्टनर्ज, धारुहेड़ा
25	रामा फाईवर लिंग हिसार
26	ईस्ट इंडिया सीन टैक्स लिंग धारुहेड़ा
27	प्रुपति स्पिनिंग एंड विर्विंग मिल्ज लिंग, धारुहेड़ा
28	हिन्दुस्तान इंस्टर्स मेंटस, धारुहेड़ा
29	ओम स्टी टयूब्ज लिंग धारुहेड़ा
30	विक्टर केब्लस लिंग फरीदाबाद

Construction of Houses for Weaker Sections

***859. Ch. Balvir Singh Grewal:** Will the Minister of State for Local Govt. be pleased to state-

(a) the district wise names of villages in the State where houses for weaker sections of the society have been constructed during the years 1981-82, 1982-83 and 1983-84 together with the number of houses constructed in each village;

(b) whether all the houses referred to in part (a) above have been occupied if not, the reasons therefor; and

(c) the total cost of each house togetherwith the number of instalments fixed for the repayment of the cost thereof ?

स्थानीय राज्य मंत्री (श्री प्यारा सिंह):

(क) व्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(ख) नहीं जी। अभी सब अलाटियों ने मकानों का कब्जा नहीं लिया है। इसका कारण डिजाईन की अस्वीकार्यता तथा कुछ सुविधाओं जो स्कीम तथा मूल्य का भाग नहीं थीं, का उपलब्ध न होना है।

(ग) प्रत्येक मकान की कुल लागत 4900/- रु० से 6780/-रु० तक भिन्न भिन्न है। लागत की पुनः अदायगी अलाटी की इच्छानुसार 15/25 वशों में मासिक किस्तों में की जाती है।

ब्यौरा

वर्ष	जिले का नाम	गांव का नाम	निर्माण किये गये मकानों की संख्या
1981–82	भौन्य	भौन्य	भौन्य
1982–83	फरीदाबाद	मोहना	78
		निगांव	118
		दयालपुर	100
	कुरुक्षेत्र	खेड़ी डबलान	44
		लोहरा	50
	करनाल	रम्भा	130
		फत्तुपुर	66
		सुबरी	65
		उचाना	34

	गुड़ गांव	चक्रपुर	72
		पुनहाना / नानकपुर	120
		धनकोट	72
	हिसार	बालसमन्द	144
	भिवानी	मिठाथल	38
		बापोड़ा	56
		लोहारू जट्टू	96
		बहल	48
		कुड़ाल	46
		महराना	64
		बलियाली	64
		कुल	1505
1983–84	भिवानी	बपोड़ा खण्ड-2	26
		कुड़ाल खण्ड-2	18

		रटेरा खण्ड-1	75
		मण्डोला	58
		कादमा	28
		चहड़कला	50
		भगवानवाला	60
		चांग	12
	रोहतक	खरक कला	46
	करनाल	सिवाह	65
		उचानी	28
		रम्भा	70
		पट्टी कल्याणा	29
	फरीदाबाद	अगवानपुर	48
		बामनीखेड़ा	86
		कलवाका	40
		भगोला	30

		पिरथला	80
		पाली खण्ड-1	16
		कुल	865

10.00 बजे ।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया कि कुल 2370 मकान सात जिलों में बनाये गये। पहली बात तो मंत्री महोदय यह बताएं कि अब तक कितने मकान अनआकुपाईड़ हैं जो कि लोगों ने लिये नहीं हैं और इनको बने हुए कम से कम दो तीन साल का समय हो चुका है। वे यूं ही पड़े पड़े बरबाद हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका खराब डिजाईन और अमैन्टीज न होने के कारण भी लोग उन मकानों को लेना नहीं चाहते। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि कहीं उन मकानों में सब स्टेंडर्ड मैटीरियल तो नहीं लगा जिसके कारण लोग इन मकानों को आकुपाई करना नहीं चाहते ?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, कुल 2370 मकान थे जिनमें से 1485 मकान लोगों के पास हैं और 885 मकान डिजाईन खराब होने की वजह से लोगों ने नहीं लिये जो कि पड़े हुए हैं। अब हमने वहां पर बिजली और पानी की पूरी सहूलियतें देने का प्रबन्ध कर दिया है। पहले हम किसी कारण ये सहूलियतें नहीं दे पा रहे थे।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि वीकर सैकंज के लिये 1982-83 में 1505 मकान बनाये गये हैं लेकिन इस वर्ष में रोहतक जिले में कोई मकान नहीं बनाया गया है। वर्ष 1983-84 में केवल खरक कलां में 46 मकानों का निर्माण हुआ यह गांव पहले भिवानी में था अब रोहतक में आ गया है। क्या मंत्री महोदय बताएंग कि जिलों या गांवों में वीकर सैकंज के लिये मकान बनाने का क्राइटेरिया क्या है ?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, जहां जहां से डिमांड आती है, वहां वहां पर हम मकान बनाते रहते हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि वीकर सैकंज के लिये रोहतक जिले में सरकार की तरफ से कोई मकान नहीं बनाया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, वहां की कोई डिमांड नहीं थीं। डिमांड के अनुसार हम मकान बनाते हैं।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, रोहतक जिले में 1983-84 में 46 मकान बनाये गये हैं।

श्री देवी दास: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जाना चाहता हूं कि सोनीपत जिले में जो कि दिल्ली के पास ही है, किसी भी गांव में एक भी मकान नहीं

बनाया गया है। क्या सरकार वहां पर वीकर सैक अन्ज के लिये गांवों के अन्दर मकान बनाने का विचार रखती है ?

श्री प्यारा सिंह: वहां से कोई मांग नहीं आई थी।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे यह जाहिर होता है कि 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में सिरसा जिले में एक भी मकान वीकर सैक अन्ज के लिये सरकार ने गांवों में नहीं बनाया है। उनका यह कहना है कि मांग नहीं आई, यह गलत है। मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि गांवों में मकान बनाकर देने का सरकार का क्राइटेरिया यानि मापदण्ड क्या है ?

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने क्राइटेरिया पूछा है। इसका क्राइटेरिया यह है कि इसके लिए बाकायदा एम्प्लीके अन्ज इंवाईट की जाती हैं। इसके अलावा जिन भाईयों को मकान बनाने के लिए सरकार ने 100-100 गज के प्लाट्स दे रखे हैं, अगर वे भाई मकान नहीं बना सकते तो सरकार उनको मकान बनाकर देगी और उनसे आसान कि तों में वसूली करेगी। हाउसिंग बोर्ड से अगर कोई मकान बनवाना चाहें, वे ऐप्लीके अन्ज दे सकते हैं। जैसे जैसे ऐप्लीके अन्ज आती हैं। उनके अनुसार ही मकान बनाये जाते हैं और आसान से आसान कि तों में वसूली की जाती है। भागीराम जी को खासतौर से मैं बता दूं कि जो

हरिजन भाई हैं, उनको हम 2000 रूपये सबसिडि के तौर पर भी देते हैं।

चौधरी कुलवीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया कि लोगों ने बहुत सारे मकान आकुपाई नहीं किये हैं क्योंकि उन का डिजाइन खराब था। क्या मंत्री जी बताएंगे कि इसकी अब रैमेडी क्या है? एक बापोड़ा गांव है जहां पर कोई भी आदमी इन मकानों को लेना नहीं चाहता। इसी तरह से जीन्द में भी ऐसे मकान यूं ही पड़े हुए हैं लोग लेना नहीं चाहते?

श्री प्यारा सिंह: स्पीकर साहब, पहले डिजाइन ठीक नहीं था अब हमने चेन्ज कर दिया है। कमरे के आगे बरामदे की जगह छोड़ दी है। पहले सीमेंट की चादरें लगीं थीं अब हमने उसको हटा कर लोहे की चादरें लगाने का निर्णय लिया है। पानी व बिजली जल्दी देने जा रहे हैं। गांव वालों की डिमांड के अनुसार हमने डिजाइन चेन्ज कर दिया है।

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 1982–83 और 1983–84 में 2370 मकान गरीब लोगों के लिये सात जिलों मे बनाये गये हैं। मैं आपके द्वारा उनसे यह जानना चाहता हूं कि ये मकान कागजों में हैं या असलियत में बने हैं? मौके पर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्र न नहीं है।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि कुल 2370 मकान गरीब लोगों के लिये सात जिलों में सरकार द्वारा बनाकर दिये गये हैं लेकिन उनमें से 885 मकान अभी ऐसे पड़े हुए हैं जिनको लोगों ने लेने से इंकार कर दिया है। क्योंकि एक तो उनको डिजाइन ठीक नहीं है और दूसरा उन पर सब स्टैण्डर्ड मैटिरीयल लगा हुआ है। अभी मुख्य मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि हमने लोगों को 100–100 गज के प्लाटस भी दिये हैं ताकि वे मकान बना सकें। क्या सरकार मेरे इस सुझाव पर विचार करेगी कि बजाये सरकार द्वारा बनाने के वह खुद लोगों को यह कह दे कि वे अपनी मर्जी से अपने डिजाइन कि अनुसार अपने मकान बनाएं और दूसरी सभी तरह की सहायता सरकार उनको दे दे। सरकार की तरफ से हर तरफ से हर तरह की सहायता लोगों को मकान बनाने के लिए मुहैया होनी चाहिये ताकि लोग अपनी मर्जी के अनुसार अपने मकान के ऊपर सही मैटिरीयल लगा सकें।

श्री प्यारा सिंहः ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मकान हाउसिंग बोर्ड बना कर देता है। 22 रुपए महीने की आसान कि त है। हरिजनों को दो हजार रुपए सबसिडी भी दी जाती है।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः अभी मंत्री जी ने बताया कि कुछ मकान इसलिए आकुपाई नहीं हो सके कि उनका डिजाइन खराब था। क्या मंत्री जी बताएंगे कि जिन अफसरों ने यह डिजाइन

तैयार किया था। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है कि गलत डिजाइन क्यों बनाया ?

श्री प्यारा सिंह मकान बनाने से पहले लोगों को नक और दिखाए गए थे। उस वक्त कोई कम्प्लैट नहीं आई थी। लेकिन जब मकान बन गए तो कम्प्लैटस आ गई। अब जो नया डिजाइन बनाया है उसमें आगे एक बरामदा बनाया है। काफी खुली जगह है, कोई चाहे तो वहां कमरा भी बना सकता है।

चौधरी धीर पाल सिंह: अभी मुख्य मंत्री जी ने एक सप्लीमैटरी के जवाब में कहा कि हरिजनों को सौ सौ गज के प्लाट दिए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 1981-82 से 1983-84 तक रोहतक के किस किस गांव से ऐप्लीकेशन मांगी गई और अगर मांगी गई थीं तो कितनी आई थीं ?

श्री प्यारा सिंह: हम अखबार में निकालते हैं। जो दरखास्तें आई थीं उसके मुताबिक हमने दे दिए।

चौधरी बलवीर सिंह ग्रेवाल: अभी मंत्री जी ने बताया कि डिजाइन में खराबी की वजह से ये मकान आकुपाई नहीं हुए। मेरा यह एलीगे अन है और मैं मुख्य मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूं कि बापोड़ा और मीथाथल में जो हाउस बने हैं और हरिजनों को अलाट हुए हैं। वे बहुत गन्दे बने हुए हैं और उनमें मैटिरियल खराब लगा हुआ है। आप वहां एक कमेटी भेजें फिर पता चल जाएगा कि फैक्ट क्या है ?

चौधरी भजन लाल: माननीय सदस्य ने आज से पहले इस बात का कभी जिक्र नहीं किया। आप मेहरबानी करके एक सादे कागज पर लिख कर भी भिजवा दिया करो। अगर किसी गांव वाले ने फ़िकायत की है तो हमारे पास लिख कर भेज दें। अगर कहीं भी सब स्टैंडर्ड मैटीरियल लगा होगा तो बाकायदा इन्क्वायरी करवाएंग और जिसका कसूर होगा सरकार उसके खिलाफ एक अनलेगी।

**Recruitment of Drivers/Conductors/Clerks/Mechanics in
Transport Department**

***854. Sh. Kigab Singh:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-the number of drivers/conductors, clerks and mechanics recruited by the Haryana Transport Department during the period from 1-1-1983 to 1-1-1985 together with the criteria, if any, adopted for their recruitment ?

परिवहन राज्य मंत्री (चौधरी चन्दा सिंह):

(1) भर्ती: परिवहन विभाग द्वारा 1-1-83 से 1-1-85 तक समय के दौरान 459 चालक, 687 परिचालक, 82 लिपिक और 3 यांत्रिक भर्ती किए गए थे।

(2) मापदण्ड: भर्ती प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के अनुसार निर्धारित माध्यम द्वारा की जाती है।

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि निर्धारित योग्यता के आधार पर भरती की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि चालकों और कंडक्टरों के लिए क्या योग्यता निर्धारित की हुई है। वे मैरिट से लिये जाते हैं और बगैर मैरिट से लिये जाते हैं दूसरे क्या वे एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के जरिये लिये जाते हैं या सीधी भर्ती की जाती है ?

चौधरी चन्दा सिंह: किसी भी सर्विस के लिए या तो रोजगार विभाग की तरफ से या एस0एस0एस0 बोर्ड की तरफ से या सैनिक बोर्ड की तरफ से या किसी दूसरे विभाग की तरफ से भरती की जाती है। अगर किसी मुलाजिम की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके किसी लड़के लड़की हो ले लेते हैं। इसके सिवाए भर्ती करने का कोई और माध्यम नहीं है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, ड्राइवर तो टैक्नीकल होता है इसकी बात तो मैं नहीं करता लेकिन जो दूसरा स्टाफ जैसे कंडक्टर और कलर्क बगैरह हैं क्या इनकी भर्ती में रिजर्व एन का ध्यान रखा जाता है ?

चौधरी चन्दा सिंह: जो मैन सवाल था उसका जवाब दे दिया गया है लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि रिजर्व एन की उल्लंघना नहीं की जाती है, उसको बिल्कुल पूरा किया जाता है। हमारे यहां तो रिजर्व एन से भी ज्यादा भरती की हुई है।

चौधरी नर सिंह ढांढ़ा: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैकेनिकों की भर्ती के लिए क्या क्राइटेरिया है ?

चौधरी चन्दा सिंह: मैकेनिक की भर्ती के लिए एक तो आई0टी0आई0 का प्रमाण पत्र देखा जाता है और साथ ही रिपेयर तथा रख रखाव के लिए उसका किसी पब्लिक अंडरटेकिंग या आटोमोबाइल वर्क गाप में दो साल का अनुभव होना चाहिए।

श्री मंगल सैन: अभी मंत्री जी ने कहा कि निर्धारित माध्यम से भर्ती करते हैं। इन्होंने एस0एस0एस0 बोर्ड का भी नाम लिया। मैं जानना चाहता हूं कि आज कल एस0एस0एस0 बोर्ड के चेयरमैन और मैम्बर्ज कौन कौन हैं ?

चौधरी चन्दा सिंह: इस समय तो बोर्ड टूटा हुआ है और उसका कोई चेयरमैन या मैम्बर नहीं है। मैंने तो यह बताया था कि इस अवधि में कुछ ड्राईवर और कंडक्टर बोर्ड के माध्यम से भी लिये थे।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, इन्होंने एक बात और फरमाई थी कि अगर कोई अचानक मर जाए तो उसकी जगह भी रिक्रूटमेंट करते हैं, वह कैसे करते हैं ?

श्री अध्यक्ष: इन्होंने बताया था कि उसके किसी बच्चे को नौकरी दे देते हैं।

चौधरी चन्दा सिंहः उसका जो भी बच्चा होगा, लड़का हो या लड़की हो यानी जो उसके परिवार को जीवन यापन का आसरा दे सके उसको नौकरी दे देते हैं।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, अक्सर देखा जाता है कि रिक्वायरमैट से ज्यादा भरती कर ली जाती है और लोग चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा लोग फर्स्ट एड का बोगस सर्टीफिकेट भी ले लेते हैं। क्या इसका कोई प्रबन्ध करेंगे ?

चौधरी चन्दा सिंहः स्पीकर साहब, रोडवेज दिन रात चलने वाली एक असैंफायल सर्विस है। हम हर डिपो में फालतू स्टाफ रखते हैं। क्योंकि फर्ज किया कोई कंडक्टर स्पैंड हो गया या कोई और दुर्घटना हो गई तो वाहन को रोका नहीं जा सकता। इसलिये उसकी जगह दूसरे आदमी की डियूटी लगा दी जाती है। रिक्वायरमैंअ से ज्यादा सिलेक्ट किये गए लोगों को हम 6 महीने के निर्धारित पीरियड के अंदर ही रखते हैं। हम लिस्ट बना कर तेयार रखते हैं जहां भी जगह खाली हो जाती है वहां पर उस लिस्ट में से भरती कर दी जाती है। स्पीकर साहब, यह सरकार सारे हिन्दुस्तान में बहुत तेज रफतार के साथ काम कर रही है। किसी के बोगस या फर्जी फर्स्ट एड सर्टीफिकेट लेने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जिस भी कर्मचारी ने कोई फर्स्ट एड सर्टीफिकेट लिया हुआ है वह बाकायदा किसी अथौरिटी से ही लिया है। यदि माननीय सदस्य की नालेज में हो कि किसी ने कोई

बोगस फर्स्ट एड का सर्टीफिकेट लिया हुआ है तो वह बता दे।
ऐसी गलत बातें कहने का कोई मतलब नहीं होता है।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा
मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो 687 कंडकटर्ज लिए गए हैं,
उनमें से एम्पलायमेंट एक्सचेंजिक के थ्रू कितने लिए गए हैं ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, 687 में
से 475 कंडकटर्ज एम्पलायमेंट एक्सचेंजिज के थ्रू लिए गए हैं।

Khadwali and Humayunpr Link Drains

***838. Sh. Hari Chand Hooda:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-whether the Government is aware of the fact that Khadwali and Humayunpur drains are lying incomplet; if so, the time by which these drains are likely to be completed ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): The position of both the drains is as under :-

Khadwali Link Drain

The total length as per sanctioned scheme is 21301. The excavation was taken in hand during June, 1984 from the outfall point (outfalling into Drain No. 8 at RD73460/R). The excavation had been completed in a length of 17410 in the land of village Khadwali u9pto 31-884. There is resistance from village Katwara for construction of balance length of 3890 for which people are being persuaded to agree. The

drainage of the area has already been improved with the work already done.

Humanyunpr Drain.

The drain is completed in a length from 0 to Km. 1.13 as per already approved project. There is a demand for its extension from Km. 1.13 to Km. 2.33. A project Estalmate is under preparation for this extended portion and the work will be taken up after the approval of scheme.

श्री हरि चन्द हुड्डा: स्पीकर साहब, अगर मिनिस्टर साहब और हम सब आपस में मिल कर चलेंगे तो लोगों का काफी फायदा होगा और हजारों लोगों को एम्प्लायमैंट मिल जाएगी। जो खड़वाली और हुमायुंपुर लिंक ड्रेनें हैं वह मैं इनके साथ कोआप्रेट करके बनवा लूंगा। मैं इनसे मिल लूंगा और उनको बनवा लूंगा। इसके अलावा मैं इरीगे अन डिपार्टमैंट के आफिसर्ज को भी बड़ी दाद देता हूं कि उन्होंने ड्रेनों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन मिनिस्टर साहब को दाद तब दूंगा जब इन ड्रेनों पर खुदाई का काम भुरू हो जाएगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मिनिस्टर साहब इन ड्रेनों की खुदाई का काम भुरू करके मेरी दाद लेना चाहेंगे ?

चौधरी भाम ॑र सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, हमें इनकी दाद की कोई जरूरत नहीं है। जो खड़वाली लिंक ड्रेन है वह हरियाणा गवर्नर्मैंट ने मंजूर कर दी है वह इस साल में बन जाएगी।

चौधरी धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, जो खड़वाली लिंक ड्रेन है उसकी 3890 फुट की खुदाई के लिए गांव कटवारा के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गांव कटवारा के लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, वह जमीन तो हमने एकवायर कर ली है और उसके मुआवजे का पैसा भी डिपौजिट करवा दिया है। काफी लोगों ने मुआवजा ले लिया है लेकिन कुछ लोगों ने नहीं लिया है। जिन लोगों ने पैसा नहीं लिया है वे उसकी अलाइनमैंट चेंज करवाना चाहते हैं। इरीगे अन डिपार्टमैंट वालों ने उन लोगों को मनाने की कोर्ट भी की है ताकि वे लोग उस ड्रेन की खुदाई के लिए मान जाएं। यदि वे नहीं मानेंगे तो कानून के द्वारा उस ड्रेन की खुदाई इस सीजन से पहले भारू करवा दी जाएगी ?

चौधरी नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे हल्के में जो कसान ड्रेन है उसकी सांगल गांव से आगे खुदाई नहीं हुई है क्या उसकी खुदाई अगले सीजन से पहले करा दी जाएगी ।

चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला: कसान ड्रैन को अगले सीजन से पहले पहले तैयार कर देंगे ।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, इसी सवाल के संदर्भ में माननीय सदस्य ने अपने हल्के की कसान ड्रैन के बारे में सप्लीमैटरी पूछी है। क्योंकि आपने क्वैचन पूछने का स्कोप बढ़ा दिया है इसलिए मैं भी इसी संदर्भ में अपने हल्के के बारे में एक सप्लीमैटर पूछना चाहूँगा। स्पीकर साहब, 1984 में जब प्रदे ठ के दूसरे जिलों में फल्ड नहीं था उस समय मेरे हल्के के 20—25 गांव फल्ड से अफैक्ट हुए थे। मेरे हल्के बेरी के उन 20—25 गांवों में ड्रेनेज डिपार्टमैट के अधिकारियों ने कई नई ड्रेनेज बनाने की स्कीम तैयार करके गवर्नरमैट के पास भेजी थी। वह स्कीम आज तक सैक ठन नहीं हुई है और न ही उन ड्रेनों को बनाने के लिए एक पैसा दिया गया है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उन नई ड्रेनों को बनाने के लिए सैक ठन कब तक दे दी जाएगी ?

चौधरी भाम रेर सिंह सुरजेवाल: स्पीकर साहब, जो फल्ड कंट्रोल बोर्ड है उसकी एक हाई पावर्ड सब कमेटी बनी हुई है, उसका मैं चेयरमैन हूँ लेकिन फल्ड कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री जी हैं। जो हाई पावर्ड सब कमेटी है उसकी मीटिंग महीने दो महीने में हो जाती है लेकिन फल्ड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग साल में एक या दो दफा हो पाती है। हाई पावर्ड सब कमेटी की मीटिंग पिछले महीने हुई थी, उस मीटिंग में स्टेट की फाइनैंसियल पोजीशन को देखते हुए कुछ स्कीमें भुरू करने के लिए रिकमैंड की हैं। जब फल्ड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होगी उन

स्कीमों को एपूव करवा कर काम भुरु करवाने की कोटि तकरेंगे।

Raising up the level of outlets

***890. Smt. Basanti Devi:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether any case of raising of any of the outlets in unauthorised manner in villages of Baland, Sunarian, Titoli, Kabulpu9r, Karauntha; Shimli, Machna, Baliana, Pakasma, Kasrenti, Samachana and Ismaila, has come to the notice of the Government during the years 1983-84 and 1984-85 (to-date);

(b) if so, the action, if any, taken against the persons, if any, found responsible therefor; and

(c) whether any spot inspection is conducted by the departmental officers to detect such cases of unauthorised raising of the outlets ?

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala):

(a) No.

(b) Question does not arise.

(c) Yes.

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मैंने मैन सवाल में जिन गांवों के नाम दिए हैं उन गांवों के मोघों का लैवल ऊंचा

कर दिया गया है, पहले उनका लैवल इतना ऊंचा नहीं था। क्या यह बात मंत्री जी नालेज में है, यदि ऐसा है तो उनका लैवल कब तक नीचा करवा दिया जाएगा ?

चौधरी भाम ॒ र सिंह ॒ सुरजेवाला: स्पीकर साहब, बहन जी ने आज तक मुझे इस बारे में नहीं बताया। मैं इस बारे में पता करवा लूँगा। मैं हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चकबन्दी एक्सीयन करता है। हर आउट लैट का एक फिक्सड एरिया होता है जिसको चक आफ दी आउट लैट कहते हैं। किसी आउट लैट को ऊंचा या नीचा करने का किसी जे०इ० या एस०डी०ओ० को अखित्यार नहीं है। एक्सीयन की आलट्रे टन को केवल एस०इ० चेंज कर सकता है वह भी सीजन के बीच में नहीं कर सकता यानि क्रौप की मैच्योरिटी के बाद हो सकती है। साल में दो बार कर सकते हैं। यदि किसी माननीय सदस्य की नालेज में यह बात हो कि कहीं पर किसी जे०इ०० या एस०डी०ओ० ने किसी आउटलैट का लैवल नीचा या ऊंचा किया है तो वह सरकार को बताएं उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती बसन्ती देवी: स्पीकर साहब, मैंने तो मैन सवाल में गांवों के नाम दे रखे हैं उनके सारे आउट लैट्स का लैवल ऊंचा कर दिया गया है। मंत्री जी इस बात की इन्कवायरी करवा लें, इनको पता लग जाएगा।

श्री अध्यक्षः मैडम, सारपे हरियाणा में जो माइनर्ज पक्के किए गए हैं, उनके आउटलैट्स का लैबल ऊंचा किया गया है।

श्रीमती बसन्ती देवीः स्पीकर साहब, इरीगे अन डिपार्टमैंट ने मेरे इलाके में किसानों को आऊट लैट्स द्वारा दो घंटे पानी देने का सिस्टम बनाया था और उसके हिसाब से किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं जबकि उनको दो घण्टे पानी नहीं मिला। अब 1985 के बाद वह सिस्टम बंद कर दिया गया है। लेकिन पिछले दो साल की दो घंटे पानी देने के हिसाब से किसानों से उगाही ली जाएगी। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जिन किसानों को आऊट लैट्स द्वारा दो घंटे पानी नहीं मिला क्या उनकी उगाही माफ की जाएगी ?

चौधरी भाम रेर सिंह सुरजेवालाः स्पीकर साहब, इनके एरिया में वोल्यूमनाइज्ड मीटर सिस्टम लगाया था। इरीगे अन डिपार्टमैंट ने घंटे के हिसाब से किसानों को पानी देने का एक नया तरीका एक्सपैरीमैंट के तौर पर भुरु किया था। वह सिस्टम इसलिए भुरु किया था ताकि किसानों से जितना पैसा लिया जाए उतना ही पानी उनको मिल जाए। लेकिन उस सिस्टम में हमने देखा कि उस एरिया में उससे किसानों को नुकसान हुआ इसलिए वह सिस्टम विद्वा कर लिया। इस समय मैं इस बारे में कोई आ वासन नहीं दे सकता कि जिन किसानों पर दो साल की उगाही लगा रखी है उसको माफ कर दिया जाए। क्योंकि किसानों ने आलरेडी पानी इस्तेमाल कर लिया है इसलिए वह पैसा माफ

नहीं किया जा सकता। आगे के लिए हमने सिस्टम को रिमूव कर दिया है। यदि बहन जी कोई डिटेल्ड बात बताएंगी तो उसको मैं एग्जामिन करवा लूंगा। आफ हैंड इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, अब सवालों का समय समाप्त होता है।

**नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों
के**

लिखित उत्तर

Stipend to internees of Ayurvedic Colleges in the State

***920 Sh. Mangal Sein:** Will the Minister of State for Health be pleased to state-the names of the Ayurvedic Colleges in the State where stipend is given to the Internees ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदा राज्य मंत्री (श्रीमती करतार देवी):

श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज कुरुक्षेत्र के विद्यार्थी डाक्टरों (इंटरनीज) को इंटरनीज अप के दौरान इंटरनीज अप भत्ता दिया जाता है।

Plying of Buses through village Dighal

***924. Ch. Om Parkash:** Will the Minister of State for Transport be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Haryana Roadways buses, plying from Rohtak to Beri, Dadri, Rewari, Gurgaon, Jhajjar, Kausli etc. thought village Dighal, have stopped operating through village Dighal for the last threee months; if so, the reasons therefor; and

(b) whether any complaingf has been recived about the hardship being caused to the public due to change of routes of the buses as referred to in part (a) above; if so, the action if any, taken thereon ?

परिवहन मंत्री (कर्नल राव राम सिंह):

(क) : जी हाँ, रोहतक चुंगी के समीप मेन सीवरेज कार्य निर्माणाधीन होने के कारण रोहतक-झज्जर मार्ग बन्द रहा।

(ख) जी हाँ, हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा सुचारू रूप से झज्जर रोड़ चुंगी, रोहतक से झज्जर तथा बेरी डीघल बस सेवायें प्रदान की जा रही थीं। अब पहले की भाँति दिनांक 11-3-85 से बस सेवा चलाई जा रही है।

Resumption of Residential Plots in Sector 14, Sonepat

***960. Sh. Devi Dass:** Will the Chief Minister of State for Public Health be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to provide drinking water facility in all the village in the State within the next tow years; if so, the amount of expenditure likely to be incurred thereon togetherwith the number of villages likely to be benefitted ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी): जी नहीं।

Provision of Electricity in Harijan Basties

***956. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether there are any Harijan basties in any villages, in district Sirsa, which have not been provided with electricity; and

(b) if so, the names of such villages togetherwith the reasons therefor ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ॒ र सिंह सुरजेवाला):

(क) : नहीं, सिरसा जिले में सभी 363 हरिजन बस्तियों का जिनमें 20 या इससे अधिक निवास स्थान हैं, उनका विद्युतीकरण कर दिया गया है।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

Repair of Roads constructed by Agricultural Marketing Board

***976. Master Ram Singh:** Will the Chief Minister of State be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair such damaged roads

as were constructed by the Agricultural Marketing Board during the last ten years; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) तथा (ख) गत दस वर्षों में कृषि विपणन मंडल ने अपने निर्माण सैल अथवा हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) द्वारा सड़कों का निर्माण करवाया है। क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत समय समय पर, जब आव यकता होती है, करवाई जाती है।

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

श्री हीरा नन्द आर्य: अध्यक्ष महोदय, थर्मल प्लांट की बात को लीजिए या दूसरी बातों को लीजिए, सरकार ने पिछले दिनों स्लैक कौल का डिस्ट्रिब्यू अन किया है। फूड एण्ड सप्लाईज डिपार्टमेंट ने एक पत्र लिखा है। मैंने इस बारे में नोटिस भी दिया है। उस पत्र में फर्मों के नाम लिखे हैं कि किन पार्टी को हरियाणा सरकार ने 1985 के लिए कौल दिए जाने के बारे में कहा है। इस बारे में सरकार ने अचानक अपनी नीति में परिवर्तन करके कुछ हिसार के और एक दो दिल्ली के आदमियों को ही मुख्य रूप से फायदा पहुंचाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे कि यह नीति अचानक क्यों बदली गई है? इसमें लाखों और करोड़ों रूपये का घपला है और यह

एक सनसनीखेज बात है। मैंने इसके बारे में काल अटें अन मो अन भी दिया है।

श्री अध्यक्षः आप का नोटिस अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है। जब पहुंचेगो तो मैं उस पर विचार कर लूंगा।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, दो दिन पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें लिखा है कि 17 महीने से चौधारी हरद्वारी लाल नाजायज तौर पर, जबरन वाइस चांसलर का काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः वैसे तो इस बारे में मैंने गवर्नर्मैंट के कमैंटस मांगे हैं लेकिन यह बात अखकार में आ गई है कि वहाँ पर नैकस्ट सीनियर मोस्ट प्रोफैसर को कह दिया गया है कि वह वाइस चांसलर का काम करे।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, हमारी इतलाह यह है कि अभी भी उन्होंने आफिस नहीं छोड़ा है। उन्होंने एक दरख्वास्त अपील के लिए दी थी जो हाई कोर्ट ने मंजूर नहीं की।

श्री अध्यक्षः दहिया साहब आप बैठिये। मैंने पहले ही कह दिया है कि इस पर मैंने गवर्नर्मैंट के कमैंटस मांगे हैं।

Sh. Mangal Sein: Sir, I have given notices of two motions today under Rule 73 of our Rules of Procedure. स्पीकर साहब, महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में

हाई कोर्ट ने जजमैंट दिया है कि सरकार ने उनकी अप्वायन्टमैंट गलत की है। ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। (विधन)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, मुझे भी अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय दिया जाये। (विधन)

श्री अध्यक्ष: पहले डा० साहब को अपनी बात खत्म कर लेने दें। इनके बाद आप बोल लें।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, ये तो उसमें पार्टी भी नहीं हैं। यह काम तो चांसलर साहब का है कि वे सुप्रीम कोर्ट में जायें। ये सुप्रीम कोर्ट में जायें यह बड़ी इल्लीगत बात है। अखबार में छपा है कि सरकार की छवि खराब है और इसकी मिटटी खराब हो रही है। इस समय हाउस चल रहा है। हमने मो अन के जरिए आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। यदि हम यह मुद्दा नहीं उठाएंगे तो हमारे पार्ट पर यह बहुत गलत होगा।

श्री अध्यक्ष: डा० साहब आप बैठिये। इस बारे में अब सी०एम० साहब कुछ कहना चाहेंगे।

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, डा० साहब बहुत पुराने मैम्बर हैं। ये अपने आपको बड़े काबिल मैम्बर समझते हैं। स्पीकर साहब, ये यह कहें कि कोई आदमी सै अन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों जायें, या हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाये, यह कहना ठीक नहीं है।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, चांसलर साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये क्यों जाते हैं ?

चौधरी भजन लाल: चांसलर सासहब भी जा सकते हैं और सरकार भी जा सकती है। सरकार जो कोई आदमी अप्वायंट करती है उसके लिए अदालत के दरवाजे खटखटा सकती है।

श्री मंगल सैन: आपने उसको अप्वायंट नहीं किया।

चौधरी भजन लाल: भुरु में तो आपने ही उनकी अप्वायन्टमैंट की थी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, यह ठीक है कि उनकी अप्वायन्टमैंट 1977 में हुई थी। Even then this was done by the Governor. Please guide him. This will be wrong that Government should in this case go to the Supreme Court against the Judgement of the High Court.

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, हमने एक अमैंडमैंट की थी उस अमैंडमैंट को हाई कोर्ट ने नहीं माना। सरकार का यह फर्ज है कि वह अपनी की हुई अमैंडमैंट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमारी अमैंडमैंट को सुप्रीम कोर्ट मान या न माने यह सुप्रीम कोर्ट का काम है। दूसरे अध्यक्ष महोदय, दहिया साहब खुद वहां पर रजिस्ट्रार रहे हैं। इनको पता है कि जब कोई वाइस

चांसलर हट जाता है तो यूनिवर्सिटी का जो सीनियर मोस्ट प्रोफैसर होता है। वह आटोमैटिकली एकिटंग बाइस चांसलर का काम करना भुरू कर देता है। इस बारे में यूनिवर्सिटी के बाकायदा कानून बने हुए हैं कि सीनियर मोस्ट प्रोफैसर वाइस चांसलर के न रहने पर काम करेगा। इसमें किसी की अप्वायंटमैंट करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में एम०डी०य० का जो एकट बना हुआ है, उसमें यह प्रोवीजन है।

श्री हीरा नन्द आर्यः हम यह जानना चाहते हैं कि किस व्यक्ति ने वहां पर वाईस चांसलर के काम को टेक ओवर किया है ? (विधन)

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जजमैंट आई है उसमें सरकार की अमैंडमैंट के बारे में कुछ नहीं है। वहां पर वाइस चांसलर को चांसलर ने अप्वायंट किया था। इसमें सरकार ने कुछ नहीं किया था। बहरहाल अब जो अपील हो वह चांसलर की तरफ से हो न कि सरकार की तरफ से। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करती है तो इसका मतलब यह है कि सरकार यूनिवर्सिटी के मामलों में दखल दे रही है। इस बारे में चांसलर ही सब कुछ हैं। अब इन द्वारा चांसलर पर दबाव डाला जा रहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में जायें। दूसरी बात इन्होंने ठीक फरमाई है कि जब वाइस चांसलर हट जाता है तो उसकी जगह वहां का जो सीनियर मोस्ट प्रोफैसर होता है वह काम करता है। मैं जानना चाहता हूं कि

क्या आज कल वहां पर चौधारी हरद्वारी लाल जी काम कर रहे हैं या किसी और की चाज़ दे दिया गया है ? यदि चार्ज किसी और को दिया गया है तो किस को दिया गया है ?

चौधारी भजन लाल: स्पीकर साहब, यह बाकायदा नियम बने हुए हैं कि जो सीनियर मोस्ट प्रोफैसर होगा वह वाइस चांसलर के ना रहने पर काम करेगा। इसमें सरकार को कोई दखल नहीं है कि किस ने चार्ज लिया है या किस ने नहीं लिया। इस बारे में तो चांसलर साहब ही बता सकते हैं कि किसने चार्ज लिया हैं मैं पहले ही बता चुका हूं कि एम०डी०य०० के एकट के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट प्रोफैसर होगा वह वहां पर एकिटंग वाइस चांसलर हो जाता है। मेरे ख्याल में अब वहां पर सबसे सीनियर मोस्ट प्रोफैसर श्री निगम हैं।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था लेकिन बीच में सी०एम० साहब ने इन्ट्रप्ट करना भुरु कर दिया। इन द्वारा इन्ट्रप्ट करने पर आप भी मजबूर हो गए।

श्री अध्यक्ष: चीफ मिनिस्टर साहब ने आपकी बात का जवाब देना था इसलिए ये बोलने के लिए खड़े हुए थे। जहां तक मेरी मजबूरी की बात है वह मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल भी मजबूर नहीं हुआ क्योंकि इसमें मजबूरी वाली कोई बात ही नहीं थी।

श्री मंगल सैन: स्पीकर साहब, आज के पंजाब के सभी अखबार में कौन त्या देवी के बारे में एक फोटो छपा है इस फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि 'मैं क्या चाहती हूं इन्साफ'। (विधन) स्पीकर साहब, इसमें आगे लिखा है कि एस०एस०पी० लखीराम तथा राम सिंह डी०एफ०एस०ओ० की धक्के आही बन्द करो। मैंने इस बारे में आपको एक काल अटैं अन मो अन भी दिया हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे उस काल अटैं अन मो अन का क्या बना है ?

श्री अध्यक्ष: आपका काल अटैं अन मो अन मेरे पास आ गया है। मैं उसको कंसिडर करूँगा।

चौधरी नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, आज अखबार में खबर आई है कि गेहूं का भाव 157 रुपये पर किवंटल फिक्स हुआ है। अब बस के और रेल के किराये पहले की अपेक्षा बढ़ गए हैं। दूसरे हरियाणा सरकार ने भी अब बजट के अन्दर बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं जिससे किसानों के खर्च पहले की अपेक्षा काफी बढ़ जाएंगे।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला): बिजली का कोई खर्च नहीं बढ़ा है।

चौधरी नर सिंह ढांडा: आपने 2, 3 तथा 4 पैसे यूनिट बढ़ा तो दिए हैं। (विधन) यह बात ठीक है कि गेहूं का भाव तो सैट्रल सरकार ने निर्दि चत करना है लेकिन मैं यह चाहता हूं कि

हरियाणा सरकार अपनी तरफ से किसानों को कुछ बोनस आदि के रूप में राहत दे और इस बारे में मुख्य मंत्री जी हाउस के अंदर ही कोई स्टेटमेंट दें।

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले साल गेहूं का भाव 152 रुपय प्रति किंवंटल था। इस साल भारत सरकार ने 5 रुपये प्रति किंवंटल एकदम बढ़ा कर 157 रुपये प्रति किंवंटल कर दिया है। (व्यवधान) आप सुनने की कृपा करें। इसके लिए भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के हित को ध्यान में रखा है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल बिजली का है। ये कहते हैं कि बिजली के रेट्स बढ़ा दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि बिजली का कोई रेट नहीं बढ़ाया, किसी भी कंज्यूमर से एक पैसा भी चार्ज नहीं होगा। 2, 3, 4 पैसे प्रति यूनिट जो डयूटी बढ़ाई है, इसमें बिजली बोर्ड के साथ आपस में एडजस्टमेंट की बात है। किसी भी कंज्यूमर से एक भी पैसा बढ़ा हुआ वसूल नहीं किया जाएगा, यह डयूटी बिजली बोर्ड से एडजस्ट की जाएगी, यानी ली जायेगी।

चौधरी नर सिंह ढांडा: स्पीकर साहब, बसों के भाडे बढ़े हैं, यह कितन परसेंट बढ़े हैं? मुख्य मंत्री जी यह भी बता दें। (व्यवधान) इसके अलावा मैंने एक काल अटैं टन मो टन का नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्षः जिस वक्त वह मेरे पास पहुंचेगा, मैं उसे कंसिडर करूंगा।

चौधरी कुलबीर सिंह मलिकः स्पीकर साहब, भाखडा नहर में जो ब्रीच हुई थी, उसके बारे में मेरा एक काल अटैं आन मो आन था। उस ब्रीच से सिरसा, हिसार और जींद जिले अफैक्ट हुए हैं। वहां पर कम्पनसे आन देने के लिए यह मेरा मो आन था।

श्री अध्यक्षः मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं।

नेमिंग आफ मैम्बर

श्री मनफूल सिंहः स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सरकार का ध्यान पानीपत थर्मल प्लांट की तरफ जिसका जिक्र कल भी चला था, दिलाना चाहता हूं। इस प्लांट में बिजली कम बनती है और इसका कारण यह है कि इसमें ठीक ढंग से काम नहीं हो रहा। वहां 15 डिप्लोमा होल्डर्ज पिछले 4 साल से दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। इसी तरह 65 डिप्लोमा होल्डर्ज से 5-6 साल से असिस्टेंट आप्रेटर के रूप में काम लिया जा रहा है जबकि वे पूरे जेऽई० हैं।

श्री अध्यक्षः इस बात का जवाब कल दे दिया गया था। अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य ने अपनी सीट ग्रहण नहीं की)

श्री मनफूल सिंह: कल इसका पूरा जवाब नहीं आया था। इसके बारे में मैंने काल अटैं टन मो टन भी दिया है। स्पीकर साहब, इन जे.ई.जे.ओ के साथ अन्याय किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपके दो काल अटैं टन मो टन मिल चुके हैं। I will consider them. अब आप बैठिए।

श्री मनफूल सिंह: वह तो ठीक है लेकिन इससे पहले सरकार जवाब दे, जे.ई.जे.ओ के साथ अन्याय हुआ है, यह बहुत बुरी बात है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइए, नहीं तो मुझे आपको नेम करना पड़ेगा।

श्री मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी बात सुन ली है। आप बैठ जाइए, otherwise I will name you.

(The hon. Member still did not resume his seat)

Mr. Speaker: I name Shi. Manphool Singh. वे मेरबानी करके बाहर चले जायें। (व्यवधान)

(The Hon. Member did not leave the House)

श्री अध्यक्षः आप बाहर चले जाएं, वरना मुझे आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा।

(The Hon. Member still did not leave the House)

श्री अध्यक्षः सार्जेन्ट, इनको बाहर ले जाओ। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रावतीः स्पीकर साहब, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: This is not good. Please do not interfere in this matter. इनका रोज का ही ऐसा एटीच्यूड हो गया है। (व्यवधान)

(The Serjeant-at-Arms went to the Hon. Member but he persisted in not leaving the House.)

Mr. Speaker: Throw him out.

श्रीमती चन्द्रावतीः यह बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)
You cannot say like that. (व्यवधान) स्पीकर साहब, वे आपसे माफी मांग सकते थे।

Mr. Speaker: You want to create interference in the compliance of my orders.

(The hon. Member, Sh. Manphool Singh still did not leave the House)

Mr. Speaker: This attitude is really not good. Serjeant, throw him out.

Ch. Balvir Singh Grewal: Speaker, Sir.....

Mr. Speaker: Mr. Grewal, please take your seat.

(At this stage the Serjeant-at-Arms escorted the hon. Member Sh. Manphool Singh, to the opposition lobby).

वाक—आउट

Sh. Mangal Sein: I am very sorry to hear from your mouth, Sir, that the member should be thrown out from the House.

Mr. Speaker: Yes, he is a member who always creates indiscipline. I cannot tolerate it.

Sh. Mangal Sein: You may mis-hear him.
(Interruptions & noise)

Mr. Speaker: I have named him. I have been observing for the last three-for days that he is creating indiscipline.

Sh. Mangal Sein: Speaker Sir, you language is highly derogatory.

Mr. Speaker: I understand the language.

Sh. Mangal Sein: As a protest, we walk out.

(At this stage all the members of the opposition staged a walk out).

वक्तव्य—

सिंचाई तथा बिजली मंत्री द्वारा कैनाल वाटर की न्यू रोटे अन पालिसी संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice from the Irrigation & Power Minister for making a statement about new rotation of canal water in view of steep fall in water from Yamuna river. He can now make a statement.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, इस समय सारा उत्तरी भारी सूखे के दौर से गुजर रहा है। हरियाणा प्रान्त भी इसके प्रकोप से प्रभावित हुआ है। 1984 तथा 1985 की सर्दियों में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई है और 1984 में मौनसून वर्षा भी कम हुई है। इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में हिमपात भी बहुत कम हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में भाखड़ा बांध में पानी का स्तर साधारण सालों के मुकाबले में 40 फुट कम रहा है जिसके कारण भाखड़ा से पानी का रिलीजिज कम होने के कारण सिंचाई व बिजली के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। भाखड़ा से पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगभग 6000 क्यूसिक पानी की रिलीजिज कम रही है और भाखड़ा बांध में पानी की कमी व लैवल नीचा होने के कारण हरियाणा को बिजली की उपलब्धि पिछले महीनों में 30 लाख यूनिट प्रतिदिन कम रही है।

उपरोक्त सूखे वातावरण से जमुना भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और जमुना से हरियाणा को पानी की उपलब्धि

साधारण सालों के मुकाबले में 2000 क्यूसिक कम रही हैं। पिछले दिनों में जमुना के पानी में इतनी भारी कमी हुई है कि हरियाणा का हिस्सा घट कर केवल 1300 क्यूसिक ही रह गया है जो पिछले 40 सालों के उपलब्ध रिकार्ड में 2000 क्यूसिक से कभी कम नहीं हुआ।

दिसम्बर 1984 तक तो भाखडा व जमुना से सिंचित इलाकों में नहरी पानी की रोटे अन साधारण सालों की तरह चलाने का भरसक प्रयत्न किया गया, परन्तु जनवरी 1985 से पानी की मिकदार बहुत कम होने के कारण जमुना से सिंचित इलाकों में पानी की रोटे अन तीन गुपों की बजाये चार गुपों में चलानी पड़ी।

मई 1984 से जनवरी 1985 तक जे०एल०एन० व लोहारू लिफट को 97 दिन के लिये 63828 क्यूसिक पानी दिया गया। यह पानी भाखडा व जमुना से दिया गया है। इस पानी की कमी का प्रभाव गुड़गांव नहर के इलाकों पर भी कुछ दिन के लिये पड़ा है। इसलिए फरवरी 1985 में इन लिफट नहरों को पानी नहीं दे सके।

जमुना व भाखडा से पानी की उपलब्धि न्यूनतम होने के कारण हरियाणा के भाखडा के इलाकों में जहां नहरें दो गुपों में चलती थीं, से पानी लेकर जमुना से सिंचित होने वाले इलाकों को पानी दिया जायेगा ताकि चार गुप सिस्टम चल सकें और उसके फलस्वरूप भाखडा के इलाकों में दो गुप की बजाय चार

गुप सिस्टम में पानी दिया जायेगा। इसका स्पश्ट भाब्दों में यह अर्थ हुआ कि यमुना के इलाकों की भाँति भाखड़ा के इलाकों में भी 8 दिन नहरें चलेंगी और 24 दिन बन्द रहेंगी। यह नई रोटे तन भाखड़ा के इलाकों में 20 मार्च से भारूल होने वाली रोटे तन पर लागू की जा चुकी है और भाखड़ा के इलाकों में रोटे तन से दिया जायेगा। परन्तु टोहाना से डाउन स्ट्रीम के भाखड़ा के इलाके तीन गुपों में चलाये जायेंगे जिसका अर्थ यह हुआ कि 8 दिन पानी चलेगा और 16 दिन बन्द रहेगा।

16 जनवरी 1985 से टयूबवैलों को न्यूनतम 6 घंटे प्रतिदिन बिजली देने का प्रावधान किया गया है और इसी बीच में समय समय पर टयूबवैलों को 12 घंटे तक बिजली उपलब्ध होती रही है। सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि फसल पकाई, कटाई व अगली फसलों की बिजाई के लिए सरकार बिजली देने के लिए वचनबद्ध है। इसी समय में पेयजल सप्लाई स्कीमज के लिए व घरों में रो नी व अनिवार्य सेवाओं को चलाने के लिये भी बिजली दी गई हैं। गर्भी की ऋतु को देखते हुए आज से एक हफ्ता पहले पीने के पानी के घंटे सवेरे के समय 2 से 3 व दोपहर को 1 से 3 घंटे तक बढ़ा दिये गये हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में जो देहाती व भाहरी वाटर सप्लाई स्कीमज नहरी पानी पर आधारित हैं और गांव के तालाब जहां मवे भी पानी पीते हैं, को नहरी पानी से भरने के लिये जन स्वास्थ्य विभाग, जिला अधिकारियों व नहर के अधिकारियों को

हिदायतें दे दी गई हैं, जिससे वह वाटर टैक्स तथा तालाबों में पानी भर सकते हैं।

उपरोक्त रोटे अन मई के पहले सप्ताह तक के लिये बनाई गई है। इसके प्रचात ऊपरी पहाड़ियों में बर्फ पिघलने से यमुना व भाखड़ा में पानी की मात्रा बढ़ने पर यमुना के इलाकों को पिछले सालों की तरह तीन ग्रुपों में तथा भाखड़ा के इलाकों को दो ग्रुपों में चलाये जाने की उम्मीद है ताकि किसान कपास, चरी आदि की फसलों को कात कर सकें।

स्पीकर साहब, यह स्टेटमैंट देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि 20 तारीख से जो रोटे अन भुर्ल हुई है उससे केवल 8 दिनों के लिए पानी चलेगा और कहीं ऐसा न हो कि लोग गर्मी के दिनों में वाटर टैक्स और तालाबों आदि में पानी न भर सकें। हालांकि सरकार ने अपने तौर पर डिस्ट्रिक्ट अथारटीज को और दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों को इत्तलाह दी है फिर भी हाउस के समुख मैं सरकार की तरफ ले एक बात कहना चाहता हूँ क्योंकि मैम्बर साहैबान आज दो दिन के लिए अपने अपने हल्के में जाएंगे और ये लोगों को बता सकते हैं कि पानी की भारी कमी है इसलिए पीने के पानी को जितनी देर नहर का पानी चलेगा, प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि पीने के पानी की मवे भी और इन्सान को कोई दिक्कत न हो।

श्री हीरा नन्द आर्यः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। ...

.....

Mr. Speaker: This is no point of order. It will not come on recore.

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रुलिंग चाहता हूँ।

Mr. Speaker: I have given the ruling. This is no point of order. Sh. Bhagi Ram.

श्रीमती चन्द्रावतीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

Mr. Speaker: I have not called you. I have called Sh. Bhagi Ram.

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं प्वायंट आफ आर्डर पर हूँ।

Mr. Speaker: No please. You please sit down. Sh. Bhagi Ram.

विभिन्न विशयों का उठाया जाना (पुनरारम्भ)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैंने एक काल अटैं अन मो अन दिया है। सिरसा जिले में जितने बारानी गांव हैं उनमें पानी नहीं लगता। वहां चने की फसल खत्म हो गई है।

श्री अध्यक्षः मैं उसको कंसीडर कर रहा हूँ।

चौधरी ओम प्रकाश: स्पीकर साहब, मैंने भी एक काल अटै अन मो अन दिया था। वह स्लैक कोल की डिस्ट्रिब्यू अन में स्कैन्डल के बारे में था।

श्री अध्यक्षः वह बात हो गई है। उसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मेरा भी एक काल अटै अन मो अन था। वह कवैरीज के बारे में था।

श्री अध्यक्षः वह डिसअलाऊ हो गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, वह तो गवर्नर्मैंट की पालिसी के बारे में था।

श्री अध्यक्षः उसके डिसअलाऊ करने के मैं अभी आपको रीजन्ज बता देता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंहः रीजन्ज तो ठीक ही होंगे क्योंकि आप एक बढ़िया वकील भी हैं लेकिन मेरी सबसि अन यह है कि वह सरकार के पालिसी मैटर के बारे में था। अखबारों में खामखाह की बात चलती रहती है। अगर गवर्नर्मैंट की तरफ से बात साफ हो जाती तो लोग एनलाइटेंड हो जाते।

श्री अध्यक्षः वह डिसअलाऊ हो चुका है। I have announced it.

नेम किए गए मैम्बर को सदन से बाहर भेजने की घटना का

प्र न उठाना ।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मेरी एक सबमि अन और है। यह बड़े दुःख की बात है यदि आपके भाब्द के ऊपर हमें वाक आउट करना पड़े। मुझे तो लगता है कि आपकी भी वैसा कहने की इंटे अन नहीं थी बल्कि स्लिप आफ टंग से वह भाब्द निकल गया। (विधन) स्पीकर साहब, थो भाब्द कुछ ठीक नहीं क्योंकि आप तो जानते हैं कि आदमी तो आदमी है। That is not a commodity. इसलिए मैं गुजारि । करुंगा कि वह भाब्द यदि ऐक्सपंज हो जाए तो बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष: चौधारी वीरेन्द्र सिंह जी, आप देख रहे हैं कि जितना लैटिच्यूड मैं देता हूं इतना कोई दे नहीं सकता। मैं यह सोचता हूं कि चलो ये मजाक कर रहे हैं इन्हें करने दो लेकिन आप महसूस करेंगे। Is it the duty of the Speaker to always ask the leader of the Opposition to make a member to sit ? He always disobeys the order. तीन चार दिनों से बात चलती आ रही है। So I will not withdraw any word.

श्री वीरेन्द्र सिंह: आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन हमें तो आपके भाब्द पर वाक आउट करना पड़ा।

श्री अध्यक्ष: यह आपका हक है। मैं आपको रोक नहीं सकता।

श्री वीरेन्द्र सिंह: परन्तु स्पीकर सर, आपके मुंह से थोड़ा बाब्द कहना नहीं ज़ंचता।

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, मैं आपको अब योर करवाती हूं कि आपको खिलाफ हम जरा सी भी डिस्कर्टसी भाओ नहीं करना चाहते लेकिन सरकार जब ज्यादती करती है तो उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना हमारा फर्ज बनता है। मैं यह मानती हूं कि अभी जो कुछ हुआ वह ठीक नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: एक बात मुझे दुःख से कहनी पड़ती है कि एक मैम्बर का रवैया डैरोगेटरी हो लेकिन सारे मैम्बर देखते हुए भी यह न कहें कि वह गलत कह रहा है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी जो बात आपने कही, मैं उससे इसलिए ऐसी नहीं करता क्योंकि मैं पिछले तीन चार दिन से देख रहा था कि उनका रवैया ठीक नहीं था।

डा० भीम सिंह दहिया: स्पीकर साहब, मेरी सबसे अब यह है कि हम गलती महसूस कर रहे थे कि उन्होंने आपको ओबे नहीं किया। उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। मैं चीफ व्हीप० के नाते उनके पास जा ही रहा था ताकि उन्हें बाहर भेजूं लेकिन आपने हुकम दे दिया कि throw him out. स्पीकर साहब, लगता है कि आपसे यह स्लिप ऑफ टंग हो गई।

Mr. Speaker: It is not a slip of tongue. I had to say it after seeing the behaviour of the Member. His behaviour has been derogatory for the last three/four days.

डा० भीम सिंह दहिया: आपके मुंह से यह बात भांभा नहीं देती।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, आप बहुत खु ा असलूबी से हाउस चला रहे हैं। मैं यह भी महसूस करता हूं कि मैम्बर की गलती है लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप थ्रो भाब्द की जगह रीमूव भाब्द इस्तेमाल कर लें तो बेहतर रहेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है थ्रो की जगह रीमूव कर लें।

श्री लछमन सिंह: स्पीकर साहब, मेरी अपील यह भी है कि उसको बुला भी लें क्योंकि उसे बड़ी सजा मिल गई है।

Mr. Speaker: No please.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अपोजी ान के माननीय सदस्यों के जो नेता हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आपने जब उस सदस्य को बाहर जाने के आदे ा दिए तो मा लि को रोकने के लिए इनके कुछ सदस्य उस मैम्बर के पास गए। (विधन) जब मा लि उन्हें बाहर ले जाने की कोर्ट ा कर रहा था तो इनके कुछ सदस्य उन्हें वहां बिठा रहे थे। (विधन) यह बड़ी गलत बात है। फिर अध्यक्ष महोदय उसके बाद ये हाउस में नहीं ठहरो बल्कि आपकी रूलिंग के खिलाफ प्रोटैस्ट करके बाहर चले

गए। इसके बावजूद भी अब ये डिमांड कर रहे हैं कि आप अपने भाव्द वापस ले लें। (विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंह: हमने थो भाव्द पर वाक आउट किया था।

श्रीमती चन्द्रावती: आप स्पीकर साहब, को प्रोवोक करना चाहते हैं।

चौधरी भाम ॑ और सिंह सुरजेवाला: मैं कोई प्रोवोक नहीं करना चाहता। मैं तो इतना अर्ज करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब, की अगर आप इज्जत करते हैं तो इधर वाले भी बहुत इज्जत करते हैं। सारे हाउस को ही इनकी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि जिस लैटिच्यूड से जिस कंसिलिए न से ये हाउस को चला रहे हैं इससे ज्यादा और कोई चला नहीं सकता, लेकिन स्पीकर साहब, भी एक इन्सान हैं। जब एक मैम्बर बार बार डिफार्ड करेगा और बाकी मैम्बर्ज का ऐटीच्यूड ऐसा होगा तो आप लोगों को ऐसे मैम्बर्ज को समर्थन नहीं देना चाहिए और न ऐसी सिचुए न क्रिएट करनी चाहिए जैसी अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी।

बिल्ज (इन्ट्रोड्यूस्ट—सदन की अनुमति से)

(1) दि पंजाब लैंड रैवेन्यू हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल को इंट्रोडयूस करने के लिए हाउस से परमि अन लेंगे।

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर साहब, मेरी महेन्द्रगढ म्यूनिसिपल कमेटी के सम्बंध में एक काल अटै अन मो अन थी और आपने कहा था कि आप उसे देख रहे हैं।

Mr. Speaker: That stage has passed now. We will talk in this regard on Monday.

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill, 1985.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल 1985 को इंट्रोडयूस करने की परमि अन दी जाए।

11.00 बजे।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, ये जो अमैंडमेंट लाये हैं। यह इसलिए लाये हैं कि गवर्नरमैंट सर्वेंटस से डयूज की रिकवरी एक एरियर्ज आफ लैंण्ड रैवेन्यू की जाये। स्पीकर साहब, आपको यह बताने में मेरी कोई गुस्ताखी नहीं होगी कि तहसीलदार लोगों को किस तरह से बान्ध कर रखते हैं, यह किसी

से छिपी हुई बात नहीं है। चौधरी भजन लाल जी ने तो कोआप्रेटिव सोसाइटीज एकट में सं पोधन कर दिया है। बेचारे बूढ़े बुजुगाँ को दफतरों में बान्धा कर रखते हैं, उन्हें जलीज करते हैं। इन्होंने इसकी स्टेटमैंट आफ औबजैक्स एंड रीजन्ज में लिखा है –

“With a view to find out Ways and Means (including legislative measures) for recovery of amounts embezzled by Government Servants expeditiously, it has been decided to carry out an amendment in the Punjab Land Revenue Act, 1887 enabling the Government to recover the embezzled amount from the concerned Government employees as arrears of Land Revenue.”

इसका मतलब यह है कि एम्पलाइज ने एम्बैजलमैंट बड़ी हाई स्कैल पर करनी भुरु कर दी है और ये उनसे नार्मल प्रोसीजर में पैसा ले नहीं पाते हैं। इसलिए ये 1887 के इस एकट में अमैंडमैंट करना चाहते हैं। अब ये गवर्नर्मैंट एकपलाई से इस तरीक से रिकवरी करेंगे। स्पीकर साहब, नार्मल कोर्स से पैसा वसूल होना चाहिये। इस अमैंडमैंट को लाने की क्या आव यकता है। मैं इसे अनाव यक समझता हूँ। यह इनकी कनफै अनल स्टैटमैंट है कि एम्बैजलमैंट बढ गई है। इनकी देखा देखी उन्होंने भी भुरु कर दी है। इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहूँगा कि यह बिल मूव नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम ोर सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, यह स्टेज डिस्क अन की नहीं थी।

अगर इनको इस बारे में कोई टैक्नीकल या प्रोसीजरल बात कहनी थी तो बिल की कंसिड्रे अन के टाईम पर कह सकते हैं। मैं बिल को इन्ट्रोडयूस करने से पहले बताना चाहता हूं कि पंजाब लैंड रैवेन्यू एकट, 1887 की सैक अन 98 जो है उसमें बहुत सी बातें हैं कि कौन कौन से आइटम्ज और कौन कौन सी रकम सरकार इस तरह से वसूल कर सकती है। यह तरीका उसी सूरत में अखित्यार किया जाता है जब नार्मल तरीके से रिकवरी न हो। हम इसमें एक बात और डालना चाहते हैं कि जो आदमी सरकारी नौकरी में होते हुए एम्बैजलमैंट कर जाते हैं उनसे रिकवरी नार्मल तरीके से हो नहीं पाती बल्कि कई आदमी तो रिटायर भी हो जाते हैं, उसके बाद बड़ी मुफ्त कल होती है। ऐसे केसिज में जहां एम्बैजलमैंट सर्विस के दौरान की हो उनसे रिकवरी लैण्ड रैवेन्यू के तौर पर कर सकें। इसलिए यह अमैंडमेंट लानी बहुत जरूरी है और समय के मुताबिक है। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्षः प्रभु न है कि—

कि पंजाब लैंड रैवेन्यू (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल 1985 को इन्ट्रोडयूस करने की परमि अन दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर सहब बिल इन्ट्रोडयूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewal): Sir, I introduce the Bill.

(2) दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने के लिए हाउस से परमि अन लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Payment of Wages (Haryana Amendment) Bill, 1985.

स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सैंट्रल एक्ट 4 आफ 1936 की सैक अन 15 में सरकार इस बात का प्रावधान करना चाहती हूँ कि राज्य सरकार किसी भी मामले को एक अथौरिटी से दूसरी अथौरिटी को ट्रांसफर कर सकती है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने की परमि अन दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि पेमैंट आफ वेजिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने की परमि अन दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोड्यूस करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher

Singh Surjewal): Sir, I introduce the Bill.

(3) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमैंडमेंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्ट्रावेड्यूस करने के लिए हाउस से परमि अन लेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher

Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1985.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्ट्रावेड्यूस करने की परमि अन दी जाये ।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं आपकी रुलिंग चाहूंगा कि अगर कन्सन्ड मिनिस्टर उपस्थित हों उसके बावजूद भी क्या उस बिल को दूसरा मिनिस्टर इन्ट्रोड्यूस कर सकता है ?

श्री अध्यक्षः यह पार्लियामैंट की कनवैन अन है कि पार्लियामैंटरी अफयर्ज मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर भी उस बिल को इन्ट्रोड्यूस / मूव कर सकते हैं ।

प्र न है कि—

दि हरियाणा (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्ट्रावेड्यूस करने की परमि ान दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इन्ट्रोड्यूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewal): Sir, I introduce the Bill.

(4) दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्ट्रावेड्यूस करने के लिए हाउस से परमि ान लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1985.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्ट्रावेड्यूस करने की परमि ान दी जाये।

श्री अध्यक्ष: प्र न है कि—

दि हरियाणा जनरल सैल्ज टैकस (अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने की परमि अन दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब बिल इन्द्रोड्यूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewal): Sir, I introduce the Bill.

(5) दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1985

श्री अध्यक्ष: अब मिनिस्टर साहब दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने के लिए हाउस से परमि अन लेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move-

That leave be granted to introduce the Punjab Panchayat Samitis (Haryana Amendment) Bill, 1985.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने की परमि अन दी जाये।

चौधरी ओम प्रकाश (बेरी): अध्यक्ष महोदय, जो पंजाब पंचायत समितिज हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1985 मूव किया है इसमें क्लाज दो के द्वारा ये अमैंडमैंट करना चाहते हैं। इसके

मुताबिक इस बिल का पर्ज बिल्कुल अन डैमोक्रेटिक हो जाये गा। गवर्नमैंट को बेजा तरीके से लोगों को नौमीनेट करके पंचायत समितिज पर कब्जा करने की पावर्ज दी जा रही हैं, जो बिल्कुल अन डैमोक्रेटिक हैं। इससे तो बेहतर यह होता कि पंचायत समिति के किसी गांव को दूसरी पंचायत समिति में मिलाने के लिए या एक पंचायत समिति से किसी गांव को निकालने का प्रोसैस पंचायत समिति की कांस्टीच्यू न से बहुत पहले हो जाना चाहिए और जो डिलीमिटेटिड ब्लौक्स हैं पंचायत समितियों के उसके आधार पर चुनाव होने चाहिए। यह एक तरीका है। अगर इनको पावर्ज दे दी गई तो उसके आधार पर जब चाहें किसी गांव को निकाल कर अपने मैम्बर को पंचायत समिति में नौमीनेट करके उस पंचायत समिति पर अपना अधिकार एकदम कर सकते हैं। इस कारण से यह जो अमैंडमैंट करना चाहते हैं यह गलत है। यह बिल मूव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस बिल से गवर्नमैंट को ऐसी पावर्ज मिल जायेंगी जो बिल्कुल अन डैमोक्रेटिक होंगी और उनका सरकार द्वारा नाजायज इस्तेमाल किया जाये गा।

श्री मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, यह जो अमैंडमैंट लाए हैं यह अन डैमोक्रेटिक है। Its Statement of Objects and Reasons reads as under :-

“This Bill seeks to provide to make up the deficiency of the Primary Members by nomination in the re-delimited block during the course of the electoral process for constituting Panchayat Samitis”.

सरकार की इसके मुताबिक कितनी गलत नीयत है। ये बाई नौमीने अन ही काम करना चाहते हैं। इनका बस चले तो असैम्बली में भी नौमीनेट कर दें। जिला परिशद नहीं बनाई है वरना उसमें भी कर दें। चीफ मिनिस्टर साहब को पता है कि इनके आगे पीछे लोग लगे रहते हैं कि हमारा आदमी नौमीनेट कर दीजिए। ये लोग क्या तमा आ करते हैं कि कलानौर के एस०एच०ओ० से इन्होंने एक आदमी की पिटाई करवाई जो इनकी बात नहीं मानता था। इस बात को मैं एस०पी० साहब के नोटिस में लाया हूं। बेरी ब्लॉक का चुनाव होना था। (व्यवधान व भाओर)

श्री अध्यक्ष: डाक्टर साहब, आप एस०एच०ओ० को इस अमैंडमेंट के साथ कैसे जोड़ रहे हो ?

श्री मंगल सैन: इसलिए जोड़ रहा हूं कि यह बहुत ज्यादा धांधलियां करते हैं और यहां पर आकर नौमीने अन का अखित्यार मांग रहे हैं। जब लोग इनके बस में न रहें तो पुलिस के जरिए पिटवा कर अगुआ कराके उनको अपने साथ में करते हैं और स्पीकर साहब, यही हाउस एक माध्यम है कि हम कोई बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में ला सकते हैं। (व्यवधान व भाओर) स्पीकर साहब, मेरी सबमि अन यह है कि यह जो बिल इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत चाहते हैं, यह उनको न दी जाए। मैं इसको अपोज करता हूं।

श्री लछमन सिंह (कालका): स्पीकर साहब, दरअसल एकट में यह अमैंडमैंट करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे हल्के में एक नया ब्लाक बरवाला बना है। गवर्नर्मैंट ने आज से दो तीन महीने पहले से ही आर्डीनैस जारी कर दिया था कि गवर्नर्मैंट नौमीनेट कर सकती है। हाउस को यह जानकर हैरानी होगी कि मेरे हल्के के साथ ही नारायणगढ़ का हल्का लगता है। पहले इलैक न हुए। चौधारी लाल सिंह जी यहां पर बैठे नहीं हैं। उनके सभी आदमी इलैक न हार गए बरवाला के अंदर मैम्बर्ज नौमीनेट भी कर दिए गए हैं और मैम्बर्ज उनको नौमीनेट किया गया है जो मैम्बर पहले इलैक न में हार गए थे। वे एक ही कम्यूनिटी के लोग हैं (३०म भोम की आवाजें) मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि समिति के मैम्बरों का ओहदा एक मुतब्रिक ओहदा है। उन्होंने चौधारी भजन लाल को मुख्य मंत्री बनाया है। इसलिए वे इस क्लास को देखें।

श्री अध्यक्षः आप अमैंडमैंट पर ही बोलें।

श्री लछमन सिंहः मैं अमैंडमैंट के बारे में बता रहा हूं कि यह अमैंडमैंट क्यों हो रही है। फिलहाल इसका सारे हरियाणा पर कोई असर नहीं होगा। सिवाये कालका या नारायणगढ़ कांस्टीच्यूएंसीज के बाकी सारे हरियाणा पर जब असर होगा, तब देखा जायेगा। मैं चौधारी साहब से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि कम से कम वे उन आदमियों को जो दो महीने पहले ही इलैक न में हारे हैं, और एक ही कम्यूनिटी से ताल्लुक रखते हैं,

पडौसी एम०एल०ए० या मिनिस्टर के कहने पर नौमीनेट न करें। वह मेरा हल्का है। उनको नौमीनेट कर दिया गया है। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कालका हल्के का एस०डी०एम० यह कहता है कि मैं लछमन सिंह को तंग करके डिप्टी कमि नर बन जाऊं। कोई लम्बा चौड़ा अर्सा बाकी नहीं है। दो साल ही तो इलैक अन में बाकी हैं। इसलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि आखिर ये भी ब्लाक समिति के चेयरमैन थे। इन्होंने इस ओहदे को मुतब्रिक समझा था। यह बड़ा ही मुतब्रिक और पाक ओहदा है। इस अमैंडमैंट को वापिस लें और यह अमैंडमैंट न करें। वहां पर वैसे इलैक अन करवा लें। ब्लाक बन गया। अभी कुछ हुआ नहीं और अदालत से स्टे भी हो गया। (श्री भले राम की ओर से विघ्न) अरे भाई, बैठ जाओ, आपसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे से इसका ताल्लुक है। मेरे लिए ही यह अमैंडमैंट है। (व्यवधान व भाऊर) यह अमैंडमैंट ही मेरे हल्के के लिए हैं। बाकी सारी जगह इलैक अन हो चुके हैं। इसलिए जो एक ही फिरके के हारे हुए आदमी नौमीनेट किए गए हैं, ये उस आर्डर को विद्धा कर लें। यह नौमीनेट नहीं होने चाहिए थे। यह एक अन डैमोक्रेटिक एक अन है। वैसे भले ही जो करना चाहें कर लें। इसलिए यह अमैंडमैंट बिल्कुल ही इल्लीगल है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी ने कहा कि हारे हुए नौमीनेट नहीं करने चाहिए थे। वैसे आपने भी

देखा है कि जो इलैक अन में एमोएलोए० या एमोपी० हार जाता है, वह राज्य सभा में नौमीनेट हो सकता है।

श्रीमती चन्द्रावती: पहले तो कांग्रेस में भी यही था कि हारे हुए मैम्बर को राज्य सभा का मैम्बर या एमोएलोसी० नहीं बनाया जाता था यह तो अभी धक्का मुक्की भुरु छुई है। (व्यवधान व भाओर)

चौधरी कुलबीर सिंह मलिक: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर।

Mr. Speaker: This is no point of order. This should not be recorded.

श्रीमती चन्द्रावती: स्पीकर साहब, यह बिल इस वक्त इन्ट्रोडयूस नहीं होना चाहिये। बाद में बे अक कर लें। इससे इन को क्या फर्क पड़ता है। सारे लोग इस बात को मानते हैं। (व्यवधान व भाओर)

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, सरदार लछमन सिंह जी बहुत पुराने मैम्बर हैं। काफी देर से ये मैम्बर चले जा रहे हैं। यह इस बिल के ऊपर बोलने की स्टेज नहीं थी। इनको आपत्ति हो सकती है। उसके लिए इनको मौका मिलेगा। जब इन को मौका मिले तब यह अपने आपको पूरी तरह से एक्सप्रैस करें। इन्ट्रोडयूस होने के बाद जब बिल पर डिस्क अन होगी, उस समय यह इसके खिलाफ

जितना चाहें, बोलें। यह इस बात की स्टेज नहीं थी। जैसे मैंने कहा कि कोई प्रोसीजरल एतराज ये इन्ट्रोडक अन स्टेज पर उठा सकते हैं। बिल की मैरिट्स और डी मैरिट्स पर इस वक्त नहीं बोल सकते। सरदार साहब तो पर्सनल बातों मतें चले गए। वे सारी गैर जरूरी बातें थी। सरदार लछमन सिंह डिवैल्पमैंट मिनिस्टर भी रहे हैं। मैं इन को यह बताना चाहूँगा कि हमने यह हल्के के लोगों की रिकवैस्ट पर ही किया है। यह प्रोवीजन अकेले बरवाला के लिए ही नहीं है। यह एक्सीजैंसी प्रोवाइड कर दी है कि चुनावों के बाद अगर कोई नया ब्लाक बन जाये, या कहीं पर बाउन्डरी चेंज हो जाए जैसे कि लोग डिमान्ड करते रहते हैं, तो बार बार चुनाव नहीं हो सकते। चुनावों का प्रोसीजन काफी लम्बा है। आप तो चुनाव के प्रोसीजर से पूरी तरह से वाकिफ हैं, आपको पता होगा कि प्रोसैस को कम्पलीट करने में ही एक साल का असा लग जाता है। उस बात का अवायड करने के लिए पंचायत समितियों के जो लोग हैं या पंचायत समितियां खुद ही पार्टीसिपेट करके पंचायती राज का जो प्रोसैस है, उसमें उनको मौका देने के लिए सैक अन 5 में यह अमैंडमैंट की गई है। अगर किसी ब्लाक की बाउन्डरी चेंज हो जाये तो नया ब्लाक बनने से मैम्बर नये या पुराने ब्लाक में आयेंगे या रह जायेंगे, उनमें एक दो, तीन, चार मैम्बर्ज की कमी को पूरा करने के लिए इलैक अन प्रोसैस एडॉप्ट करने की बजाये जिसमें एक साल लग जायेगा, बाकि के पीरियड के लिए नौमीनेट कर देंगे। सारी उम्र के लिये किसी को हम नौमीनेट नहीं करेंगे सिर्फ बाकी के पीरियड के लिये

ही नौमीनेट करेंगे ताकि पंचायत समिति इलैक्ट्रिड और नौमीनेटिड मैम्बरों के द्वारा कांस्टीच्यूट होकर काम पूरी तरह से कर सकें। इस बिल का इससे फालतू कोई मुददा नहीं है। इसलिए यह बिल लाया गया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आर्डर है। जो बात चौधरी भाम १०८ सिंह जी ने बतलायी है कि इसका मना क्या है, या तो हम नहीं समझ पाये या ये कुछ गलतफहमी में हैं। मैं अमैंडिंग क्लाज को पढ़ देता हूँ। इसमें इन्फोंने फरमाया है कि कोई एक्सीजैंसी अराईज हो जाए, डिलिमिटे अन हो जाए या कोई लैकूना रह जाए, उसको पूरा करने के लिए यह बिल लायें हैं। इस में यह लिखा हुआ है :—

“(4) Notwithstanding anything contained in sub section (1) and (3) where a block is re-delimited, before the constitution of the Panchayat Samiti

यानि पंचायत समिति बनने से पहले कोई री डिलिमिटे अन का आर्डर हो जाए, वह तो है, बाद में अगर कोई हो जाये, उसके लिए कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम बाद में भी कर लेंगे, उसके लिये इसमें कोई प्रोवीजन हमें तो नजर नहीं आता। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी जरा इस बात को क्लीयर कर दें।

चौधरी भाम १०८ सुरजेवाला: चौधरी वीरेन्द्र सिंह समझ नहीं पाये, पता नहीं इनको क्या गलतफहमी है। पंचायतय

समिति का मतलब है। चेयरमैन और वार्ड से चेयरमैन आफ दि पंचायत समिति। मान लो किसी पंचायत समिति के मैम्बर इलैक्ट हो गए हैं। चेयरमैन और वार्ड से चेयरमैन अभी इलैक्ट नहीं हुए हैं। पंचायत समिति कांस्टीच्यूट हो गयी फार दी इलैक्ट न आफ दि आफिस बीयरज्ज। मैम्बर आलरेडी इलैक्ट हो गए हैं और मैम्बर्ज की इलैक्ट न के बाद किसी ब्लाक की बाउंडरी चेंज हो गयी, उसके लिए यह बिल है। किसी ब्लाक के मैम्बरों की इलैक्ट न के बाद और चेयरमैन पंचायत समिति के इलैक्ट न से पहले अगर बाउंडरी चेंज हो गई हैं, तो नौमीनेट होंगे। (व्यवधान व भाओर) जहां कहीं भी बाउंडरी चेंज हुई है या बदली है, उसके लिए यह बिल है, इसमें गलतफहमी क्या है।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

दि पंजाब पंचायत समितिज (हरियाणा अमैंटमैंट), बिल 1985 को इन्द्रावेड्यूस करने की परमि न दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब मिनिस्ट साहब बिल इन्द्रावेड्यूस करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Ch. Shamsher Singh Surjewala): Sir, I introduce the Bill.

वर्ष 1985–86 के बजट पर सामान्य चर्चा

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब वर्ष 1985-86 के बजट पर जनरल डिस्क न भुरु होगी।

श्रीमती चन्द्रावती (बाढ़डा): जनाब, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे । किया है, इसमें 114 करोड़ रूपये का धाटा दिखाया है। इसमें ज्यादा धाटा नान प्लान साईड पर है, प्लान साईड पर कम है। स्पीकर साहब, पहले तो बजट में भूतपूर्व प्रधान मंत्री और वर्तमान प्रधान मंत्री की स्तुति की गई है उसके बाद केन्द्रीय बजट के लिए भी दो भलोक लिखे गए हैं। मेरा ख्याल है कि अगर लक्ष्मी की भी कुछ महिमा का वर्णन आ जाता तो क्या ही अच्छा होता क्योंकि रूपये पैसे का मामला है। सब कुछ भुभ हो जाता, अगर बजट में ऐसा कर दिया जाता। जनाब, यह जो बजट पे । किया गया है, इसमें डिवैल्पमैंट नाम की कोई चीज नहीं है। जौब औरिएन्टिड बजट यह है ही नहीं। जब बात आयेगी कि पैसा कहां से आयेगा, तो मैं टैक्सों की बात कहूँगी। 1979 से लेकर अब तक एक बार में तो स्टाम्प रजिस्ट्रे न टैक्स 10.5 परसैंट से साढ़े बारह परसैंट किया गया था। उसके बाद इसी तरह से बसों का भी दो बार 1979 से लेकर अब तक किराया बढ़ाया गया है।

जनाब जब बजट का जिक्र आया है तो मुझे एक कहानी याद आ गई। किसी आदमी के कई बेटे थे। खूब कमाते थे। उनके तीन चार ही भी थे और आज के जमाने के हिसाब से ट्रैक्टर भी थे। स्पीकर साहब, पहले तो वे अपनी अलग गांठी करने लग गए। कोई पूली बेच आया, कोई अनाज बेच आया और एक

लड़का तो गाड़ी ही बेच आया। स्पीकर साहब, यही हाल हमारी इस सरकार के खजाने का है। खजाने में तो कुछ भी नहीं है। यह सरकार तो ऋण पर चलने वाली है। रजिस्ट्रे अन टैक्स, सैल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और व्हीकल्ज टैक्स कोई भी टैक्स पूरी तरह से रियलाइज नहीं होता। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, अगर टैक्स पूरी तरह से रियलाइज हो जाए तो दुबारा टैक्स लगाने की जरूरत ही न पड़ें चूंकि टैक्स पूरी तरह से रियलाइज नहीं होता इसलिए हर साल नए टैक्स लगते जाते हैं। इनके जो अधिकारी हैं वे पैसा खाते हैं और इसलिए व्यापारियों ने दो दो बही खाते रखे हुए हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, अफसरों के पैसा खाने वाली बात रिकार्ड नहीं की जानी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रावती: मैंने किसी पर्टिकुलर अफसर के बारे में नहीं कहा। डिप्टी स्पीकर साहब, बजट स्पीच के पेज 19 पर पैरा 42 में इन्होंने लिखा है— एक विपरीत न्यायालय निर्णय के कारण कुछ सौदों पर बिक्री कर की वसूली नहीं हो पाई। डिप्टी स्पीकर साहब, कहीं बिक्री कर की वसूली नहीं हो पाती और कहीं बिजली के कर की वसूली नहीं हो पाती। 77-77 लाख और 64-64 लाख रुपया बड़े बड़े साहूकारों के नाम पड़ा हुआ है लेकिन उसको वसूल नहीं किया जाता। इस सरकार का तो दिवाला निकला हुआ है। सारी चीजें कर्जे में चल रही हैं। डिप्टी

स्पीकर साहब, स्टेट पर कहीं वल्ड बैंक का कर्जा है और कहीं ने तनेलाइज्ड बैंक्स का कर्जा है तथा कुछ सैंट्रल गवर्नमैंट से आता है लेकिन अपने यहां का कुछ भी नहीं है। व्यापारियों से आए दिन चन्दा लिया जाता है जो कि चुनावों में काम आता है। आज यह सरकार दिवालिया हो गई है। इस सरकार ने डिवैल्पमैंट का कोई काम नहीं किया है। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि ये लोग कम्पयूटर का खिलौना तो ले आए होंगे लेकिन असली कम्पयूटर की बात करना ठीक मालूम नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको कुछ करना ही नहीं है। जहां यह हालत हो कि यह सरकार लोगों को एक साइकिल न दे सकती हो, जहां लोगों की यह स्थिति हो कि घर पर हर मैम्बर साइकिल न खरीद सकता हो वहां कम्पयूटर की बात करना एक मजाक है। कम्पयूटर का खिलौना तो आ जाएगा या प्रदर्शनी में कहीं कम्पयूटर आ जाएगा लेकिन लोगों को कम्पयूटर सर्विस प्रोवाइड करना एक मजाक की बात है। बजट में इसका नाम लिया गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, कोई प्रैक्टिकल बात करते जिससे कि लोगों को काम मिलता तो वह मानने वाली बात थी।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने बसों के किराये बढ़ाये हैं। आम आदमी मोटर में सफर करता है और बड़े लोग कारों में सफर करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने बीस प्रति तत्काल किराया बढ़ा दिया। यह बोझा जन साधारण पर पड़ेगा और इसके लिए पहले भी लोगों ने बड़ा विरोध किया था। यह सरकार बसासे-

को तो बढ़ाती नहीं है लेकिन किराया बढ़ाती जाती है। अब गर्मी का मौसम आ रहा है कहीं पर भी पानी का इन्तजाम नहीं होगा। औरतों की गोद में छोटे छोटे बच्चे होंगे लेकिन उनके लिए कहीं भी पीने का पानी नहीं होगा। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर यह सरकार बसें नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम गर्मी के सीजन में पानी का इन्तजाम हर जगह करवा दे। अगर बसें कम हैं तो एक बस का कई कई बार चक्कर लगवा दें। यहां पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे नहीं हैं और जहां भी बैठे हों वे नोट कर लें या कोई और नोट कर लें। मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में कहना चाहती हूं। सदन के पटल पर यह इंफरमे अन रखी गई थी कि 29 कंडक्टर्ज को तीन महीने के बाद हटा दिया यमुनानगर के जी०ए००० ने पांच हजार से दस हजार तक लेकर 2 लाख 40 हजार रुपया लिया है, इस बारे में इंक्वायरी करवा ली जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, उसी अफसर को इस सरकार ने लैंड इक्वीजी अन अफसर बना दिया। वह अफसर किसान को एक पैसा भी नहीं देगा। वहां पर ईमानदार अफसर बैठा था जो आपको पसन्द नहीं था। इसलिए उसको वहां से हटा दिया। डिप्टी स्पीकर साहब, पहले वाला लैंड इक्वीजी अन अफसर ईमानदार था। जिस किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से जमीन बनाई, कम से कम वह ईमानदार अफसर उस किसान को उसकी जमीन का ठीक पैसा तो दे देता था लेकिन यह अफसर तो उस गरीब किसान को एक पैसा भी नहीं देगा। मेरा सरकार से कहना है कि कम से कम ईमानदार अफसर को तो लगाओ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं बहुचर्चित एस०वाई०एल० कैरियर चैनल की बात करती हूं। मैं चौधरी खुर रीद अहमद, जब वे फाइनैस मिनिस्टर थे उनकी स्पीच में से थोड़ा सा पढ़ देती हूं। उसमें लिखा है—

“Our undying gratitude must go once again to Smt. Indira Gandhi for ensuring that justice is granted to us in this matter. With her blessing we expect that the carrier channel in the Punjab territory will be completed within two years.

ये दो साल की बात करते थे लेकिन आप देखिए कि कितने साल गुजर गए। डिप्टी स्पीकर साहब, यह कितने साल की बात हो गई। इसी तरह से दूसरी बार छोकर साहब ने 1983–84 में नाथपा झाकड़ी के लिए कहा था। लेकिन अब ये कहते हैं कि नाथपा झाकड़ी को हमने छोड़ दिया है। डिप्टी स्पीकर साहब, इतना पैसा खर्च करने के बाद इस सरकार ने उसको क्यों छोड़ दिया, क्या वजह थी उसको छोड़ने की? क्या आपके पास ज्यादा बिजली हो गई है? कोई वजह तो सरकार को बतानी चाहिए। लोगों को धोखा दिया गया है। कभी नाथपा झाकड़ी का नाम लिया जाता है और कभी यमुना नगर ताप विद्युत घर का नाम लिया जाता है और इसी तरह से कई और नाम लिये जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जे०एल०एन० के बारे में कहना चाहती हूं। खुर रीद अहमद जी ने भी इसके बारे में कहा था कि यह एडवान्स स्टेज पर है लेकिन मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जे०एल०एन० का काम बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है।

झज्जर में प्लेटफार्म बन चुका है और वहां पर कालोनी वगैरह भी बन चुकी है लेकिन जो 16 एम०वी० का ट्रांसफारमर लगना था वह नहीं लगाया गया। इस वजह से जो मैटिरियल वहां खर्च किया गया वह सारा बेकार चला गया। डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात हो तो वह बताई जाए इनके तो सारे के सारे काम ही खराब है। इस बजट में लिखा है कि वर्ल्ड बैंक की सहायत के पैसे से लाइनिंग का काम किया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर खराब मैटिरियल लगाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर साहब, लोहानी में एक मैकेनीकल वर्क आप है। वहां पर साल साल से एक ही एक्स०ई०एन० बैठा हुआ है। वहां पर पानी लिफ्ट करने के लिए प्रौपलर लगे हुए थे। वे गन मैटल के थे और उनमें तीन पंखड़ियां लगी हुई थीं। इस एक्स०ई०एन० ने एक सौ एक प्रौपलर बदल दिए। अब वे लोहे के हैं और उनमें चार पंखड़ियां लगी हुई हैं जिससे कि उनका संतुलन नहीं होता। वह लोहा जो उनमें लगा हुआ है वह जंग लगा हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर दो सौ हौर्स पावर की मोटर लगी हुई है। उसमें एक विंवटल तार लगते हैं लेकिन अब उसमें अस्सी पिचासी किलो तार लगाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, अगर वहां की इंक्वायरी कराई जाए तो बीस तीस लाख का घपला मिलेगा। यह आदमी वहां पर पिछले सात साल से बैठा हुआ है। पहले वहां पर मि० सोढ़ी एक ईमानदार एस०डी०ओ० था लेकिन उसको रहने नहीं दिया। अगर वहां पर यही हाल रहा तो लिफ्ट नहीं चलेगी और वह मोटर पानी नहीं उठायेगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, वहां पर एक कादवां गांव पड़ता है। वहां पर एक सब डिवीजन बनाया गया। वहां पर राम कुमार नाम का एक असिस्टेंट था। इस एक्स0ई0एन0 ने ट्रैक्टर के टयूब और टायर तो खुद उत्तरवा लिए और उस राम कुमार को पकड़वा दिया। उस बेचारे ने भार्म की वजह से आत्म हत्या कर ली। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। जिस आदमी ने यह काम करवाया था उसने यह केस दबवा दिया। मैं सरकार से दरखास्त करूँगी कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तीन एक्स0ई0एन0 होने चाहिएं वहां पर एक बैठा हुआ है। इस बजट में बहुत कुछ करने के लिए जिक्र तो किया गया है लेकिन उन कामों को करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि किस तरह से काम चलेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा में खेत सूखे पड़े हैं अगर भाखड़ा नहर एक दफा टूट गई थी। तो उसकी जिम्मेदारी ठहरानी चाहिए थी कि दुबारा वह नहर कैसे टूटी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कुछ बातें कहीं थी लेकिन मैं उनहें दोहराना नहीं चाहती। बिजली के बारे में अभी सुरजेवाला जी ने यह माना है कि भाखड़ा से 30 हजार यूनिट प्रतिदिन कम बिजली मिलती है। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज किसानों की हालत बन्धुवा मजदूरों से भी खराब है। आपने अफरीकन गरमटियों का नाम सुना होगा, आज वही हालत यहां पर किसानों की है। कर्जा तो देते हैं किसानों को लेकिन उस कर्जे का चैक जो होता है वह डीलर को दिया जाता है। इससे किसान को पूरा लाभ नहीं हो

पाता है। वह 3500 की मोटर पहले तो किसान को 4000 में लगाता है और हो सकता है कि पुरानी मोटर भी दे दे क्योंकि चैक उस डीलर के हाथ आ जाता है और वह अपनी मनमानी करता है। चलो अगर चैक उसी को ही देना है तो कम से कम सरकार इस बात का तो किसानों को आ वासन दे कि एक साल के अंदर वह मीन टूटेगी नहीं और अगर उसका कोई पुर्जा खराब हो जाएगा तो उसे वह फ्री मिलेगा। लेकिन इस तरह का कोई आ वासन सरकार की ओर से किसानों को नहीं दिया गया है जिसके कारण किसानों को काफी मुँह कलों का सामना करना पड़ता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, हरिजन भाईयों के बारे में यह सरकार बड़ी डींगें मारती है कि हमने हरिजनों के लिये यह कर दिया, वह कर दिया। एक हरिजन कल्याण निगम है उसे 8 जी0एम0 एडमिनिस्ट्रे न के लिए लगा रखे हैं। उनमें से पांच स्वर्ण, एक ही बिरादरी के हैं। इसके अलावा चार फील्ड आफिसर्ज लगा रखे हैं, वे चारों ही आदमपुर के हैं। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): डिप्टी स्पीकर साहब, यह बात इनकी गलत है कि वे आदमपुर के हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: आप उनके बारे में बता दें कि इन 8 जी0एम्ज0 में से कितने हरिजन हैं? डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पास एक इकनौमिक सर्वे की किताब है जो कि इनकी दी हुई है।

उसमें लिखा है कि हरियाणा में 36.6 परसैंट लोग यीलो पावर्टी हैं और दूसरी तरफ यह बताया है कि 114.62 परसैंट ग्रेजुएट्स लाईव रजिस्टर्ज में अन एम्प्लायड हैं मैट्रिकुलेट 49.37 परसैंट अन एम्प्लायड हैं। पारा मैडीकल, एग्रीकल्चर डाक्टर्ज वैट्रनरी और इंजीनियर्ज तक भी लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक हमारी यह सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है। इसी संबंध में मैंने एक सवाल भी पूछा था कि हम जब अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को तो नौकरी नहीं दे सकते लेकिन वाराणसी, रायबरेली और अमेठी के लोगों को खुट्टा करने के लिये नौकरी क्यों दे रहे हैं। इतनी दूर जाने का क्या लाभ जबकि हमारे अपने प्रदेश में बेरोजगार बैठे हैं। कम से कम अपने लोगों को तो पहले काम मिलना चाहिये। यमुनानगर में मैं गयी थी वहां नर्सरी में मुझे एक एम्प्लाई मिला था, वह मेरठ का था, पता नहीं उसको कैसे लगा दिया इन्होंने ? दूसरे लोगों को तो ये बिना एडवरटाईजमैंट के बिना क्वालिफिकेशन के ही लगा देते हैं। हमारे यहां डाक्टर्ज, इंजीनियर्ज, ओवरसीयर्ज का तो हिसाब ही नहीं कितने हैं, मैट्रिक, ग्रेजुएट्स तक की तो बात ही छोड़िए। अन एम्प्लायमैंट इतनी है कहना ही क्या और फिर अपने बजट में यह दिया है कि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जाएगा। काम अगर सरकार किसी को देना चाहे तो वह एक छोटी इंडस्ट्री के द्वारा भी दे सकती है लेकिन इसके लिये बजट में सरकार ने पैसा बहुत कम रखा है। अगर भूल से कहीं कोई बेचारा छोटी इंडस्ट्री लगा भी

लेता है तो उसे बिजली नहीं मिलती है। इसलिये सरकार को मेरी इन सब बातों पर अवय ध्यान देना चाहिये।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने बहनों को खुत्ता करने के लिये उनकी पहनने वाली चूँड़ियों पर रियायत कर दी है। मैं तो यह कहूँगी कि जितनी मुन्यारी की चीजें हैं उन सब में रियायत की जानी चाहिये। इस तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गांव गांव में लगवा दें ताकि इससे रोजगार की समस्या भी दूर हो और लोग अपने हाथों से काम करना भी सीखें तथा भाहर की तरफ न भागें। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक लड़की अपनी चुन्नी पर सलमा सितारा लगाने के लिए 20 रुपये लगा देती है। अगर 100 चुन्नियों पर सलमा सितारा लगाया जाये तो 2000 रुपये खर्च बैठता है। इस तरह से अगर सरकार ऐसी छोटी छोटी किस्म की इंडस्ट्रीज को गांव गांव में बढ़ावा दें तो हर गरीब आदमी को रोजगार मिल सकेगा और वह अपना व अपने बच्चों को पेट पाल सकेगा।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे पास सतबीर सिंह नाम का एक लड़का आया। उसे सैल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम के तहत नारनौल में मारबल कटिंग के काम के लिए 13-3-1984 को कर्जा तो मिल गय है लेकिन उसे अभी तक बिजली का कनैक्ट नहीं मिला है। आप ही बताएं कि अगर उसे बिजली नहीं मिलेगी तो उसका काम कैसे चलेगा और वह कर्जे की कि तें सरकार को कैसे अदा

करेगा। इसलिए सरकार को ऐसे केसिज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी आदमी को मायूसी न हो, वह अपने काम धन्धे में लगा रहे और दूसरों को भी उससे काम मिलता रहे। मुझे तो इस सरकार की कारगुजारी को देख कर आ चर्य होता है कि यहां पर कभी भाखड़ा टूट गया, कभी बिजली नीं कभी एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में यहां पर पुओं के लिए चारा भी नहीं रहेगा। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं लेकिन आयल सीड और गेहूं की कीमतें नहीं बढ़ीं। गेहूं जब किसानों के घर में होता है तो कीमतें घट जाती हैं। इसी तरह से आलू, तोरिया, कपास और सरसों का भी यही हाल है सरसों के बारे में तो इन्होंने खुद माना भी है। डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार तो ऐन्टी पीपल है और ऐन्टी पीपल बजट ही इस सरकार ने पे । किया है।

इससे आगे डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पुलिस की बात कहना चाहूंगी। पुलिस के ऊपर इनका खर्च बढ़ा है और यह कहते हैं कि हमारे प्रदे । में कानून और व्यवस्था सबसे अच्छी है। चण्डीगढ़ के होस्टल का ही प्रमाण ले लीजिये। फिर कहेंगे कि चण्डीगढ़ यू०टी० में है, इसका प्रासन यहां का है, हमारा कोई हाथ नहीं है। इन्होंने होस्टल में पुलिस की छावनी बैठा रखी है। खुद मुख्य मंत्री महोदय के लिए अलग से गाड़ियां, मोटर साईकल

सवार और बहुत से गन मैन वगैरह साथ चलते हैं। (गोर एवं व्यवधान),

वन तथा जेल मंत्री (श्री गोवर्धन दास चौहान): बहन जी, वह छावनी सब एम०एल०एज० की हिफाजत के लिए है।

श्रीमती चन्द्रावती: इन छावनियों की, गन मैन की आव यकता इसलिये पड़ रही है क्योंकि कानून और व्यवस्था की हालत नाजुक है। सुरेन्द्र सिंह दलाल को एक ए०एस०पी० ने मार दिया और वह दनदनाता हुआ फिरता है। (गोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, कमि नर रैंक के एक अधिकारी इसी जांच कर रहे हैं। जिस केस की जांच हो रही हो उस केस का हाउस में जिक्र नहीं होना चाहिये।

श्रीमती चन्द्रावती: डिप्टी स्पीकर साहब, एक आई०पी०एस० वर्दी में एक आदमी को गोली से मारता है और फिर यह कहें कि इस बात का जिक्र यहां नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए ? पुलिस कस्टडी में अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसके खिलाफ सरकार को एक अन लेना चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि इन्होंने उस ए०एस०पी० के खिलाफ क्यों एक अन नहीं लिया। कुछ देर के बाद ऐसे आदमी को छोड़ दिया जाए यह कहां का कानून है ? डिप्टी स्पीकर साहब, पुलिस कस्टडी में कोई चोर डाकुओं

को नहीं मारा जाता बल्कि उनको मारा जाता है जो कि इनके बैरी हों, जिनके साथ इन्होंने बैर निकालना हो ।

मैं तो डिप्टी स्पीकर साहब, यह भी कहना चाहती हूं कि इनके ला एण्ड आर्डर का यह हाल है कि आज अगर किसी बहु बेटी को थाने के अंदर किसी केस की तफती आ के लिये ले जाएं, तो उन बेचारियों की इज्जत महफूज नहीं है । कितने आई०जी० कितने डी०आई०जी० और कितने ए०आई०जी० पुलिस विभाग में हैं, 75 परसैंट बजट इन पर ही चला जाता है । जैसे डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी में होता है कि गवर्नर्मैंट आफ दि पीपल, बाई दी पीपल एण्ड फार दि पीपल उस तरह से यह बजट आफ दि गवर्नर्मैंट, बाई दी गवर्नर्मैंट एण्ड फार दि गवर्नर्मैंट है । यह बजट लोगों के लिये नहीं है क्योंकि लोगों के लिए इस बजट में कोई चीज नहीं है । जनाब सड़कों का भी बहुत बुरा हाल हैं मंत्री जी ने खुद बताया था कि एक सड़क की मुरम्मत के लिए हमें चाहिएं तो 24 हजार रुपए लेकिन हम लगाते हैं 6 हजार रुपए । डिप्टी स्पीकर साहब, 6 हजार रुपए में तो सड़क का पैच वर्क भी नहीं हो सकता । इस तरह से सरी सड़कें टूट गई हैं । गोरछी गांव के बारे में हमने इतीन बार कह दिया कि लेकिन वहां पर सड़क नहीं बन रही है । जो लिंक रोडज हैं वे भी सब टूटी पड़ी हैं । किसी सड़क में अगर पैच वर्क करते हैं तो उसमें दो कंकर डाल देते हैं और उस पर रोलर नहीं लगाया जाता । उसका नतीजा यह होता है कि वह कंकर दूसरे दिन फिर निकल जाते हैं । आप चीफ इंजीनियर

को भेजें वह जाकर देखें कि गांवों की सड़कों की क्या हालत है।
मंत्री जी गांव के ही रहने वाले हैं (गोर)

श्री उपाध्यक्षः यह बात रिकार्ड न की जाए।

श्रीमती चन्द्रावतीः डिप्टी स्पीकर साहब, पीने का पानी सबसे जरूरी चीज है। पिछले 8—9 महीने हुए हैं कि अम्बाला में पीने का पानी नहीं था। मैं किसी के घर चली गई तो वे लोग किसी पड़ौसी से पानी मांग कर लाए। गुड़गांव और भिवानी का भी यही हाल है। जहां तक नारनौल भाहर का ताल्लुक है वहां पर तो बहुत बुरी हालत है। मैं कहती हूं कि सरकार कम से कम पीने का पानी तो मुहैया करे। अगर आप यहां के लोगों को नौकरियां नहीं देते हो तो कम से कम पीने का पानी तो दो। यह काम वर्ल्ड बैंक की स्कीम में भी आता है और दूसरी स्कीमों में भी आता है। मैंने सुना है केन्द्रीय सरकार भी इस काम के लिए काफी पैसा देती है। भिवानी जिले में जहां पानी नीचा था वहां पर डीप टयूबवैल्ज लगाए थे। जैसे भिवानी जिले में बाढ़ा और ढालनवास तथा महेन्द्रगढ़ जिले में मांधां गांवों में टयूबवैल्ज तो हैं लेकिन आबादी के हिसाब से पानी नहीं आता। देहात के लिए ये कहते हैं कि देहातों के घरों में नलके नहीं देंगे। मैं तो यह कहती हूं कि भाहरों के भी हर घर में नलका दिया जाए उससे पानी कम वेस्ट होगा। बाहर के नलकों से तो बल्कि लोग टूटी उतार कर ले जाते हैं। मेरा कल एक पोल्यू न के बारे में सवाल था। आज कस्बे और गांव सड़ रहे हैं। वहां पर सैनीटे न का तो नाम ही नहीं

है। एक एक गांव में 2-2 और 3-3 पंचायतें हैं लेकिन सैनीटे अन का इन्तजाम नहीं है। इसी तरह से कस्बों में है। जहां तक बिजली का ताल्लुक है कस्बों में आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, वे बल्ब और टयूब के पैसे खा जाते हैं। कोई बल्क या टयूब लगाई ही नहीं जाती। इसलिये चोरियां ज्यादा होती हैं। तो इस बजट में लोगों के लिए क्या चीज है। यह एंटी पीपल बजट है। (धंटी) मैंने कैमिकल्ज के बारे में भी कहा था कि थोड़े दिनों में यह हालत हो गी कि आपका गुड़गांव और फरीदाबाद भोपाल बन सकता है। वहां सेफटी का बिल्कुल इन्तजाम नहीं है। एक कैमिकल इंडस्ट्री दादरी में भी है। इन इंडस्ट्रीज में किसी वक्त भी खतरा हो सकता है। यह मेरी आपको वारनिंग है। आप इन फैक्ट्रीज को कहो कि वे सेफटी का प्रबन्ध करो। फरीदाबाद में आज कोई आदमी सांस भी नहीं ले सकता। मैं चाहती हूं कि इन इंडस्ट्रीज पर पोल्यू अन टैक्स लगाया जाए।

श्री उपाध्यक्षः आपको आधा धंटा दिया था, आपके दो तीन मिनट रहते हैं। इसलिये आप वाइंड अप करें।

श्रीमती चन्द्रावतीः मैं थोड़ा टाईम और लूंगी। डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक नान आफिं टायल बिल भेजा था कि गांवों और कस्बों में सैनीटे अन के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन उस चीज के लिए कहने लगे कि हमने गांव के लोगों पर एक सैस लगाया था उसी से गांवों की डिवैल्पमैंट हो जाएगी। आप लोग भी गांवों से आए हैं। आपको पता है कि बच्चे गन्दी नालियों में

खेलते हैं, उनको बीमारी लग सकती है। जहां तक दूध की बात है, दूध बेचने वालों से जब हम पूछते हैं कि भाई आप दूध में पानी क्यों मिलाते हो तो वे कहते हैं कि क्या करें हमें ऊपर पैसा देना पड़ता है (गोर) डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं मैडिकल और पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहती हूं। (धांटी) मैडीकल के लिए इन्होंने क्या रखा है। हमने कहा था कि हस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, पटटी नहीं हैं और जो थोड़ी बहुत होती हैं वह बाजार में बेच दी जाती हैं। आप इन्क्वायरी करवाओं कि किस तरह से ग्लुकोस की बोतल बीमार को न देकर बाजार में बेच दी जाती है। इस बजट में हमें कोई नई चीज नहीं दिखी। इन्होंने खुद माना है कि इनके पिछले बजट का धाटा 46.83 करोड़ रुपये था और अभी साल खत्म भी नहीं हुआ कि उससे पहले ही वह धाटा अब 91.53 करोड़ रुपए हो गया है। डिप्टी स्पीकर साहब, कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए इन्होंने सूअर पालन और बकरी पालन की स्कीम बनाई है। सूअर और बकरी पालने से मैंने तो कोई असीर बनते देखा नहीं, वो सबसे गरीब होते हैं। क्या ये लोगों को पोल्टरी लाइन से भी नीचे लाना चाहते हैं। जो मछली पालन की स्कीम है उसका भी सारा पैसा खाया जाता है। आप तीतर पालन को क्यों नहीं डोमेस्टीकेट कर लेते? इन भाब्दों के साथ मैं कहूंगी कि विलेज इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री इन्द्र सिंह नैन (बरवाला): डिप्टी स्पीकर साहब, 20 मार्च को माननीय फाइनैंस मिनिस्टर ने इस आगस्ट हाउस में वर्श

1985–86 का जो बजट प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे विपक्ष के दोस्तों को पता नहीं किस बात की चिन्ता है। (गोर) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रेपीटी न नहीं करूंगा। अपोजी न के भाईयों को मेरी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। जब मैं गवर्नर महोदय के एड्रेस पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोला था, उस समय भी मैंने यह कहा था कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई नुकताचीनी नहीं करता और न ही अब नुकताचीनी कर रहा हूं। मैं जो भी बात कहता हूं वह सही कहता हूं गलत बात नहीं कहता। इसलिए सही बातों को सुनने की मेरी अपोजी न के भाईयों में हिम्मत और गटस होने चाहिए। इन्होंने जो बातें कहनी हैं, वे अपने बोलने के समय पर कह सकते हैं, इनको इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और इस बजट को मैं रियलिस्टिक, बोल्ड, करजीयस, वैल बैलेंस्ड और कामनमैन बजट कहता हूं और दूसरे भाब्दों में यह बैस्ट बजट कहा जा सकता है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी को इस बारे में मुबारिकवाद देता हूं। This budget reflects vision, experience and foresightedness of a talented politician who presented the best budget in this August House. (Interruptions) डिप्टी स्पीकर साहब, अच्छी बात तो यह है कि मेरी बातों को अपोजी न के भाई अच्छी तरह से और ध्यान से सुनें। जब समय आउ उस समय ये मेरी बातों का जवाब दे सकते हैं। हाउस में डैकोरेम रखना

हमारा सबका कर्त्तव्य बनता है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने इस बजट में सरकार की 1984-85 की जो उपलब्धियां हैं, उनके बारे में बड़े संक्षेप में वर्णन किया है और आगामी वर्ष अर्थात् 1985-86 के लिए सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनके बारे में रूपरेखा दर्ज है। डिप्टी स्पीकर साहब, 31 अक्तूबर 1984 को हिन्दुस्तान की स्वर्गीय महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी जी भावीद हो गई। इस बजट में इस बात का जिक्र है (विधन) मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा। इस बात का इस बजट में जिक्र है। मैं रैलेवेंट बोल रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमर भावीद हो गई और उनका नाम केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। उनके बाद उनके सुपुत्र श्री राजीव गांधी, हमारे लोकप्रिय युवा नेता, भारतवर्ष के प्रधान मंत्री बने। डिप्टी स्पीकर साहब, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई उस समय सारे भारतवर्ष में अंधेरा छा गया था। उस समय हिन्दुस्तान की जनता यह सोचती थी कि अब देश का क्या होगा। यही नहीं विदेशी ताकतें जो कि हिन्दुस्तान की भावित को सहन नहीं कर सकतीं, वे यह सोचती थीं कि इंदिरा गांधी के बाद भारत के टुकड़े होंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हाई कमांड ने पांच मिनट के अंदर यह फैसला कर दिया कि हम भारत का प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को बनाएं और केवल पांच मिनट के अंदर ही श्री राजीव गांधी को देश का

प्रधान मंत्री बना दिया। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बारे में कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, यह बिल्कुल रैलवैंट बात है। मेरे अपोजी न के भाई हमारी कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। ये अपने गिरेबान में मुंह डाल कर नहीं देखते। ये अपने नेता का फैसला 50 साल में नहीं कर सकते लेकिन हमने केवल पांच मिनट में अपने नेता का फैसला कर दिया था (गोर)

प्रो० सम्पत्ति सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। विधान सभा के अंदर सभी पार्टीज के माननीय सदस्य बैठे हैं। अगर इनको ये बातें कहनी हैं तो वह इनकी अपनी पार्टी मीटिंग में कहीं जा सकती हैं, चाहे उसमें इससे ज्यादा बातें कह लें लेकिन इस बारे में इतनी ज्यादा बातें कहने के लिए यह कोई प्लेटफार्म नहीं है। अगर इनकी अपनी पार्टी मिटिंग में इनको नहीं बोलने दिया जाता है, इनकी जुबान बंद कर रखी हैं तो ये पार्टी को छोड़ दें। (गोर)

श्री इन्द्र सिंह नैन: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने पांच मिनट के अंदर अपने नेता का फैसला कर लिया था और श्री राजीव गांधी को भारत का प्रधान मंत्री बना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही हिन्दुस्तान में लोक सभा के चुनाव करवाने की घोषणा की थी और लोक सभा के चुनाव करवा दिए।

श्री उपाध्यक्ष: नैन साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, ये बातें बजट स्पीच में भी आई हुई हैं। इसलिए मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। मैं बजट पर बोलने की भूमिका बना रहा हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, लोक सभा के इलैक अन के बाद हिन्दुस्तान की जनता ने अपना क्या फैसला दिया उसके बारे में मेरे अपोजी अन के भाईयों को अच्छी तरह से मालूम है। मेरे धनिश्ठ मित्र चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी हाउस में बैठे हैं और डा० मंगल सैन जी इस समय हाउस में नहीं हैं। इनकी पार्टी के तीन सदस्य आए थे और उनकी पार्टी के दो आए थे जबकि लोक सभा का इलैक अन 508 सीटों के लिए हुआ था। (थम्पिंग) अभी थोड़ी देर पहले श्रीमती चन्द्रावती जी इलैक अन के बारे में कह रही थीं। (गोर)

डा० भीम सिंह दहिया: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता था कि माननीय सदस्य को बजट के बारे में बोलने के लिए थोड़ा सा समय मिला है इसलिए इनको हाउस का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बजट से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं होती। बजट की किताब हिन्दी में भी छपी हुई है उसको पढ़ कर आ जाएं फिर बोलें। इस किताब को पढ़ कर पैरावाइज बोल लें। इनको यह किताब को पढ़ कर बताना चाहिए कि इस बजट में कौन सा पैसा ठीक दिया है और कौन सा पैसा गलत दिया है। माननीय सदस्य इलैक अन के बारे में जो भाशण दे रहे हैं इसके लिए और भी काफी वक्त है। इस बारे में सदन से बाहर भी भाशण दे सकते हैं।

चौधरी भाम ौर सिंह सुरजेवाला: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं सख्त प्रोटेस्ट करता हूं कि जो दहिया साहब ने कहा है कि माननीय सदस्य हाउस का मजाक बना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव राजनैतिक अथोरिटी का, राजनैतिक पावर का एक आधार है वही अथोरिटी बजट बनाती है, वही पालिसी बनाती है और वही प्रोग्राम बनाती है। डिप्टी स्पीकर साहब, इंदिरा गांधी जी केवल एक पार्टी की नेता नहीं थी, वे 16 साल तक इस दे १ की प्रधानमंत्री रही हैं इसलिए माननीय सदस्य द्वारा इंदिरा गांधी जी के बारे में जिक्र करना बहुत ही जस्टफाइड और रैलवैंट है।

12.00 बजे

श्री इन्द्र सिंह नैन: डिप्टी स्पीकर साहब, दहिया साहब मेरे मित्र हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं, मैं कैसा बोल सकता हूं इन्होंने मेरे साथ एक कमेटी में काम भी किया हैं डिप्टी स्पीकर साहब, एस०वाई०एल० चैनल के बारे में नान ऑफि०यल डे की काफी चर्चा हो चुकीह है। इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, ये किसानों की बात कर रहे थे और ये किसानों के हितैशी बन रहे हैं। जब इनका जमाना आया था तो उस अढाई साल में इन्होंने किसानों के लिए क्या किया वह सब को पता है। मैं हाउस को बताना चाहूंगा कि विक्रमी 1956 में कहत पड़ा था। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं उस समय के कहत को

छपना काल कहता हूं। (विध्न) मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं।
(विध्न)

चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवालः डिप्टी स्पीकर साहब, ये बहुत इर रैलेवैन्ट बोल रहे हैं।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी परमि अन से बोल रहा हूं (विध्न) मुझे बोलने का पता है। मुझे विपक्ष की एडवाइज की जरूरती नहीं है। हमारी सरकार ने सबसे पहले कृशि को प्राथमिकता दी है। भारत वर्ष कृशि प्रधान दे त है। हरियाणा में भी 80 प्रति अत लोग खेती पर ही निर्वाह करते हैं। ये भाई कृशि के बारे में कह रहे थे कि किसानों को कुछ नहीं मिला। जब इनका राज आया तो उस समय तीन रूपये विंवटल गन्ना और 260 रूपये विंवटल नरमा बिकता था। उस सययश लोगों में एक नारा था और लोग व्यंग्य करते थे कि लकड़ी 26 रूपये विंवटल, गन्ना 6 रूपये विंवटल बोले चौधरी चरण की जय।

श्री उपाध्यक्षः आज जल्दी खत्म करिए। आपका समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने भाहरों के लिए और देहातों के लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, सिर्फ अभी 10 मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्षः मेरे पास बहुत से मैम्बरों की लिस्ट है, जिन्होंने अभी बोलना है। आपको भी बोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही मिलेंगे। Please try to wind up.

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, श्री फूलसा राम और चौधरी भाकरुला खां का समय भी इन्हीं को दे दो।

.....

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड पर न लाया जाये।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, जो समय मेरा विपक्ष के भाईयों ने खराब किया है, उसका भी आप ध्यान रखें और वह समय मुझे जरूर दें। (विधन) मैं सारा समय भी ले सकता हूं, आप चिन्ता न करें आप यहां पर बार बार कह रहे हैं कि इस सरकार ने किसानों का कुछ नहीं किया। (विधन) यदि आप मेरी बात ध्यान से सुनें तो मैं आप लोगों के कान खोल दूं। डिप्टी स्पीकर साहब, यह बजट बहुत ही बढ़िया बजट है। अब मैं अपने हल्के के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, 27-10-84 को आदरणीय मुख्य मंत्री जी बरवाला हल्के में आये थे और उस दिन इन्होंने 50 हजार आदमियों की एक जन सभा को संबोधित किया था। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सी०ए० साहब को कहना चाहता हूं कि जो मांगे हमने रखी थीं, वे एक्सपीडाइट करवाई जाएं। जो मांगे हमने उस समय सी०ए० साह बके सामने रखी थीं उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं-

बरवाला को उप तहसील बनाना, बरवाला में प्राईमरी लैण्ड डिवैल्पमैंट बैंक खोलना, आई०टी०आई० चालू करवाना, प्राईमरी हैल्थ सैन्टर जो 8 बैड का है उसको बढ़ा कर 30 बैड का करना, बस स्टैंड का निर्माण करना, जे०बी०टी० ट्रेनिंग इन्स्टीच्यू न मेरे हल्के के गांव राखी भाहपुर में खोला जाना आदि थीं। बस स्टैंड का निर्माण कार्य पहली अप्रैल से हो जाने की संभावना है। डिप्टी स्पीकर साहब, आज सुबह ही मेरे हल्के के कुछ लोग और मैं चौधरी भाम और सिंह सुरजेवाला जी से मिले थे। हमने इनसे प्रार्थना की थी मेरे हल्के में जो सुरबरा माइनर और नाड़ा माइनर है उसको एकस्टैंड किया जाये। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हाउस में भी इनसे निवेदन करता हूं कि इस माइनरी को जल्दी से जल्दी एक्सपैंड किया जाये। मेरे हल्के के गांव राखी भाहपुर में जे०बी०टी० इन्स्टीच्यू न भी चालू किया जाये क्योंकि वहां पर बिलिंग पहले से ही बनी हुई तैयार पड़ी है। इस समय वह बिलिंग खाली है। बिलिंग खाली रहने की वजह से वह खराब हो रही है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में कापड़ों से थनमोरी तक एक लिंक रोड है उसको भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव और टैकनीकल एपूवल हो चुकी है। इसी प्रकार से बेरी अकबरपुर से उकलाना मण्डी के साथ लगता केवल आधा किलोमीटर का एक बाई पास भी जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए। मेरी सरकार से यह भी प्रार्थना है कि बरवाला कस्बे के अंदर एक आटो मोबाइल मार्किट, एक सब्जी मण्ड़ और रेजिडैंसियल मकान भी जल्दी से जल्दी बनाये जाने

चाहिए। ये सारी मांगे हमने जब सी०ए० साहब वहां पर 27-10-84 को गए थे, उनके सामने भी रखी थीं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बरवाला करखे के अंदर जो हिसार से चण्डीगढ़ आने के लिये 100 फुट की चोड़ी सड़क है उसके दोनों तरफ फुटपाथ बनाये जाएं, बीच में पटटी बनाई जाए और ट्यूब लाईट लगवाई जाएं।

बरवाला भाहर में जो थाना और हस्पताल की बिल्डिंगें हैं। वह लड़कियों के स्कूल के लिए दी जाएं क्योंकि इन दोनों के लिए भाहर से बाहर अलग बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई है। उस बिल्डिंग में थाना और हस्पताल फ्रैप्ट हो चुके हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि खाली पड़ी हुई बिल्डिंग लड़कियों के स्कूल के लिए दी जाए। (विधन)

श्री उपाध्यक्षः आप वाइंड अप करिए।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, विपक्ष के भाई कुछ बात कह रहे थे। मैं एक उदाहरण के द्वारा इन भाईयों को समझाना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी गांव के रहने वाले हैं और ये भाई भी गांव के रहने वाले हैं। इन्दिरा जी 1977 के अन्दर प्रधान मंत्री के पद से हट गई थीं। उनके हटने के बाद इनका राज जनता पार्टी की भाक्ल में आया था। उस समय की जनता पार्टी के अंदर आज की बी०जे०पी०, डी०ए०के०पी० व दूसरी पार्टियां भागिल थीं। उस समय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती

इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यह एक खिचड़ी और दि आहीन पार्टी है। (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, श्रीमती गांधी जी ने जो बात इनके बोर में कहीं थी वह, जो उदाहरण में अब आपके सामने कहूंगा, उससे सही साबित हो जायेगी। डिप्टी स्पीकर साहब, एक गावं में एक सुरदास यानि अंधा आदमी था। उसका मकान मेन गली में था। अंधे की गाफी और लंगडे की लाठी बड़ी खतरनाक होती है और अन्धे का अन्दाजा भी बड़ा सही होता है। उसके मकान के साथ एक लक्कड़ पड़ी हुई थी। यह आपको पता ही है कि देहात में लोग दीवार के साथ लक्कड़ या तो गाड़ देते हैं या टेढ़ा खड़ा कर देते हैं। वह अंधा आदमी रोज उस लक्कड़ पर बैठ कर पे आब किया करता था। एक दिन लोकदल के वर्कर उस लक्कड़ को चुरा कर ले गए। (विधन) लक्कड़ चुराने के बाद वह जगह खाली हो गई।

Dr. Bhim Singh Dahiya: On a point of order, Sir. We take strong exception to what he has said. He has no business to cast aspersions. He is telling a tale and is naming a political party. (Interuptions) The time of the House is being wasted. Why should he not speak on Budget ? (Interruptions and noise).

श्री उपाध्यक्ष: अब लोक दल कोई पार्टी नहीं है। नैन साहब, आप जल्दी खत्म करिए, आपका समय हो चुका है।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। (गोर) मैं कह रहा था कि वह जगह खाली हो गई (विघ्न)

प्रो० सम्पत्त सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मेरे साथी इन्द्र सिंह नैन जी ने यह कहा है कि लोक दल वाले चुरा ले गए।

श्री उपाध्यक्षः इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है।

प्रो० सम्पत्त सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जो ये बात करते हैं उसका मैं जवाब दे देता हूं।

श्री उपाध्यक्षः यह रिकार्ड पर नहीं आये गा।

चौधरी सुरेन्द्र सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब,

श्री उपाध्यक्षः यह भी रिकार्ड पर नहीं आये गा।

श्री हीरा नन्द आर्यः डिप्टी स्पीकर साहब,

..

श्री उपाध्यक्षः यह कुछ भी रिकार्ड न किया जाये।

श्री इन्द्र सिंह नैनः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि वह जगह खाली हो गई। देहात में भैंसे को झोटा कहते हैं। एक दिन गांव का झोटा खेत में से चर कर आया और उस खाली जगह पर बैठ गया। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अन्धा आदमी लाठी के सहारे लकड़ पर बैठकर पे आब करने का आदि था।

उस दिन वहां पर लक्कड़ नहीं था बल्कि झोटा बैठा हुआ था। अन्धा आदमी लाठी के सहारे लक्कड़ की बजाये झोटे पर पे आब करने के लिए बैठ गया। झोटा डर गया क्योंकि अन्धा आदमी हाथ में लाठी लिए हुए था। झोटा डर के मारे गली में सरपट दौड़ पड़ा, अन्दा आदमी झोटे पर था। सौभाग्य से उस गांव का सरपंच कांग्रेसी था। उसने गांव की गलियां पक्की करवा रखी थी। पक्की गली होने के कारण झोटे के पैरों की आवाज और भी अधिक आई। सामने से एक अन्धा लाठी टेकते हुए आ रहा था। वह डर गया और बोला, देखना अरे घोड़े वाले मारेगा। अन्धा आदमी जो झोटे पर बैठा था वह कहने लगा कि अरे मुझे यह तो बतला दे कि मैं किस चीज पर बैठा हूं। आया घोड़े पर बैठा हूं या हाथी पर बैठा हूं। अन्धा आदमी जो झोटे पर बैठा था वही हाल उस समय की जनता पार्टी का था। अच्छा हुआ लोगों ने अढाई साल में ही उस समय की जनता पार्टी की छुटटी कर दी वरना तो पता नहीं ये दे । को किस गड्ढे में डाल देते। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे उदाहरण से स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की वह बात जो उन्होंने कही थी कि जनता पार्टी एक खिचड़ी पार्टी और एक दि आहीन पार्टी है, सच्च हो जाती है। अन्त में मैं डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट का समर्थन करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

चौधरी तैयब हुसैन (ताउड़ू): डिप्टी स्पीकर साहब, खजाना मंत्री हरियाणा ने जो बजट हाउस के सामने पे । किया

है, मैं इस पर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा 1984–85 मेरे हाथ में हैं, इसके ओपनिंग सैंटैंस में लिख है:—

“The dawn of Haryana on 1st November 1966 ushered in an era of reconstruction and rejuvenation of Haryana”.

इसमें कहा गया है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सी बातें लिखी हैं। इन सारी बातों में हरियाणा की तरक्की का ही बोलबाला है। इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब कहते नहीं थकते कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है। अगर बार बार बयान दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा की तरक्की नहीं हुई है, इसका काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा या जो तरक्की हुई है, यह उनको पसन्द नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब से हरियाणा वजूद में आया तब से फलां फलां फील्ड में तरक्की हुई है। ठीक बात है, तरक्की हुई है, इसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर साहब हमें बिल्कुल पीछे ले जाना चाहते हैं और जब कोई बात आती है तो कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत राय है, जाति राय है। सी०एम० साहब को यह बात क्यों बोलनी पड़ती है ? जो कुछ ये बोलते हैं उसको सुना जाता है, लेकिन जब इस ओहदे पर नहीं रहेंगे तब देखेंगे कौन उनकी बात को सुनता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इकोनामिक सर्वे आफ हरियाणा के भुरु में कहा गया है —

“The benefits of development have reached the poorest section of society.”

हमारे एफोएम० साहब अपनी बजट स्पीच के पेज 4 पर कहते हैं कि पिछले चार सालों में 61 परसैंट पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है। इसके साथ ही साथ कल मैंने एक सवाल पूछा था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे सूबे में 1983 में 30.2 परसैंट लोग पावर्टी लाईन के नीचे थे। एक तरफ तो कहते हैं कि पर कैपिटा इन्कम 61 परसैंट बढ़ी है और दूसरी तरफ पावर्टी लाईन के नीचे 30.2 परसैंट लोग हैं। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं 61 परसैंट पर कैपिटा इन्कम का मतलब है कि तरकी हुई है। इसका मतलब यह है कि कुछ ही खानदान हैं जिनकी तरकी हुई है और उनकी वजह से चार सालों में 61 परसैंट पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है। बाकी जो गरीब लोग हैं, वे और गरीब होते जा रहे हैं। ये आंकड़े इन्होंने ही दिये हुए हैं। इकोनोमिक सर्वे आफ हरियाणा में एक जगह लिखा है—

“Under the sacred leadership of the Chief Minister.”

ये सैकड़ लीडर हैं और इन्होंने कुछ लोगों में इन्ट्रैस्ट लिया है, कुछ को फायदा पहुंचाया गया लेकिन जहां तक गरीबी की बात है, वह वहीं की वहीं रही। गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कोई तवज्जो नहीं दी गई। जिस एरिया से मैं चुन कर आता हूं वहां बेहद गरीबी है। उस एरिया की डिवैल्पमैंट करने के लिए सरकार ने मेवात बोर्ड बनाया। इसके बावजूद सरकार ने 1980-81

से लेकर 31 जनवरी, 1985 तक की जो फिर्गर्ज मेरे कल के सवाल के जवाब में दी हैं, उसमें लिखा है assistnace is being provided in the shape of subsidy and loan in district Hissar to 64545 persons. इसके मुताबिक हिसार में 64545 लोगों को असिस्टेंस दी है यानि हिसार सारे हरियाणा में टौप पर है। इससे हम यह समझते हैं कि हिसार में ज्यादा पावर्टी है और वह सारे हरियाणा में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। हम यह कहते हैं जिन एरियाज को बैकवर्ड आईडैटीफाई किया हुआ है, इसके मायने यह है कि सरकार ने उन एरियाज पर खास तौर पर तवज्जो देनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिन एरियाज को आईडैटीफाई किया हुआ है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके साथ ही साथ हम गरीब आदमी की बात करते हैं। जो स्कीमें गरीब आदमी को ऊपर उठाने के लिए बनाई जाती हैं, उन पर बिल्कुल अमल नहीं होता। एफ०एम० साहब कहते हैं कि 61 परसैंट पर कैपिटा इन्कम बढ़ी है लेकिन दूसरी तरफ पावर्टी लाईन के नीचे की फिरगर 30.2 परसैंट रही है। 61 प्रति तात पर कैपिटा इन्कम अगर गरीब लोगों की बढ़ी होती तो पावर्टी लाईन के नीचे के फिरगर 30.2 परसैंट न होती। सरकार ने 20 प्वायंट प्रोग्राम बनाया है। इसका मकसद है गरीबों को ऊपर उठाना। इस प्रोग्राम के तहत अमीर लोगों को ऊपर उठाने की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अमीर आदमी अपनी देखभाल खुद ही कर लेंगे। उनके पास साधन हैं, अगर अपनी देखभाल वे खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा लेंगे, उनके

लिये कोई मुच्चि कल काम नहीं है। सवाल गरीबों का है, लेकिन गरीबों के लिए जो प्रोग्राम बनाये जाते हैं, उन पर पूरी तरह से अमल नहीं किया जाता।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक एग्रीकल्चर सैक्टर की बात आती है, इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि हरियाणा सूबा कृषि प्रधान प्रदे 1 है, यह नार्मली एग्रीकल्चर पर डिपैंड करता है बजट में एग्रीकल्चर की तरकी के लिए जो रकम रखी है, वह टोटल बजट का 11.8 परसैंट है। एक तरफ हम एग्रीकल्चर की दोहाई देते हैं और दूसरी तरफ इसके लिए बहुत कम पैसा रखा जाता है। Explanatory memorandum on the Budget for 1985–86 के पेज 115 पर फण्डज की एलोके अन की फिगर्ज दी हुई हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि आप थोड़ी देर में धंटी बजा देंगे। इस मैमोरैंडम में डिप्रैंट स्कीम्ज के लिए पैसे की एलोके अन की हुई है। पिछले साल दो आईटम्ज कौटन सीड और हाईब्रीड बाजरे के लिए बजट में एलोके अन हुई थी। उसमें से 0.26 लाख रुपया कौटन सीड का और 24 लाख रुपया हाईब्रीड बाजरे का सरैंडर कर दिया। ये कहते हैं कि हम सर्टिफाइड बीज नहीं खरीद सके। यह एग्रीकल्चर सैक्टर की पोजि अन है। अल्टीमेटली क्या पोजि अन बनेगी, यह देखने वाली बात है। जितना रुपया बजट में रखा जाता है, उसका भी सही इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आप पैसैंजर टैक्स की रिकवरी को देख लीजिए। गवर्नर्मैंट का एस्टीमैंट सवा 7 करोड़

रूपया रिकवर करने का था लेकिन रिकवरी सिर्फ 6.6 करोड़ रूपये की हुई है। जिस तरह पैसेंजर टैक्स की रिकवरी में कमी हुई, इसी तरह और आइटम्ज में भी हुई है। अब बिजली का मामला ले लीजिए। बिजली को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो ट्रांसफार्मर्ज सड़ जोते हैं, वे कई कई महीने तक पड़े रहते हैं, उनकी न रिप्लेसमैंट होती है और न रिपेयर होती है। इनकी जल्दी से जल्दी या तो रिपयेर होने चाहिएं या उनकी रिप्लेसमैंट होनी चाहिए। महकमे के मुलाजिमों की गलती से अगर किसी आदमी को बिजली नहीं मिलती और उसको नुकसान होता है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले दिनों किसान की फसल तबाह हो गई। सरकार न किसानों कास आवियाना एक साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है आशाढ़ का भूला आशाढ़ में धर वापिस आ जाए जो उसको भूला नहीं कहते।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने मेवाल डिवैल्पमैंट बोर्ड बनाया। बोर्ड बनाने का मकसद तो अच्छा है, लेकिन मेवात की डिवैल्पमैंट क्या कर रहे हो ? नाम तो इसका रखा है मेवाल डिवैल्पमैंट बोर्ड, लेकिन इसकी डिवैल्पमैंट के लिए अलग से पैसा देते ही नहीं। बोर्ड का अपना अलग फण्ड नहीं है और यह फण्ड इसके औवर एंड अबव होना चाहिए। इन्होंने दूसरे महकमों के लिए जौ पैसा रखा है, उनसे फण्ड निकाल कर मेवात की डिवैल्पमैंट के लिए रख दिया और मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड बना दिया। पिछले साल इसके लिए 2.40 करोड़ रूपये की एलोके न

की थी। इसमें से एथ्स्टमेटिड खर्च 1.80 करोड़ रुपए आया, बाकी 60 लाख रुपया बचा लिया। मालूम नहीं यह बचाया हुआ 60 लाख रुपया, किसी को चौधरी साहब ने हिसार में दे दिया। अफसोस की बात यह है कि जितने रुपये की एलोके न छोती है, वह भी पूरे तौर पर खर्च नहीं किया जाता, उसमें से भी बचा लिया जाता है। इन एरियाज को जो रुटीन में एलोके न छोती है, उसके ओवर एंड अबव जाकर पैसा दिया जाना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब, मेवात एरिये की एक और प्रौद्योगिकी है। बोर्ड को दफतर गुड़गांव में है, इसको नूह में फ्राफ्ट किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो दफतर मेवात बोर्ड में कंसर्न रखते हैं, उन सबको मेहरबानी करके नूंह में फ्राफ्ट कर दिया जाए। नूह एक सैंट्रल प्लेस है, लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। इसलिए इन सभी दफतरों को नूंह में फ्राफ्ट किया जाए। मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड के जो आफिसर हैं, इनको भी नूंह में फ्राफ्ट किया जाए लेकिन ये आफिसर नूंह में रह कर राजी नहीं। नूंह में उनके रहने के लिए सरकार जगह नहीं देतील। जब सरकार आफिसर्ज को रहने की जगह ही नहीं देती तो काम कैसे चलेगा? जब यह आईडैटिफाईड है कि मेवात बैकवर्ड है और उसकी डिवैल्पमैंट करनी है तो मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड का चार्ज जिसके पास है उसी को यहां का डिप्टी कमि नर लगा दिया जाए अगर आप चाहते हैं कि उस एरिया का सही मायनों में विकास हो जाए, तो मैं अर्ज करूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब सीरियसली और संजीदगी के साथ इस तरफ पूरी तवज्ज्ञों दे। ये खुद देख कर आए हैं और इस बात को मानेंगे कि

भायद इसका जो मक्सद था वह मौके के मुताबिक पूरा नहीं हुआ है। मेरी यह दरख्वास्त है कि उसको पूरा करने के लिए पूरी कोटि टा की जाए।

डिप्टी स्पीकर साहब, पोल्टरी के लिए हरियाणा सरकार वह सुविधा नहीं देती जो पंजाब में हासिल है। नतीजे के तौर पर अमृतसर और गुरदासपुर के लोग चीपर रेट पर अपनी चीजें दिल्ली में बेच जाते हैं क्योंकि वहां कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट अन कम है। सन 62 में जब कैरों साहब चीफ मिनिस्टर होते थे तो नूंह और फिरोजपुर झिरका में पोल्टरी ऐक्स्टैंन सेंटर बने थे लेकिन फिरोजपुर झिरका वाला सेंटर रैस्ट हाउस में तबदील हो गया और नूंह वाले सेंटर की बिल्डिंग सरकार की तवज्जो न होने के कारण वैसे ही खत्म हो गयी। तो मेरी यह गुजारि टा है कि जितनी तवज्जो इस तरह के कामों में पंजाब सरकार देती है कम से कम उतनी तवज्जो तो हरियाणा सरकार को देनी चाहिए ताकि लोग आसानी से दिल्ली में कम्पीट कर सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक पीने के पानी का मामला है, इन्होंने खुद कहा है कि इनके पास 574 प्रौद्योगिकीय बिलेजिज हैं। हमारे यहां कुछ इलाका ऐसा है जो दो पहाड़ों के बीचे में है और वहां पीने का पानी नहीं। लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर कहीं पानी है तो उसकी सप्लाई अ योर्ड नहीं है। मेरी सरकार से गुजारि टा है कि वहां जैनरेटर सैट लगाए जाएं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके। पानी

बहुत पतली चीज है। अगर यह सरकार लोगों को पानी भी नहीं दे सकती तो इससे और क्या तवक्को की जा सकती है। इसे चाहिए कि जहां पानी का इन्तजाम नहीं है, वहां उसका सही इन्तजाम किया जाए। सारी स्टेट में ये देखें कि जहां जहां पानी दिया गया है वह कागजों पर दिया गया है या असल में लोगों को मिल रहा है ? इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि गर्भ के मौसम में तो दिक्कत और ज्यादा होगी।

डिप्टी स्पीकर साहब, ब्लॉक समितिज के इलैक अन्ज का यहां जिक्र आया था लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बिना वजह जब चाहे इलैक अन मुल्तवी करा दिए जाते हैं। मैं तो यहां तक कहूँगा कि जुड़ी तायल ऑफिसर्ज को भी हिदायत दी जाती है कि आप ऐसा फैसला कर दें, लोग तो इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब का नाम लेते हैं लेकिन यह बात कहां तक ठीक है यह इनको पता होगा। (विध्न)

श्री उपाध्यक्षः आपको जुड़ी तायरी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए।

चौधरी तैयब हुसैनः मैं तो ऐरजैकिटव के जुड़ी ताल ऑफिसर्ज के बारे में कह रहा हूँ। I do not mean the judicial officers who come under the High Court. (Interruptions) I am referring to the executive officers who are dealing with some quasi judicial matters. (विध्न) अगर आप खुल कर ही मेरे से

कहलवाना चाहते हैं तो मेरा मतलब एस0डी0एम0 और डिप्टी कमि नर से है।

डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने कहा है कि सड़क से हर गांव को कनैकट कर दिया है। यह इन्होंने दावा किया हुआ है लेकिन खुद ही इकानौमिक सर्वे औफ हरियाणा ने माना है कि हमारे पास 149 विलेजिज सड़क से कनैकट होने को बाकी हैं। ये सड़कें गुडगांव जिला में भी हैं और दूसरे जिलों में भी हैं। (विधन) आपने स्टेटमैंट तो दे दी लेकिन ऐकचुअली सारे गांव सड़क से कनैकट नहीं हुए हैं। लगभग 98 परसैंट गांव सड़क से कनैकट हुए हैं। मेररबानी करके बाकी गांवों को भी सड़क से कनैकट करवा दीजिए। (धांटी) मैं तीन चार मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप वाइन्ड अप कीजिए क्योंकि यह निर्णय हुआ है कि 15 मिनट लीडर आफ दी ग्रुप को आधा धांटा लीडर आफ दी अपोजी न को और बाकी मैम्बर्ज को दस दस मिनट का समय दिया जाएगा।

चौधरी तैयब हुसैन: डिप्टी स्पीकर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि नूंह जैसी जगह में आज तक जुड़ी आयल कोर्ट नहीं है जबकि 1954 में वहां सब डिविजन बन गया था। नूंह और फिरोजपुर झिरका के सारे लिटिगेंट्स गुडगांव आते हैं। गुडगांव वाले वकील यह नहीं चाहते कि कोर्ट वहां चली जाए। हाई कोर्ट वाले कहते हैं कि जुड़ी आयल ऑफिसर को रहने के लिए वहां

मकान नहीं हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड इतने अर्से से क्या कर रहा है यदि वह एक मकान भी वहां नहीं बना सकता है जिसमें जुड़ी टायल औफिर जाकर रह सके। यह इनकी परफारमैंस है। (धांठी)

डिप्टी स्पीकर साहब, स्वर्गीय इन्द्रा गांधी के कत्ल के बाद जो बरबादी हुई सरकार ने उसकी फिगर 150 की दी है। लेकिन मेरे ख्याल में यह फिगर इससे कहीं ज्यादा है। (विध्न) इस बारे में आपको परे गान नहीं होना चाहिए। आप इसकी जुड़ी टायल इंक्वायरी करवा लें ताकि बात एक तरफ हो जाए। मैंने गवर्नर ऐंड्रेस पर बोलते हुए भी यह बात कही थी लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। इस प्वायंट को टन तक नहीं किया।

चौधरी भजन लाल: अकालियों की भाशा क्यों बोलते हों ?

चौधरी तैयब हुसैन: मैं अकालियों की भाशा नहीं बोलता बल्कि इंसाफ की बात कहता हूं, कहता रहा हूं और कहता रहूंगा। आप कहते तो हैं कि अकाली बुरी बात कर रहे हैं लेकिन यह बात भी ठीक है कि आप लोगों को मरवा रहे हैं। औफिसर्ज ने मेरे सामने लोगों को मरवाया है (गोर)

डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक क्वैरीज के मामले का सम्बंध है, उसकी हर रोज यहां और अखबारों में चर्चा होती है।

फरीदाबाद की बात यहां कही गई। आपके सामने इन्होंने माना कि वहां गोली चली। चाहलका, सूदे और सोहना की क्वैरीज में भी आप जानते हैं गलत तौर पर मामलात चल रहे हैं। अगर उनको सरकार ने अनेलाइज कर ले तो लोगों को काम मिलेगा, सरकार की आमदनी बढ़ेगी और वहां मामलात ठीक होंगे। इस तरफ तवज्ज्ञों देने की जरूरत है।

जहां तक बजट का ताल्लुक है इसमें इन्होंने बस का किराया बढ़ा दिया और दूसरे टैक्स भी बढ़ाए हैं। इससे आम आदमी पर बहुत असर पड़ेगा। गेहूं की कीमत तो कम बढ़ी लेकिन इन पुट्स और दूसरी जरूरत की चीजों की कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि इस बढ़ौतरी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरफ भी सरकार को तवज्ज्ञों देने की जरूरत है। (विध्न)

डिप्टी स्पीकर साहब, कोयले के बारे में मैंने कल एक पौजिटिव बात कही थी। वह बात आज आपने अखबारात में भी देखी होगी। सुरजेवाला जी उस बात को डायरैक्टली तो नहीं माने लेकिन इनडायरैक्टली माने हैं कि गलती से एक रैक थर्मल प्लांट में आ गया था। डिप्टी स्पीकर साहब, फैक्ट यह है कि कोयले का अच्छा रैक तो प्राईवेट इंडस्ट्री को दे दिया गया और खराब कोयले का रैक थर्मल प्लांट में रख लिया गया। उस खराब कोयले की वजह से थर्मल प्लांट चलने से रुक गया। मैं आपकी मारफत इनसे अर्ज करूँगा कि ये इस बात की इंक्वायरी करवा लें। (विध्न)

चौधरी भजन लालः यह मामला तो रेलवे से सम्बन्धा
रखता है।

चौधरी तैयब हुसैनः थर्मल प्लांट वालों ने ऐसा किया
है।

चौधरी भाम ॒र सिंह सुरजेवालाः हमें यह बात मालूम
नहीं।

चौधरी तैयब हुसैनः आप इंक्वायरी करवा लीजिए।
अगर आपको मालूम नहीं तो इसमें क्या बुराई है कि सही चीज
आपके सामने आ जाए।

चौधरी भाम ॒र सिंह सुरजेवालाः पता करवा लेंगे
लेकिन थर्मल प्लांट्स और बिजली बोर्ड इंडस्ट्रीज से डील नहीं
करते।

चौधरी तैयब हुसैनः डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार को
यह भी मौनिटर करना चाहिए कि विजिलैंस डिपार्टमेंट ने कितने
ऑफिसर्ज के खिलाफ रिपोर्ट दी है और उनके विरुद्ध क्या
कार्यवाही हुई है ?

ला एंड आर्डर के मामले का जहां तक ताल्लुक है,
उसके बारे में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसको सही ढंग से
चलने दिया जाए। ज्यादा अच्छा हो यदि सियासी इन्टरफ
ीयरैंस न हो। तो मैं अर्ज करूंगा कि सियासी इंटरफीयरैंस

को रोका जाए। साथ ही मैं यह भी अर्ज करूँगा कि टैकिसज की जो प्रपोजल्ज दी गई हैं, उनको बिल्कुल हटाया जाए वरना इससे गरीब आदमी और ज्यादा गरीब हो जाएगा। यह कमर तोड़ बजट है। इसमें बिजली और ऐग्रीकल्चर की तरफ वह तवज्जो नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। इन अल्फाज के साथ मैं आपका भुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे टाईम दिया।

चौधरी ई वर सिंह (पुंडरी): डिप्टी स्पीकर साहब, जो बजट सागर राम गुप्ता जी ने पेंट किया है, वह बैलेन्सड बजट है, हरियाणा की प्रगति को जाहिर करता हैं सरकार के नि चय भी निरन्तर हरियाणा को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि सन 1970–71 के स्थिर मूल्यों के हिसाब से 1979–80 में 1200 करोड़ रुपये की हमारी आमदनी थी, 1983–84 में 1547 करोड़ रुपये तक हो गई और 1984–85 में 1592 करोड़ हो गई। इसी तरह से प्रैजैन्ट रेटस पर राज्य की आय, सन 1979–80 में 2423 करोड़ रुपये थी और सन 1983–84 में 4320 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। डिप्टी स्पीकर साहब, तीन सैकटर्ज होते हैं, प्राइमरी, सैकेण्डरी, टर्टीयरी। इनमें इसी तरह से हमारे यहां वृद्धि होती जा रही है। पहला प्राइमरी सैकटर ऐग्रीकल्चर और अलाईड एकिटवीटीज से सम्बन्धित है, दूसरा मैन्यूफ “कचरिंग/इंडस्ट्री से और तीसरा जनरल सैकटर से। सभी में उन्नति हो रही है। गवर्नमैंट की फिर्गर्ज के हिसाब से हमारी पर कैपिटा इनकम सन 1979–80 में 1949 रुपये थी, वह बढ़ कर

1983–84 में 3147 रुपये हो गई है। इस तरह से चार साल में 61 परसैंट बढ़ौतरी हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना में 1638 करोड़ रुपया खर्च हुआ और नैचुरल कलेमिटिज के लिए भी अधिक रुपया रखा गया, वह पैसा इसके अलवा है। ऐम्प्लाईज की ए0डी0ए0 की कि तें भी बढ़ीं, वे प्लान में भासिल नहीं हैं, वे नान प्लान में हैं। नैचुरल कलेमिटिज और जो दूसरी राहत दी गई, उन पर 570 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है। जहां तक छठी प्लान का ताल्लुक है इरीगे अन एण्ड पावर को प्रायरिटी दी गई है। इन पर 966 करोड़ रुपया खर्च किया गया हैं यह कुल योजना का 59 परसैंट है। इन सालों में हमारा इरीगे अन का 3.52 लाख हैक्टेयर एरिया बढ़ा है, एक लाख टयूबवैल्ज लगे हैं, बिजली उत्पादन क्षमता 362 मैगावाट हुई है। इसी तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में हाई यील्ड वैरायटी ज्यादा एरिया में ले गये हैं, फर्टिलाइजर का अधिक प्रयोग किया गया। इसका नतीजा यह है कि पैदावार बढ़ाने में हमारे किसानों का बहुत बड़ा हाथ है। वे नई टैक्नोलोजी को समझते हैं और उनके योगदान से ही पैदावार बढ़ी है।

डिप्टी स्पीकर साहब, यहां पर एस0वाई0एल0 की बात की गई और कल भी एस0वाई0एल0 के बारे में रैजोल्यू अन आया था उस पर भी काफी डिटेल में चर्चा हुई। उस वक्त यह भी कहा गया कि जे0एल0एन0 कैनाल और लिफट इरीगे अन स्कीमों के लिए पानी की कमी है और यह सरकार सो रही है। पहली चीज

इनफ्रास्ट्रक्चर की होती है। वह सरकार ने बना दिया है। जब हमने पहले इनफ्रास्ट्रक्चर पैदा कर दिया और उस पर रूपया भी खर्च कर दिया तो हमारा क्लेम बनता है। इसी तरह से लिफट इरीगेन स्कीम हैं, उनकी भी हमारे यहां और जरूरत है। अम्बाला जिले में खास तौर से है क्योंकि यहां से पानी बह कर आगे चला जाता है और उस इलाके को पानी नहीं मिलता है। इसी प्रकार से करनाल और कुरुक्षेत्र के जिलों को भी जरूरत है। वहां रेलवे लाईन और जी०टी० रोड के बीच पूर्व की ओर सूखा हिस्सा पड़ा है। उसके लिए लाडवा और नलवी की स्कीम बना दी। यह पैडी और गन्ना ग्रोइंग एरिया है। यहां पर पानी आयेगा तो और ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। ७० करोड़ रूपया एस०वाई०एल० के लिए अगले साल में रखा गया है। सुरजेवाला जी ने बताया है कि जून १९८७ तक एस०वाई०एल० कैनाल पूरी हो जायेगी जो पंजाब के हिस्से में बननी है। इससे जो हमारी सिवानी, लोहारू, जुई और नंगल आदि की लिफट इरीगेन स्कीमें हैं उनमें पानी आयेगा। जे०एल०एन० कैनाल में भी लगभग लिफट इरीगेन स्कीम है। इस नहर के चालू होने से सभी जगहों पर पानी पहुंच सकेगा। दूसरे हमारी नहरों का सिस्टम इंटर कनैक्टड है। भाखड़ा और डब्ल्यू०जे०सी० का पानी एक जगह से दूसरी जगहों पर जा सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला जिले के बारे में सभी भाई कह रहे हैं कि यहां पर भी पानी आना चाहिए। जब हमें

एस०वाई०एल० का पानी मिल जायेगा तो अम्बाला का जो ऊपर का हिस्सा है, दादुपुर से नहर निकाल कर उस हिस्से में पानी पूरी तरह से दिया जा सकता है। नहरों की तथा नालों की लाईनिंग के लिए भी 26 करोड़ रुपया रखा गया है और साथ ही हर महकमें में मोनिटरिंग और ईवैल्यूए अन सैल्ज बना दिये गये हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि नहरों में खास तौर से जो लाइनिंग का सिस्टम है वहां हर जगह पर बराबर का काम नहीं है। बाज जगह पर नहर के काम में अच्छा मैट्रियल लगा है और बाज जगह कमी है, स्पैसिफिके अन के मुताबिक नहीं है। जो पहले रेमिंग होती है वह अच्छी होनी चाहिए। पहला कोट जो सीमैंट और रेत का करतेत है, वह ठीक होना चाहिए। वहां पर रेत का प्रयोग ठीक तरह से इंजीनियर्ज नहीं करते हैं। उसका कारण यह है कि वहीं रजबाहों से रेती निकाल कर लगा देते हैं जिसमें मिटटी का अं अ होता है, वह सीमैंट को खा जाता है। एक और पांच की रे गों से सीमैंट और रेत मिला कर पहला कोट एक सूत का होना चाहिए और दूसरा कोट एक और तीन की रे गो से सीमैंट और रेत मिला कर होना चाहिए लेकिन वह हर जगह पर स्पैसिफिके अन के मुताबिक नहीं होता है। इस और ज्यादा विजिलेंस की जरूरत है। बाज जगहों पर देखा जाता है कि धाट साल भर में टूट जाता है और माइनर्ज में खास तौर पर ऐसा होता है। जब भोर गाह सूरी के टाईम की मीनारें 440 साल से खड़ी हैं और उनकी एक ईंट निकालने से भी नहीं निकलीती है तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए ताकि काम ठीक हो सके।

इसी तरह से 15 लाख हैक्टेयर भूमि पर जहां बाढ़ का पानी आ जाता था उसका भी बचाव कर लिया गया है। सोनीपत और रोहतक में जो ड्रेन नम्बर आठ निकलती है उसकी कैपैसिटी बढ़ाने के लिए 14 करोड़ अगले साल के लिए रखा गया है, उससे बाढ़ की काफी रोकथाम होगी।

नाथपा झाकड़ी की भी यहां पर बात की गई कि इस स्कीम को हरियाणा सरकार ने सैंटर को दे दिया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। सैन्टर से जो पैसा हमें आना था वह लोन के रूप में आना था, अगर उस पैसे को सैन्टर इस प्रोजैक्ट पर अपने हाथ से लगा दे तो हमें क्या नुकसान हैं हरियाणा सरकार अपने प्रोजैक्ट जो आलरेडी हाथ में हैं, जैसे पानीपत का थर्मल प्लांट, यमुनानगर का हाईडल प्रोजैक्ट, उन्हें ही पूरा कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। सैन्टर नाथपा झाकड़ी के प्रोजैक्ट को तेजी से पूरा करेगा। हरियाणा को अपना हिस्सा 40 प्रति अंत इस प्रोजैक्ट में से मिलेगा। सैंटर में जो हमारा खाता है उसमें वह इस प्रोजैक्ट पर लगाये पैसे को लिख देगा और बाद में इसकी वसूली होती रहेगी।

इसके साथ ही बिजली भी अगले फाईव ईयर प्लान में 898 मैगावाट पैदा की जा सकेगी। अगली फाईव ईयर प्लान में 430 मैगावाट पानीपत में, 420 मैगावाट यमुना नगर में और 48 मैगावाट हाइड्रो जनरेंटन जिसका आन आफ हमारे अपने हाथ में होगा, हम पैदा कर सकेंगे। इसके अलावा एटौमिक पावर हाउस के लिए भी सरकार कोटा कर रही है। हमारे यहां पर जहां तक

फूड ग्रेन्ज की पैदावार का ताल्लुक है, इस वर्ष 71 लाख टन फूड ग्रेन्ज पेदा हुए हैं। अगले साल 75.1 लाख टन अनाज का लक्ष्य रखा गया है इसी तरह से भौगोर केन में 7.65 लाख टन और काटन बेल्ज का लक्ष्य 8 लाख नियत किया गया है। हमारे यहां पर गन्ने की पैदावार तमिलनाडु और महाराश्ट्र के मुकाबले कुछ कम है। लेकिन काटन की पैदावार में पर एकड ईल्ड के हिसाब से हम सारे हिन्दुस्तान में फर्स्ट हैं। एग्रीकल्चर के साथ ही हौर्टीकल्चर के लिए भी पैसा रखा गया है। क्योंकि यह देखा गया है कि महेन्द्रगढ़, गुडगांव, भिवानी इत्यादि के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर टोटल एरिया के मुकाबले में इसके लिए एरिया बहुत कम है। इससे यह जाहिर होता है कि फलों और सब्जियों की कात बहुत ही कम है। इसको बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर इस बजट में प्रावधान किया गया है। जहां तक इन्टैग्रेटेड रुरल डिवैल्पमैंट स्कीम और नरेप की स्कीमों तथा दूसरी स्कीमों का सम्बंध है, इनके द्वारा गरीब आदमियों का भला सोचा गया है। रुरल एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम जैसी योजनाएं बनाकर गरीब लोगों की भारी मदद की गई है क्योंकि देहात में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको 12 महीने का काम नहीं मिलता। खेती का काम तो मौसमी है। जब बुआई या कटाई होती है, उस वक्त काम होता है या हमारे इलाके में पैडी की लगाई या कटाई के समय थोड़ा बहुत काम मिल जाता है, वरना काम नहीं मिलता। सारे साल पूरी दिहाड़ी का काम मिल सके। 100 दिन के काम की रुरल एम्पलायमैंट गारन्टी स्कीम के तहत 88 हजार फैमिलिज को लाभ

होगा। जो भाई गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिये भी यह सरकार काफी कुछ कर रही है। सर्वे कराने के बाद यह पता चला कि हरियाणा में 8 लाख परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। 5 लाख परिवारों को इसी इन्टैग्रेटेड रुरल डिवैल्पमेंट स्कीम के अधीन कर्ज दिये चुके हैं। आखिर कर्ज का मतलब साधन मुहैया करवाना होता है। कोई भैंस लेगा, भेड़ बकरी लेगा, सूअर लेगा, कोई झोटा बुगड़ी लेगा या अपना कोई काम धन्धा भुरू करेगा। कई बार तो ये लोग सौ सौ रुपया रोज तक भी कमा लेते हैं। इस तरह से उनकी गरीबी दूर होगी। यह भी अन्दाजा लगाया गया है कि अगले साल इन 5 लाख में एक लाख के करीब और आदमी जुड़ जायेंगे। जहां तक बाकी 2-3 लाख के करीब गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का ताल्लुक है, उनके लिये भी मुझे यही मालूम हुआ है कि कुछ लोगों को कर्ज दिये गये हैं उनके पास अब कुछ न कुछ साधन हो गये हैं जिनसे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। स्पीकर साहब जो 2-3 लाख बाकी के परिवार हैं, उनको भी यह सरकार साधन मुहैया करा रही है। इसी तरह से कोआप्रेटिव के लिए भी 255 करोड़ रुपये का लोन एक साल में दिया गया है। हैफैड की भी बहुत सी स्कीम्ज हैं जिनके लिए 145 करोड़ रुपया रखा गया है। (घंटी) मैं एक दो मिनट में खत्म करता हूं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज के लिए भी हमारी सरकार काफी कोरिटा कर रही है। एक तेल भांधक कारखाना पानीपत में लगा रही है। इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग पंचकूला में और गुडगांव में लगाये जा रहे हैं। इसी तरह से वीवर्ज के लिए

भी हम खास तौर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा तीन भूगर मिल्ज इस साल लग चुकी हैं और तीन भूगर मिलें अगले सालों में भी लगाने का प्रोग्राम है। नान रैंजीडैंट इंडियन्ज के पास सबको पता है कि काफी पैसा है। ऐसे 368 लोगों ने हमारे यहां पर कारखाने लगाने की इच्छा जाहिर की है। आपको पता है कि इनको कारखाने लगाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। जितने कारखाने हमारे यहां लगेंगे उतनी ही स्टेट की इन्कम बढ़ेंगी। टैक्सों की वसूली ज्यादा होगी। इसके अलावा 6300 अनएम्पलायेड एजुकेटिड परसन्ज को 25000 रुपए तक काच लोन दिया गया है ताकि वे अपना काम धन्धा जारी कर सकें। वन विन्डो सर्विस हमने इसके लिए प्रोवाइड कर रखी है, वहां पर सारे डिपार्टमेंट्स के कन्सन्ड आदमी होते हैं। टैक्नीकल आदमी भी होता है, बैंक वाले भी होते हैं, हरियाणा फाइनैंशियल कारपोरे न और एच०एस०आई०डी०सी० का आदमी भी वहीं पर होता है। वह उनको सलाह देते हैं। इससे हरियाणा में इंडस्ट्रीज को बड़ा भारी प्रोत्साहन मिला है इसके साथ ही सब को यह पता है कि हमारी स्टेट एक वैल्फेयर स्टेट है। हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हरिजन हैं या बैकवर्ड हैं, उनके लिए यहां पर 33 करोड़ रुपया रखा गया है वैल्फेयर स्कीम द्वारा 55000 परिवारों को फायदा होगा। जो स्पैल कम्पोनेंट स्कीम है, वि शेकर फाड्यूल्ड कास्ट्स के लिए उसके लिए हर महकमे में सुविधा प्रदान करने के लिए 198 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह सब सहूलियातय आपके सामने हैं कि अगर किसी आदमी की इन

सर्विस मौत हो जाये तो उसने अगर कोई कर्जा लिया हुआ हो, मकान बनाने के लिए, विवाह के लिए, उत्सव के लिए या साईंकल खरीदने के लिये, यह सब कर्जा माफ हो जायेगा। इसके साथ ही ज्वायंट इन ऑरेंस स्कीम जो बनाई गयी है, यह भी एक बड़ी भारी सहूलियत है इसके अलावा दूर कन्सैन (एल0टी0सी0) भी दिया गया है कसौली, कटडा और वैश्णो देवी में होलीडे होम्ज हैं, उनके अलावा दूसरी जगहों पर भी यह होली डे होम्ज स्थापित किये जायेंगे। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि धाटे का जितना जिक्र किया गया है, साल के अन्त में उतना धाटा नहीं होगा, उससे कहीं कम होगा। कुछ हमारे करों की वसूली ज्यादा होगी। पिछले दो महीनों में आपने देखा होगा कि करों की बहुत ज्यादा वसूली हुई है। हमारे रिसॉसिज की पोजीशन सारे हिन्दुस्तान में दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में दूसरे नम्बर पर आ गयी है। यह जो धाटा दिखाया गया है, आखिर में जाकर यह इतना नहीं रहेगा। करों की ज्यादा वसूली होने की वजह से, ऐसा होगा। कन्साइनमैट टैक्स हमारे लिए एक विशेष टैक्स है क्योंकि हमारे कारखाने दिल्ली के चारों तरफ बहादुरगढ़, फरीदाबाद, सोनीपत वगैरा में लगे हुए हैं। वे लोग अपना माल दिल्ली में बेचा हुआ दिखाते हैं उसके लिए कांस्टीच्यूनल अमैंडमैंट तो पहले कर दी गयी थी और एक रैजोल्यून हरियाणाच असैम्बली ने भी पास कर दिया था लेकिन अब पार्लियामैंट के अंदर इसकी इनैक्टमैंट होगी। उससे हमें कन्साइनमैट टैक्स मिल सकेगा। हमने इस बजट में इससे साढ़े 44 करोड़ रुपये की इन्कम दिखाई है। यह तो 6 महीने की

आमदनी काच हिसाब लगाया गया है। जब अगले साल में यह टैक्स लागू हो जायेगा तो साल भर में हमारा रैवैन्यू और भी बढ़ जायेगा।

श्रीमती चन्द्रावती: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। यह जो कन्साईनमैंट टैक्स की बात कर रहे हैं, इस बारे में तो अभी फैसला ही है। आप कैसे प्रिज्यूक कर लोगे कि वह जरुर लगेगा। इसके बारे में वित्त मंत्री जी से कहूंगी कि वे जरा स्पष्ट कर दें।

चौधरी ई वर सिंह: सर, इस बारे में दिल्ली में जो हमारे आफिसर्ज की बात हुई है, उसमें यह वि वास दिलाया गया है और प्लानिंग कमी अन ने भी यह कहा है कि इसकी इन्कम आप फिलहाल 50 परसैंट ही डाल लो। (**इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।**) जहां तक किराये भाड़े बढ़ाने की बात का ताल्लुक है अगर पैट्रोल/डीजल का खर्च बढ़ेगा तो किराया भी तो बढ़ेगा। अगर हम डिवैल्पमैंअ चाहते हैं तो टैक्स तो लगने ही चाहिए। स्पिरिट पर या दूसरी चीजों पर टैक्स लगता है, वह जायज है। यह घाटे को पूरा करने के लिए जरुरी है। (धांटी) अन्त में मैं वित्त मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक जुड़ी-जायस और बैलेन्स्ड बजट पे अ किया हैं मैं वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने खूब अच्छा बजट पे अ किया है जिसमें सभी वर्गों को सहूलियतें दी हैं मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा प्रान्त में तरक्की के काम हो रहे हैं, इसी तरह से हरियाणा प्रगति करता रहे। धन्यवाद।

मास्टर फिल प्रसाद (अम्बाला भाहर): स्पीकर महोदय, वित्त मंत्री ने यह जो बजट सदन के सामने रखा है। इस सारे को पढ़कर दो बातें सामने आती हैं। एक तो वही बातें इसमें कहीं हैं जो गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में कहीं थी। उन्हीं बातों को रिपीट किया है। वित्त मंत्री ने यह समझा कि अगर मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव के बारे में वे बातें नहीं कहीं तो ऐसा न हो कि मेरा नम्बर कम हो जाये। दूसरी बात यह है कि वित्त मंत्री ने टैक्स लगाते समय भी भायद गरीब लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया। स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री कहे या कोई और मंत्री कहें एक बात यह कही जाती है कि प्रधान मंत्री के हाथों जो हरियाणा का हित है वह सुरक्षित है। स्पीकर साहब, हरियाणा का हित सुरक्षित होना भी चाहिए क्योंकि वे दे ता के प्रधानमंत्री हैं और हरियाणा इस दे ता का एक हिस्सा है। लेकिन जो बात बार बार मुख्य मंत्री जी कहते हैं भायद यह बात मुख्यमंत्री अपने ऊपर लागू नहीं करते कि मैं भी सारे हरियाणा का मुख्यमंत्री हूं और अम्बाला भी हरियाणा का हिस्सा है। वे इस बात को भूल जाते हैं। अगर वे अम्बाला की ओर ध्यान दते तो आज जो स्थिति अम्बाला की है वह बेहतर नजर आती। स्पीकर साहब, इस बजट में सड़कों के बारे में, पीने के पानी के बारे में और बहुत दूसरी बातों के बारे में कहा गया है। स्पीकर साहब, सप्लीमेंटरी डिमांडज पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा था, यह बात स्वीकार की थी कि कुछ ऐसी सड़कें हैं जो भायद आधा किलोमीटर की हैं या एक किलोमीटर का फासला कवर होता है तो वे सड़कें बनाई जायेंगी। स्पीकर

साहब, कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी और मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अभी भी कुछ गांव अम्बाला में ऐसे हैं जिनका फासला सड़क से आधा किलोमीटर या एक किलोमीटर का है। बच्चे उन गांवों में पढ़ने के लिए जाते हैं। जब बरसात का मौसम होता है तो रास्ते में पानी इकट्ठा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि सड़क से लेकर स्कूल तक पानी भर जाता है और उन बच्चों को बड़ी भारी परे आनी होती है। मैं इस तरह के चार गांवों को जिक्र करना चाहता हूँ। धनकोट, बरनाला, डियाना और टूंडली। इन गांवों के स्कूलों तक पक्की सड़क पहुँचनी चाहिए जिससे कि बरसात के दिनों में बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। स्पीकर साहब, और भी बहुत से गांव हैं जो कि सड़क से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तो केवल चार का नाम लिया है। बरनाला से टूंडली और देवी नगर से घोल गांव की सड़कों के एस्टीमैट चण्डीगढ़ आए थे लेकिन पता नहीं उनका क्या हुआ और ये सड़कें नहीं बनीं। अगर वे सड़कें बन जाएं तो बरनाला से अम्बाला छावनी आने के लिए पांच छः किलोमीटर का रास्ता बच सकता है। स्पीकर साहब, मानकपुर वालों की सारी जमीन डियाना में है लेकिन इन दोनों के बीच में नाला आता है। अगर इस नाले पर एक पुल बना दिया जाए और दोनों गांवों को सड़क से जोड़ दिया जाए तो जमींदार लोग आसानी से अपनी जमीन पर जा सकते हैं। और वहां से अपनी उपज और अनाज वगैरा ला सकते हैं। स्पीकर साहब, देवी नगर से घोल को अगर पक्की सड़क से जोड़ दिया जाए तो घोल के लोगों को जी०टी०

रोड पर आने के लिए सात आठ किलोमीटर का फासला कम जो जाएगा। इस समय वहां पर कच्चे रास्ते से ट्रैक वगैरा तो जाते हैं लेकिन काफी रेत वगैरा उड़ती हैं इस तरफ पी०डब्ल्यू०डी० को ध्यान देना चाहिए। स्पीकर साहब, घोल से लाहरसा और रामदास नगर से सिजावाला वगैरह को जोड़ दिया जाए तो जी०टी० रोड, पटियाला रोड और हिसार रोड आपस में मिल जाएगी और लोगों को सुविधा हो जाएगी।

स्पीकर साहब, रामदास नगर और रत्न गढ़ न पंचायत में हैं और न नगरपालिका में हैं। सरकार इस बारे में सोचे और उनको या तो नगरपालिका में मिलाये या पंचायत में मिलाये। जो इन्होंने पंजोरा ड्रेन निकाली है उससे रत्नगढ़ और रामदास नगर का फासला आधा किलोमीटर का है अगर वहां पर पुल बना दिया जाए तो इनको पटियाला रोड और हिसार रोड से जोड़ा जा सकता है। इस वक्त दोनों गांव के लोगों को सात आठ किलोमीटर का फालसा तय करना पड़ता है। पुल बनने से यह फासला कम हो जाएगा।

स्पीकर साहब, पीने के पानी के बारे में बजट में जिक्र किया गया है। बहुत अच्छी बात है कि गांव गांव में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन इस मामले में अम्बाला भाहर को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता रहा है। स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि अगर अम्बाला में पीने के पानी की दिक्कत न होती तो चण्डीगढ़ की बजाये अम्बाला को राजधानी बनाया जाता। वहां पर

रेलवे स्टेशन नजदीक है, धूलकोट का स्टेशन नजदीक है। वहाँ पर फैक्टरीज लग सकती हैं और भी डिवैलपमैंट हो सकती थी लेकिन पीने के पानी की कमी के कारण भाहर की हालत खराब होती जा रही है। स्पीकर साहब, पिछली दफा भी मैंने कहा था कि पानी के न होने के कारण भाहर की हालत खराब होती जा रही है, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। मैं वहाँ के पानी का नमूना एक भी पी में भरकर लाया था लेकिन वह भी पी होस्टल में रह गई स्पीकर साहब, आप उस पानी को देखते तो वाकई आप कहते कि यह पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है। बात यह है कि वहाँ पर पानी की पाइप लाइन नाले के पास से जा रही है और नाले का पानी उस पाइप लाइन में चला जाता है। अगर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा भी ध्यान दे तो यह समस्या हल हो सकती है। स्पीकर साहब, अगर वह लापरवाही छोड़ कर इस तरफ ध्यान दे तो लोगों को जो कीड़े वाला गन्दा पानी पीना पड़ता है उससे छुटकारा हो सकता है। इस पानी से लोगों को पीलिया तक हो जाता है। मैंने उस पानी को डी०सी० को भी दिखाया था। इसलिए मेरी सरकार से गुजारि था है कि अम्बाला के लोगों के गन्दा पानी पीने से बचाया जाए। यह बहुत जरूरी काम है स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी जब अम्बाला में मिनि सैक्रेटरिएट का फ़ालान्यास करने गए थे तो इन्होंने वहाँ पर कहा था कि इस साल के अन्त तक लोगों को नहर का पीने का पानी मुहैया हो जाएगा लेकिन दुःख की बात है कि आज उस बात को साढ़े पांच साल हो गए हैं लेकिन इस दिन में वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। स्पीकर

साहब, गांवों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है लेकिन इसके साथ ही साथ भाहरों की और भी ध्यान देना जरूरी है जिससे कि पहले वहां पर जो डिवैल्पमैंट हुई है वह खाराब न हो और भाहर गांव न बन जाए। मैं समझता हूं कि सरकार इस और ध्यान देगी।

अम्बाला में सड़कों और गलियों का सिलसिला ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिंट हो जाये तो गन्दे नाले का पानी वहां पर भर जाता है और आने जाने में बड़ी भारी दिक्कत होती है। स्पीकर साहब, वहां पर सिवरेज का काम बहुत पहले भुरु हुआ था लेकिन वह बीच में ही रह गया। इस काम के लिए वहां की कमेटी ने लोन भी लिया था लेकिन वह काम पूरा नहीं हुआ। स्पीकर साहब, सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहीं से भी पचास लाख रुपया या एक करोड़ रुपया अम्बाला के लिए दे दें जिससे कि अम्बाला भाहर को गांव होने से बचाया जा सके। स्पीकर साहब, मैंने अब तक सड़कों और पानी का जिक्र किया है, अब मैं प्राक्षा के बारे में कुछ भाब्द कहना चाहता हूं। इस सदन में बताय गया कि पिछले दिनों 99 प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल अपग्रेड किया गया और 93 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल अपग्रेड किया गया। स्पीकर साहब, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 1977 से लेकर आज तक अम्बाला भाहर में तीन स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। एक स्कूल को हाई स्कूल अपग्रेड किया गया और दो प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल अपग्रेड किया गया। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि टूंडला का मिडिल स्कूल जहां पर लड़कों

की संख्या ठीक है और बिलिंडग भी ठीक है, उसको हाई स्कूल बनाया जाए और सुलतानपुर के स्कूल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बनाया जाये। स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार लड़कियों की शिक्षा पर काफी जोर दे रही है और ग्यारहवीं तक शिक्षा मुफ्त कर दी है। अम्बाला भाहर में बलदेव नगर में गल्झ स्कूल हैं उसको प्राईमरी स्कूल से मिडिल स्कूल बनाया जाए। स्पीकर साहब, इस समय मोतीनगर में प्राईमरी तक स्कूल है। छठी कक्षा में पढ़ने के लिए बच्चों को रेलवे लाइन पार करके स्कूल जाना पड़ता है। रेलवे लाइन पार करने में बच्चों का ऐकसीडैंट होने का खतरा है। मरी सरकार से दरखास्त है कि मोती नगर के प्राईमरी स्कूल को मिडिल स्कूल अपग्रेड कर दिया जाये जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को रेलवे लाइन पार न करनी पड़े। स्पीकर साहब, जिन जिन स्कूलों के बारे अति आव यक था, उनके बारे में, मैंने सरकार के नोटिस में ला दिया है। आ गा है सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

13.00 बजे।

स्पीकर साहब, अब मैं हास्पीटल्ज के बारे में कुछ भी कहना चाहूंगा कि इस वक्त अम्बाला में केवल चार हास्पीटल्ज हैं। सिविल हस्पताल, मिट्टन हस्पताल और कैंट में एक गवर्नर्मैट हस्पताल और एक मिलट्री हस्पताल है लेकिन वहां पर कोई मैडीकल कालेज नहीं है। केवल रोहतक में एक मैडीकल कालेज है। लुधियाना एक छोटा सा भाहर है, वहां पर दो मैडीकल कालेज

हैं, इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि रोहतक की तरह एक मैडीकल कालेज की अम्बाला में भी स्थाना की जाए ताकि हमारे हरियाणा के बच्चों को दूसरे राज्यों में प्रवेश पाने के लये न जाना पड़े। मैडीकल कालेज बन जाने से हमारे इन हस्पतालों का योगदान भी उसे मिल पाएगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आग्रह करूंगा कि 1980 में मुख्य मंत्री महोदय ने एक नये सिविल हस्पताल का फ़िलान्यस किया था लेकिन वह काम भी अभी तक अधूरा है। कर्मचारियों के लिए क्वार्टर्ज तो बन गए हैं, लेकिन दूसरे काम को सिरे चढ़ाने की भी सरकार कोटि रुपये पर एक डंगरों का हस्पताल भी है जिसकी हालत बड़ी खसता है। उस तरफ भी सरकार को अब योग्य ध्यान देना चाहिए।

इससे अगला प्वायंट मेरा यह है कि आज हरियाणा के अंदर गरीब लोगों को गरीब किसानों को और गरीब हरिजनों को ऊपर उठाने की अति आवश्यकता है। सरकार ने इन गरीब आदमियों को लोन देने का प्रावधान किया हुआ है। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे बस रहे हैं और जिन तक यह सरकार की इमदाद पहुंचनी चाहिये, वह उन तक नहीं पहुंच रही है। वह राटि ऊपर ही ऊपर, अधिकारियों के लैवल पर ही इधर उधार हो जाती है। जिन गांवों में यह राहत मिलनी चाहिये, वहां तक पहुंच ही नहीं पाती और गलत आदमियों तक यह सहायता ऊपर मिलमिला कर तकसीम कर दी जाती है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे। मिसाल के तौर

पर एक आदमी तो भूख से मर रहा है और दूसरा एक या दो टाईम कम से कम खाना तो खा लेता है उसकी बजाए जो आदमी भूखा मर रहा है, उसको पहले सहायता मिलनी चाहिए, दूसरे को बाद में। मेरा कहने का मतलब यह है कि पैसाव बांटते वक्त अधिकारीगण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिसकी हालत ज्यादा खस्ता है, कौन इस कर्जे का पहले हकदार है। अगर सही आदमी तक सरकार का यह पैसा न पहुंचे तो गरीब आदमी को इससे क्या लाभ हो सकता है ? कई लोगों ने तो गरीबों को लोन दिलवाने का एक किस्म का यह धन्धा ही भुरु कर रखा है और वे लोगों से पैसे ले लेकर यह काम करवाते हैं। फर्ज कीजिये एक आदमी को भैंस खरीदने के लिए 4000 रुपया देना है तो उस पैसे में से डेढ हजार रुपये के करीब काट लिया जाता है। उसे कह देते हैं कि चलो आप को भैंस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही अब कुछ बेचने की जरूरत है। इससे लेने वाला भी खुट्टा हो जाता है और जो लोग इधर उधर का धन्धा करते हैं, वे भी खुट्टा हो जाते हैं। यह भी करवा दिया जाता है कि अगर किसी की भैंस मर जाए तो डाक्टर को 200 रुपये देने पर उसका पोस्टमार्टम भी तैयार ही मिलता है जिससे बाद में उनका लोन भी माफ करवा दिया जाता है। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि इन लोगों से गरीब आदमियों को बचाया जाए और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि गरीब आदमियों के पास लोन की राट्टा पहुंच सके।

इससे अगला प्लायंट, बसिज के जो रोजाना एक्सीडेंट्स होते हैं उस बारे में मेरा सरकार से यह सुझाव है कि यात्री बीमा स्कीम चालू की जाए। यात्रियों से टिकट के साथ ही एक या दो पैसे जितना उचित समझें ले लें ताकि यात्री को इस बात का पता हो कि जब मैं गाड़ी मैं बैंठ गया तो मैं सेफ हूं। अगर दुर्भाग्यवे किसी यात्री की तरह से मृत्यु को जाए तो जो भी सरकार मुआवजे के तौर पर रामि फिक्स करे, 5, 10, 20, 30 हजार रुपये वह उस मरने वाले के घर वालों को स्पौट पर दे दी जाए ताकि उस मरने वाले के परिवार को एकदम सहायता के तौर पर राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: मास्टर जी, आप का समय हो गया। अब आप वाइंड अप कीजिये।

मास्टर फिलिप प्रिंसिपल: इसके साथ साथ मैं स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अम्बाला में सरकार ने कुछ समय पहले लोगों से इस आ वासन के साथ 500—500 रुपये की रामि ली थी कि सरकार उनको मकान बना कर देगी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार ने अभी तक इस स्कीम के लिए जमीन भी एकवायर नहीं की है। एक मजाब अव य वहां के लोगों के साथ सरकार ने किया है कि अम्बाला छावनी में वीकर सैक अन्ज के लिए एक कालौनी ट्रिब्यून कालौनी के साथ बनी हुई है, वहां पर लोगों को कहा कि हम आप को वे हाउसिज दै देते हैं। लोगों ने कहा कि बच्चे हमारे यहां पढ़ते हैं, भाहर में रहते हैं

और हम वहां पर कैसे जा सकते हैं। इसलिए मेरी रिकवैस्ट है कि सरकार तुरन्त ही जमीन एकवायर करके उन लोगों के रहने के लिये मकान बनाये।

इससे अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब पंजाब और हरियाणा इकट्ठा था तो एक हक आफा का कानून बना हुआ था। पंजाब ने तो अब वह खत्म कर दिया है लेकिन हरियाणा में अभी भी वह कानून चल रहा है। होता क्या है कि गांवों के अंदर लोग पहले अपनी जमीन बेच देते हैं, फिर दाएं बाएं से अपने ही रि तेदारों से उस पर हक आफा करवा देते हैं। इससे वहां के डिवैल्पमैंट रुक जाती है। इसलिए मेरी सरकार से रिकवैस्ट है कि इस तरह का कानून खत्म किया जाए। इस मेरे सुझाव पर दोबारा विचार किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। इससे सरकार को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आगे मैं प्रकाशन के बारे में भी अपने सुझाव देना चाहूंगा। पिछले दिनों पता नहीं किन कारणों से वहां की तीन पंचायतों, रायपुर रानी, भाहजादपुर और बराड़ाच को तोड़ कर नगरपालिका बना दिया गया। बराड़ा पंचायत की आमदनी इनमें सबसे ज्यादा है। हमारी प्रार्थना यह है कि रायपुर रानी और भाहजादपुर दोनों की आमदनी का कोई जरिया नहीं है, इनको नगरपालिका इसलिए बनाया गया है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। वहां पर 1982 में कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए चुनाव में किसी ने काम किया था और दुर्भाग्यवा वहां कांग्रेस हार गयी। वहां की इंडीपैडेंट आदमी

जीत गया जो बाद में कांग्रेस में भारिल होकर फिर मिनिस्टर बन गया। उसने बदले की भावना से, हालांकि उन पंचायतों में उसके कोई आदमी नहीं जीते थे, फिर भी वहां पर नगरपालिकाएं बनवायीं। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने फैसले पर पुनः विचार करे। उन पंचायतों को पैसा भी दे क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है।

इसके साथ साथ मैं बसों के किराये की बाबत कहूंगा कि जो किराये बढ़ाये गये हैं, वे न बढ़ाए जाएं क्योंकि इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। एम०एल०एज० तो बसों में फ्री आते हैं और मंत्रीगण अपनी कारों में आ जाते हैं। इसलिये आम आदमियों की तकलीफ को देखते हुए सरकार अपने निर्णय पर दोबारा विचार करे।

इससे आगे मैं बिजली के बारे में कहूंगा कि सरकार ने 2 पैसे डोमैस्टिक, 3 पैसे कमर्शियल और 4 पैसे उद्योग पर प्रति यूनिट के हिसाब से जो रेट बढ़ाया है, उस पर भी सरकार दोबारा विचार करे। उद्योगों के ऊपर चाहे और ज्यादा लगा दिया जाए लेकिन डोमैस्टिक और कमर्शियल पर बिल्कुल छूट दे दी जाए। यह आम आदमियों का खून चूसने वाली बात है। इन भाबों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं। जय हिन्द!

श्री भले राम (बड़ौदा—अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, जो वर्ष 1985-86 का बजट पे 1 किया है मैं उसका समर्थन

करते हुए यह कहना चाहूंगा कि अच्छे बजट की कसौटी यही होती है कि प्रदे 1 में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों को इससे फायदा पहुंचे। जिस प्रकार से सर्दी में सूर्य निकलता है और उसकी किरणें सबको अच्छी लगती है, उसी तरह से यह बजट है। चाहे कोई किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, विद्यार्थी है या औरत है या ढाबे वाला है सबको इससे फायदा हुआ है। जब इस बजट की खबर लोगों ने रेडियो पर सुनी तो लोग खुपी से इस प्रकार नाचने लगे जिस प्रकार से समुद्र से लहरें उठती हैं। यह ठीक है कि इस बजट में कुछ टैक्स भी लगाए हैं लेकिन उन टैक्सों का भार बहुत मामूली है। हमें साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि इससे कितना फायदा हुआ है ये मामूली टैक्स हैं और लगाने बहुत जरूरी थे क्योंकि पट्रौल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं इसलिये बसों का किराया भी बढ़ाना पड़ा। इसका मेरे साथियों को भी फायदा हुआ है। यह जब विधान सभा से अपना 100 लेंगे तो इनको 20 रुपए बढ़े हुए मिलेंगे। दूसरा टैक्स गुडज ट्रांस्पोर्ट पर बढ़ा है वह भी 2000 सालाना की जगह केवल 2400 रुपए सालाना किया है जैसे इन्होंने बिजली के बारे में कहा कि उसके रेट भी बढ़ा दिए। वह वास्तव में बढ़े नहीं हैं क्योंकि एक बार सरकार ने डियूटी कम कर दी थी इसलिये इस पर टैक्स बढ़ा नहीं है बल्कि पहले जितना किया है। यानी केवल दो चार पैसे बढ़ा है। हमारे ये साथी जब बाजार में घूमने जाएंगे और अपनी बीबी को साथ लेकर जाएंगे तो इनको डेढ़ रुपए वाली चूड़ी अब एक रुपए में मिलेगी। दूसरी राहत फारमर्ज को दी है। उनको

साढे सात हौरस पावर के मोनो ब्लाक पम्पिंग सैट्स पर रियायत दी है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे सिरसा, हिसार, जीन्द तथा कुछ और भी होंगे, जहां पर साढे बारह हौरस पावर की मीन कामयाब हैं इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां पर साढे बारह हौरस पावर की मीनें कामयाब हैं और साढे सात हौरस पावर की मीनें कामयाब नहीं हैं वहां साढे बारह हौरस पावर की मीनों पर भी रियायत दी जाए। इसके साथ साथ इस बजट से कर्मचारियों को भी बहुत फायदा हुआ है। इसमें एक बात की गई है भादी के लिए कर्मचारियों को लोन अब तीन हजार से बढ़ कर पांच हजार रुपए मिल सकेगा तथा बेटी या बहिन की भादी के लिए दस हजार रुपए लोन मिलेगा। लेकिन बहिन की भादी के लिए लोन लेने में यह भार्त लगा दी है कि अगर कर्मचारी के माता पिता जिन्दा होंगे तभी यह लोन मिलेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी कर्मचारी के मां बाप मर जाएं तो क्या वह अपनी बहिन की भादी नहीं करेगा ? बहिन तो सबको प्यारी होती है इसलिये यह भार्त हटाई जानी चाहिये। इसके अलावा मैं हरिजनों के लिए भलाई की स्कीमों का जिक्र करना चाहूंगा। सरकार ने हरिजनों के लिए बहुत स्कीमें बनाई हैं। जैसे कि अब जो हमारा सैवन्थ प्लान जाएगा वह 3200 करोड़ रुपए का होगा। उसमें से 198 करोड़ रुपये स्पै ल कम्पोनेंट स्कीमों पर खर्च होगा जिसमें से 33 करोड़ रुपया इसी साल खर्च होगा। इससे लगभग 55-56 हजार फैमिलीज को फायदा होगा। इसके साथ साथ मैं सरकार से यह भी कहूंगा कि

आपने फ़ाडयूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज सैल का गठन किया है। आप उनकी कम से कम तीन महीने में एक मीटिंग जरूर रखें ताकि पता चल सके कि जो हमारी भिन्न स्कीमें हैं, उनकी इम्पलीमेंटेशन कहाँ तक होती है। अगर ऐसाव किया जाएगा तो हम इन भाइयों को भी बता सकेंगे कि सरकार यह काम करने जा रही है। इसके साथ साथ दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से 18 साल पहले की स्कीम के तहत जो हरिजन विद्यार्थी कालेज में ग्यारवी क्लास में पढ़ता है उसको किताबें खरीदने के लिए सरकार बगैर ब्याज के दो सौ रुपया कर्जा देती है। वह कर्जा 14 साल में वापिस करना पड़ता है आज की महंगाई में दो सौ रुपए बहुत कम हैं इसलिये यह राष्ट्र बढाई जानी चाहिए। दूसरे यह सुविधा ग्यारवीं क्लासा के बाद नहीं दी जाती। मैं चाहता हूं कि यह सुविधा आगे बी०ए० तक दी जानी चाहिए। स्पीकर साहब, हरिजनों के लिए और भी बहुत स्कीमें हैं जैसे इनको बगैर ब्याज के कर्जा दिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बार जिला लैवल पर वैलफैयर कमेटी की मीटिंग हुई है और कुछ जिलों में अभी होनी बाकी हैं। जहाँ अभी मीटिंग नहीं हुई है वहाँ यह पता किया जाए कि इस साल फ्री इन्स्ट्रेस्ट लोन क्यों नहीं दिया गया। पहले कुछ ऐसे आदमी होते थे जिनको एक दो हाजर रुपए मिल जाते थे और उससे वे अपना छोटा मोटा धन्धा चला लेते थे। अब की बार केवल दो ही स्कीमों को मीटिंग है। पहले वैलफैयर का बहुत काम होता था। जैसे परचेज आफ लैंड थी उसके लिए कुछ पैसा वैलफैयर महकमा देता था और कुछ

पैसा हरिजन कल्याण निगम देती थी। लेकिन अब न महकमा पैसा देता है और न निगम देती है। पहले वे उस पैसे से एक आध किल्ला जमीन खरीद लेते थे। यह बात ठीक है कि सरकार हरिजनों में सरप्लस जमीन का बंटवारा करती है लेकिन उस पैसे से वे अपने ढंग से जमीन खरीदते थे। इसलिये सरकार से प्रार्थना है कि इस बात को भी देख लिया जाए। इसके अलावा मैं इरीगे न और पावर का जिक्र करूँगा। यहां पर सभी भाईयों ने जिक्र किया था कि हरियाणा के किसान को पानी की बहुत जरूरत है। सरकार इसके लिए भी कदम उठा रही है। एक तो एस०वाई०एल० का मसला है। जब वह नहर पंजाब साइड में खुद जाएगी तो उससे पानी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा सरकार दूसरे तरीके भी अपना रही है। जैसे हमारा हरियाणा इरीगे न प्रोजैक्ट है। सन 1983 में भूय हुआ था और सन 1988 तक सरकार इसको 25 करोड़ क्यूबिक फीट लाइनिंग का काम पूरा कर लेगी। यह ठीक है कि इस काम में एक आध जगह सीमेंट वगैरह में गड्बड हुई हो। लेकिन आम तौर पर यह काम ठीक ठाक चल रहा है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि लाइनिंग करते वक्त लैवल का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए वरना सरकार का दुगना खर्चा हो जाता है। हमारे यहां मदीना गांव में एक खाल की लाइनिंग की गई थी लेकिन उसका लैवल ठीक न होने की वजह से लोगों को उसके बराबर दूसरा खाल खोदना पड़ा। इसके अलावा कई लोग जो नहर का आउट लैट या मोरी तोड़ लेते हैं उसकी वजह से वे लोग सफर करते हैं जो टेल पर होते हैं

क्योंकि वहां कई साल तक पानी नहीं पहुंचता। उसके बावजूद भी टेल पर बैठे किसान को वाटर टैक्स देना पड़ता है। इसलिये सरकार इस बारे में भी सोचे। जहां पर ऐसी भारारत जान बूझ कर की जाए, वहां सख्त कार्यवाही की जाए। चाहे कोई मेट हो या ओवरसियर हो, वे साल में एक बार ट्रांसफर होने के बाद बिल्कुल नहीं डरते क्योंकि उनको पता है कि यहां से अब दोबारा एक साल से पहले ट्रांसफर नहीं होंगी। मेरा सुझाव है कि अगर कोई ऐसा कर्मचारी भारारत करता है तो उसके लिए एस0ई0 और एक्सीयन को पावर दी जाए कि वह उनको इधर उधर बदल सके। जैसे पुलिस विभाग में किसी सिपाही को जब भी चाहो बदला जा सकता है उसी तरह से इनके केस में किया जाना चाहिए। यह नहीं कि ओवरसियर एक बार ट्रांसफर होने के बाद वहीं पर बैठा रहे। इसलिये एस0ई0 और एक्सीयन को उसकी ट्रांसफर करने की पावर दे दी जाए। अब मैं एजुकेशन का जिक्र करना चाहूंगा। हरियाणा सरकार पहली सरकार है जो एजुकेशन पर बहुत ध्यान दे रही है।

श्री अध्यक्ष: आपका ठाइम हो गया है, आप वाइंड अप करें।

श्री भले राम: मैं जल्दी ही खत्म करने की कोटि 1 करूंगा। स्पीकर साहब, मैं एजुकेशन के बारे में कह रहा था। सरकार ने पहले भी बहुत स्कूल अपग्रेड किए हैं और इस बजट में भी स्कूलों को अपग्रेड करने का प्रोवीजन किया गया है। लेकिन

हम जो एजुके अन का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं वह हम अब तक नहीं बढ़ा पाए। स्पीकर साहब, चाहे कालेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो और चाहे एजुके अन बोर्ड में हो, नकल करने का एक टरेंड बन चुका है। एग्जामों में लड़के बहुत नकल करते हैं। एग्जामों के दिनों में प्लाइंग स्कॉर्च भेज कर यह कोटि रुपयों की जाती है कि नकल न हो। नकल इसलिए भी होती है क्योंकि टीचर पर यह पाबंदी लगाई हुई है कि आपके स्कूल या कालेज का इतने परसेंट रिजल्ट आना चाहिए, यदि इससे कम रिजल्ट आया तो आपकी इन्क्रीमैंट रोक दी जाएगी। इसलिए टीचर भी लड़कों को नकल करवाने की कोटि रुपयों की जाती है। सरदार प्रताप सिंह कैरो जब ज्वांयट पंजाब में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय उन्होंने यह तरीका अपनाया था कि इतने परसेंट रिजल्ट होना चाहिए नहीं तो टीचर की इन्क्रीमैंट रोक दी जाए। इसीलिए टीचर लड़कों को नकल करवाने की कोटि रुपयों की जाती है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि एक साल के लिए टीचर के ऊपर से यह पाबंदी हटा दी जाए कि आपके स्कूल या कालेज का इतने परसेंट रिजल्ट आना चाहिए। यदि यह पाबंदी हटा दी जाए तो किसी टीचर की यह हिम्मत नहीं होगी कि वह लड़कों को नकल करवाने की कोटि रुपयों कर सके। स्पीकर साहब, इसके अलावा मेरे अपोजी अन के भाईयों ने हरियाणा एजुके अन बोर्ड के बारे में काफी बातें कही हैं। यह भी कहा कि एजुके अन बोर्ड के बारे में अखबारों में भी जिक्र आता रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा एजुके अन बोर्ड सबसे अच्छा बोर्ड है। मैं पिंडले तीन साल से

उसका चेयरमैन हूं। कहने का आप कुछ कह दें। पिछले दो सालों से बहुत कम परसैंट रिजल्ट आया है। वह इसलिए आया है क्योंकि मैंने प्लाइंग स्कॉर्ड द्वारा चैकिंग करवाइ थी और लड़कों को नकल करने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब मैं एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन बन कर गया था, उस समय बोर्ड के आफिस के लिए बिल्डिंग का नकारा भी पास नहीं हुआ था लेकिन अब मार्च या अप्रैल के महीने में दो करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार हो जाएगी। इसके अलावा स्पीकर साहब, अब मैं सड़कों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जाएं। आपका समय समाप्त हो चुका है।

श्री भले राम: स्पीकर साहब, मैं सड़कों के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता था। लेकिन समय की कमी के कारण आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं इसलिए इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि यह बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है, वैल बैलैंस्ड बजट है और यह सब के लिए है, इसलिए सभी माननीय सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिए। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री भागी राम (एलनाबाद- अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, मेरी तरफ आपकी नजर पड़ी लेकिन हाउस का समय बहुत थोड़ा रह गया है। हमारे वित्त मंत्री श्री सागर राम गुप्ता जी ने

20 मार्च को हाउस में जो बजट पे त किया है वह बहुत भारी धाटे का बजट है, इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहब, सरकार पक्ष भी मानता है कि हरियाणा एक कृशि प्रधान प्रदे त है और इसमें 80 प्रति त आबादी खेत पर निर्भर करती है। थोड़ी देर पहले बोलते हुए श्री तैयब हुसैन जी ने बताया था कि खेती के लिए केवल 11.8 परसैंट पैसा ही रखा गया है, यश्ह बहुत ही कम पैसा है। मैं भी कहता हूं कि इतने पैसे से खेती के लिये कोई भी काम नहीं होंगा, यह पैसा बहुत ही कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं खास करके सिरसा जिले के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। सिरसा जिले के किसानों का बहुत बुरा हाल हो गया है। इस साल बरसात न होने की वजह से, नहरों से पानी न मिलने की वजह से और बिजली न मिलने की वजह से सिरसा जिले के किसानों का बहुत बुरा हाल हो गया है। उनको पेट भर खाने को रोटी तक नसीब नहीं होती। उस एरिया के हरिजन और खास करके मजदूर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं स्पीकर साहब, मजदूर तो सारे हरियाणा प्रदे त के ही बेकार हो चुके हैं। स्पीकर साहब, सिरसा जिले में बारानी एरिया बहुत ज्यादा है। हरियाणा प्रदे त में सिरसा जिले में सबसे ज्यादा चने की फसल होती है। इस बार बरसात न होने के कारण चने की फसल बिल्कुल भी नहीं है। जिन किसानों ने चने का बीज बोया था वह भी उनको वापिस नहीं मिलेगा यानी उनका बीज भी पूरा वापिस नहीं होगा। मेरा सरकार से अनवेदन है कि उस एरिया की स्पै तल गिरदावरी करवाई जाए और जिस तरह से चौधरी देवी

लाल जी ने अपने समय में किसानों को ओलौं से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का मुआवजा 400 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया था उसी तरह से यहां दिया जाए। यह रिवायात चौधरी देवी लाल जी ने ही डाली थी, उन्हीं की मेहरबानी से किसानों को फसल के नुकसावन का मुआवजा मिलता है। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे भी बरसात न होने की वजह से नश्ट हुई फसलों का मुआवजा दें। चौधरी देवी लाल जी ने किसानों को फसलों के खराब होने का मुआवजा देने की जो रिवायात डाली थी उसके लिए चौधरी देवी लाल जी का नाम हमें आ अमर रहेगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बरसात न होने की वजह से जिन इलाकों में फसलों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए। (गोर)

फिल्म का राज्य मंत्री (श्री जगदीप नेहरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलना तो बजट पर चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से गलत बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे माननीय सदस्य चौधरी देवी लाल जी के बारे में कहा है कि चौधरी देवी लाल जी का नाम अमर रहेगा यह बात हम उनकी सहन नहीं करेंगे। इनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। जिन्दा आदमी के बारे में इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। (गोर)

चौधरी भाम गोर सिंह सुरजेवाला: स्पीकर साहब, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। क्या जिन्दा आदमी को श्रद्धांजलि दी जा सकती हैं? (हँसी)

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि चौधारी देवी लाल जी ने जिन किसानों की फसलें औलों की वजह से नश्ट हो गई थी उनको 400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने के लिए अनाउंस किया था। यदि चौधारी भजन लाल जी खड़े होकर यह अनाउंस कर दें कि जिन किसानों की फसलें बरसात न होने की वजह से, पानी न मिलने की वजह से और बिजली न मिलने की वजह से खराब हो गई हैं उनको 400 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा तो मैं कहता हूं कि चौधारी भजन लाल जी का नाम भी अमर होगा। यदि ये किसानों के हितैशी हैं तो आज ही अनाउंस कर दें। स्पीकर साहब, अब मैं नेहरा साहब के महकमे के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, इनके पास शिक्षा का महकमा है। सिरसा जिले में ज्यादातार प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें सरकार ने बच्चों को दलिया देने की स्कीम बना रखी है। ठेला भर कर दलिया स्कूलों में भिजवा दिया जाता है। उस दलिये से बच्चों की पढाई में बहुत भारी नुकसान होता है। मैं इस सरकार की इस नीति के खिलाफ हूं। स्पीकर साहब, जब सुबह सुबह बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते ही मास्टर कहता है कि अपने घर वापिस जाओ और गुड़, कटोरी और लकड़ी ले कर आओ। बच्चे अपने घर वापिस जाते हैं और अपने अपने घर से एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में लकड़ी लेकर वापिस स्कूल में आते हैं। इसके अलावा उस दलिये को बेचारा मास्टर ही बनाता है। जब मास्टर दलिया बनाने लग जाता है तो बच्चे अपने अपने घर पर कटोरी और लकड़ी लेने के

लिए आते हैं। जब बच्चे आने एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में लकड़ी लेकर स्कूल में वापिस पहुंचते हैं उस समय बेचारा मास्अर दलिया बना रहा होता है। बच्चे दलिया बनने की इंतजार में बैठ जाते हैं कि दलिया कब बने और हम खाएं, दलिया कब बने और हम खाएं। इस तरह से बच्चे सारा दिन उस दलिये की इंतजार में बैठ कर निकाल देते हैं और बगेर पढ़े अपने घर वापिस आ जाते हैं। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चूंकि इस सरकार ने स्कूलों में दलिया देना भुरु कर दिया है। इसलिये बहुत सारे मास्टरों ने भैंसे रखनी भुरु कर दी है। इसके अलावा फ्रिक्षा के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ फ्रिक्षा पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ ली हैं और कितने बाकी रहते हैं। यदि नेहरा साहब को आकर कोई आदमी कहता है कि मेरा लड़का पढ़ा हुआ है, उसको नौकरी लगवाओ तो नेहरा साहब कहते हैं कि फलां गांव में प्रौढ़ फ्रिक्षा का केन्द्र खोला है, वहां पर आपके लड़के को लगा दिया जाएगा। लेकिन उस गांव में वह लड़का कभी भी नहीं जाता है, वह गांव वालों को जानता तक नहीं और न ही आज तक कोई हाजरी वगैरा लगी है। लड़के 30–40 गांव वालों के नाम लिख कर ले आते हैं और उनको प्रौढ़ फ्रिक्षा केन्द्र में लगा दिया जाता है। जब ये कहते हैं कि गांव वालों के 30–40 नाम लिख कर ले आओ तो वे 80–80 साल के बूढ़ों के नाम लिख कर ले जाते हैं और उनको अप्खायंट कर देते हैं। उन को 100 या 150 रुपये महीने की तनख्वा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको प्रौढ़ फ्रिक्षा

स्कीम चलानी है तो पढ़ाने वालों को कम से कम 400 रुपए महीना तनख्वाह दें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सिरसा जिले के प्राईमरी स्कूलों में यदि सरकार दलिया सप्लाई करती है तो उसके साथ गुड या खांड दें और उस दलिये को बनाने के लिए मास्टर की डियूटी नहीं होनी चाहिए, किसी और आदमी को अप्वायंट करे। या तो दलिया बनाने के लिए गांव के सरपंच की डियूटी लगाई जाये या पंचायत की तरफ से कोई और आदमी अप्वायंट किया जाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सैंस हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी, बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठक का समय 5 मिनट बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1985–86 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री भागी राम: अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा। शिक्षा मंत्री जी अकसर हरियाणा में और खासकर सिरसा जिले में दौरे पर जाते हैं। ये स्कूलों के अन्दर पब्लिक मीटिंग करते हैं। जब स्कूलों में इनका प्रोग्राम चला जाता है तो वहाँ के स्कूलों के मास्टर गांव वालों को कहते हैं कि आप मीटिंग में चलें, नेहरा साहब आ रहे हैं। यदि आप लोग नहीं आएंगे तो नेहरा

साहब मुझे हटा देंगे, यह मेरी इज्जत का सवाल है। (हंसी) स्पीकर साहब, ये स्कूलों में पब्लिक मीटिंग करें, यह कोई सही बात नहीं है। (विधन) स्पीकर साहब, अब मैं चक्का गांव की बात कहना चाहूंगा। (विधन)

श्री अध्यक्षः आप बजट पर ही बोलें।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। आज फैक्शा का सारे हरियाणा में बुरा हाल है। मैं चक्का गांव की बात कर रहा था। इन्होंने एक बार चक्का गांव का प्रोग्राम बनाया। चक्का गांव के मास्टरों ने वहां पर इनका कोई पब्लिक मीटिंग का प्रोग्राम नहीं बनाया। उस स्कूल के अंदर हमारी एक अच्छी बहन लगी हुई थीं।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर का इन्स्टांस रिकार्ड में नहीं आएगा।

श्री जगदी ठ नेहराः आन ए प्वायंट आफ आडर, सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आडर यह है कि ये बजट पर बोलें न कि मेरे बारे में बोलें। ये सारी बातें मेरे बारे में ही कहे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्षः इनको आपसे प्यार है, इसलिए आपके बारे में कह रहे हैं। (हंसी)

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, मेरा कहना यही है कि ये स्कूलों में पब्लिक मीटिंग या जलसे आदि न किया करें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी गांव के लोग विशेष कर हमारे जिले के लोग अफसरों से मिलने के लिए आते हैं तो दफतरों में अफसर नहीं मिलते। अफसरों की भीड़ मंत्री के पास लगी रहती है। एक एक मिनिस्टर के पीछे 20–20 अफसर लगे हुए होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि रैस्ट हाउसिज में हर वक्त मंत्री बैठे रहते हैं और सारे अफसर उनके चक्कर में लगे रहते हैं। (विधन) मंत्रियों पर पाबन्दी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्षः यह बजट की कौन सी मद है।

श्री भागी रामः मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्रियों के दौरे के दिन फिक्स होने चाहिए कि इतने दिन कोई मंत्री दौरे पर रहेगा और इतने दिन मंत्री चण्डीगढ़ हैड क्वार्टर पर रहेगा। इनको ज्यादा प्रोग्राम बाहर के नहीं बनाने चाहिए। स्पीकर साहब, अब मैं ग्रिवैन्सिज कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। इस कमेटी की महीने में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मंत्री जी भी जाते हैं। मैंने ग्रिवैन्सिज कमेटी की मीटिंग में भी मंत्री जी को कहा था और यहां पर भी पिछले सै अन में कहा था कि इस ग्रिवैन्सिज कमेटी में या तो प्रत्येक पार्टी के सदस्यों को भागिल किया जाए या फिर इस ग्रिवैन्सिज कमेटी का नाम बदलकर कांग्रेस (आई) ग्रिवैन्सिज

कमेटी रखा लिया जाये। (विधन) इन्होंने इस कमेटी में अपनी ही पार्टी के लोगों को लिया हुआ है। (विधन)

श्री अध्यक्षः आपका टाईम हो गया है।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, अभी मेरा टाईम खत्म नहीं हुआ।

श्री अध्यक्षः आपका टाईम खत्म हो गया है।

अब हाउस मन्डे 25 मार्च, 1985 बाद दोपहर 2.00 बजे तक एडजर्न किया जाता है।

13.35 बजे।

(तत्प चात सदन सोमवार, 25 मार्च, 1985 को बाद दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।)